



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 320]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 4, 2015/अग्रहायण 13, 1937

No. 320]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 4, 2015/AGRAHAYANA 13, 1937

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी और संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2015

(अंतिम जाँच परिणाम)

विषय : चीन जनवादी गणराज्य मूल की अथवा वहां से निर्यातित 3 क ग्रेड और उससे निम्न स्तर की शहतूती अपरिष्कृत रेशम (मल्बरी रॉ सिल्क) (बिना - बटी हुई) के आयातों पर पाटन-रोधी संबंधी जाँच।

मामले की पृष्ठभूमि

फा. संख्या 14/17/2014-डीजीएडी.—यतः केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने घरेलू उत्पादकों/रीलरों की ओर से कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के राज्यों में उनकी एसोसिएशनों/सोसाइटियों, जिनके नाम नीचे दिए गए हैं, के माध्यम से घरेलू उद्योग की ओर से एक आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि चीन जनवादी गणराज्य मूल की अथवा वहां से निर्यातित 3 क ग्रेड और उससे निम्न स्तर की शहतूती अपरिष्कृत रेशम (मल्बरी रॉ सिल्क) (गैर-बटी हुई) (जिसे आगे “संबद्ध वस्तुएं” भी कहा गया है) का पाटन हो रहा है और अनुरोध किया है कि संबद्ध देश मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटन-रोधी शुल्क लगाने के लिए पाटन-रोधी जाँच शुरू की जाए।

(i) मेसर्स सिल्क रीलर्स एसोसिएशन, कर्नाटक

(ii) मेसर्स रामानगरम सिल्क रीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन, जिला-रामानगरम, कर्नाटक

- (iii) मेसर्ज कोलर रीलर्स इंडस्ट्रियल को-ओपरेटिव सोसाईटी लिमिटेड, जिला-कोलर, कर्नाटक
- (iv) मेसर्ज सिधलाघट्टा तालुक सिल्क रीलर्स एसोसिएशन, जिला – सिधलाघट्टा, कर्नाटक
- (v) मेसर्ज कर्नाटक राज्य मल्टीएंड सिल्क रीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन (रजिस्टर्ड), जिला-रामानगरम, कर्नाटक
- (vi) मेसर्ज क्यलनूर सिल्क रीलर्स इंडस्ट्रियल को-ओपरेटिव सोसाईटी लिमिटेड, जिला – कोलर
- (vii) मेसर्ज धर्मापुरी जिला सिल्क रीलर्स एसोसिएशन, कामाकृशियाम्माम क्रोस, धर्मापुरी ।
- (viii) मेसर्ज सिल्क रीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन, रजि. नंबर, कोकून मार्किट, हिन्दुपुर, जिला – अनाथापुर, आंध्र प्रदेश
- (ix) मेसर्ज धर्मावरम सिल्क रीलर्स वेलफेयर एसोसिएशन (रजिस्टर्ड सोसाईटी), धर्मावरम, जिला – अनाथापुर, आंध्र प्रदेश

2. और यतः प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 09 दिसंबर, 2014 को प्रकाशित अधिसूचना जारी की थी जिसमें नियमावली के नियम 5 (5) के अनुसार आरोपित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव को निर्धारित करने और पाटन-रोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने, जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, के लिए संबद्ध पाटन-रोधी जाँच की शुरुआत की है ।

क. क्रिया-विधि

3. प्राधिकारी द्वारा मौजूदा जाँच की शुरुआत करने की अधिसूचना जारी करने के बाद संबद्ध जाँच करने के संबंध में निम्नोक्त वर्णित क्रिया-विधि का अनुसरण किया गया है :

- (i) प्राधिकारी ने उपरोक्त नियमावली के नियम 5 (5) के अनुसार जाँच की कार्रवाई शुरू करने से पहले पाटन-रोधी आवेदन पत्र प्राप्त होने के बारे में संबद्ध देश के दूतावास/प्रतिनिधि को अधिसूचित किया है ।
- (ii) प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 09 दिसंबर, 2014 को प्रकाशित अधिसूचना जारी की थी जिसमें आरोपित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव को निर्धारित करने और पाटन-रोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, के लिए संबद्ध पाटन-रोधी जाँच की शुरुआत की है ।
- (iii) जांच शुरुआत करने संबंधी अधिसूचना की एक प्रति, संबद्ध देश के संबद्ध वस्तुओं के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और भारत में संबद्ध देश के दूतावास, घरेलू उत्पादकों और ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को इस अनुरोध के साथ भेजी गई थी कि वे पाटन-रोधी नियमावली के नियम 6 (2) के अनुसार अपने उत्तर और अपने विचारों को लिखित रूप से प्राधिकारी को प्रस्तुत कर दें ।
- (iv) प्राधिकारी ने उपरोक्त नियमावली के नियम 6 (3) के अनुसार आवेदक की और से प्रस्तुत किए गए आवेदन के अगोपनीय वृत्तान्त की प्रतियां, संबद्ध देश के संबद्ध वस्तुओं के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और भारत में संबद्ध देश के दूतावास/प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई थीं।
- (v) निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति, भारत में संबद्ध देश के दूतावास/प्रतिनिधि को, निर्यातकों के नामों और पतों के साथ इस अनुरोध के साथ भेजी गई थी कि वे अपने देश के

निर्यातकों/आयातकों को यह परामर्श दें कि वे प्रश्नावली के उत्तर निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राधिकारी को प्रस्तुत कर दें।

- (vi) जाँच शुरूआत करने संबंधी अधिसूचना संबद्ध देश के संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित उत्पादकों/निर्यातकों को भेजी गई थी :-
- (क) मेसर्ज झेझिआंग सिल्क इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कार्पोरेशन
 - (ख) मेसर्ज सिकुआन प्रोविंस सिल्क इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ग्रुप
 - (ग) मेसर्ज झेझिआंग बेलाई आई एंड ई कार्पोरेशन लिमिटेड
 - (घ) मेसर्ज जिआंगसू हेईन कोकून सिल्क ग्रुप कंपनी लिमिटेड
 - (ङ) मेसर्ज जिआंगसू सोहो इंटरनेशनल ग्रुप कार्पोरेशन
 - (च) मेसर्ज चाईना नेशनल सिल्क इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कार्पोरेशन
 - (छ) मेसर्ज साईकुआन ड्राईड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
 - (ज) मेसर्ज साईकुआन बुशेंग एंटाई सिल्क्स कंपनी
 - (झ) मेसर्ज नांजिआंग टेक्सटाईल्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कार्पोरेशन लिमिटेड
 - (ण) मेसर्ज बाझोंग योंगआई कोकून सिल्क कंपनी लिमिटेड
 - (ट) मेसर्ज झेझिआंग टसकश्मीरी कंपनी लिमिटेड
 - (ठ) मेसर्ज लिआंनिंग सिल्क इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कार्पोरेशन
 - (ड) मेसर्ज चेंगडु टिआनऊ डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड
- (vii) संबद्ध देश के किसी उत्पादक/निर्यातक ने प्रश्नावली के उत्तर नहीं प्रस्तुत किए हैं।
- (viii) चीन के रेशम उद्योग की ओर से चाईना चेम्बर आफ कामर्स फॉर इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ टेक्सटाईल्स द्वारा निवेदन किए गए हैं।
- (ix) पाटन-रोधी नियामवली के नियम 6 (4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में संबद्ध वस्तुओं के ज्ञात निम्नलिखित आयातकों और/अथवा उपभोक्ताओं को आयातक की प्रश्नावलियां भेजी गई थीं :-
- (क) मेसर्ज आशा सिल्क एक्सपोर्ट्स
 - (ख) मेसर्ज इम्पोर्टर्स एंड एक्सपोर्टर्स
 - (ग) मेसर्ज भारती सिल्क्स
 - (घ) मेसर्ज चामुंडी टेक्सटाईल्स (सिल्क मिल्स) लिमिटेड
 - (ङ) मेसर्ज चैत्रा प्रिंट्स

- (च) मेसर्ज दत्तारैया सिल्क एक्सपोर्टस्
 (छ) मेसर्ज एथनिक एक्सपोर्ट्स
 (ज) मेसर्ज गजानन्य सिल्क फैब्रिक्स
 (झ) मेसर्ज हार्मोनी सिल्क्स प्राईवेट लिमिटेड
 (ण) मेसर्ज जे. जे. एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
 (ट) मेसर्ज हिमतसिंगका सीडे लिमिटेड
 (ठ) मेसर्ज स्वान सिल्क लिमिटेड
 (ड) मेसर्ज पार्थी प्रिंट्स
 (ढ) मेसर्ज शाह सिल्क एंड फैब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड
 (रा) मेसर्ज इलाई इंक
 (त) मेसर्ज रामा टेक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड
 (थ) मेसर्ज रिलटिका सिल्क एंड साडीज
 (द) मेसर्ज त्रिवेणी साडीज
 (ध) मेसर्ज बी. आर. एक्सपोर्टर्स (इंडिया)
 (न) मेसर्ज चेतन एक्सपोर्टस्
 (प) मेसर्ज क्लासिक क्रिएशनस्
 (फ) मेसर्ज आलोक एक्सपोर्टस्
 (ब) मेसर्ज जयके इंटरनेशनल
 (भ) मेसर्ज शालीमार एक्सपोर्टस्
 (म) मेसर्ज अमृता एक्सपोर्टस्
 (x) किसी भी आयातक ने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है।
 (xi) प्राधिकारी को प्रयोक्ताओं/आयातकों की ओर से निम्नलिखित एसोसिएशनों से उत्तर प्राप्त हुए हैं :-
 (क) आल इंडिया सिल्क वीवर्स एसोसिएशन
 (ख) दि मैसूर पावर लूम सिल्क मेन्युफैक्चरर्स को-ओपरेटिव सोसाईटी लिमिटेड
 (ग) कर्नाटक स्टेट नेकारा (वीवर्स) सांघा लिमिटेड
 (घ) सिल्क ट्रेड एसोसिएशन (रजिस्टर्ड), वाराणसी
 (ङ) दि साउदर्न गुजरात चेम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री
 (च) आलोक एक्सपोर्टस्
 (छ) बनारसी वस्त्र उद्योग एसोसिएशन

- (ज) प्योर सिल्क वीवर्स एसोसिएशन
- (झ) रेशम तागा एसोसिएशन, वाराणसी
- (ण) फेडरेशन आफ इंडिया आर्ट सिल्क वीविंग इंडस्ट्री
- (xii) निम्नलिखित हितबद्ध पक्षकारों ने मौखिक सुनवाई के अनुसरण में अपने लिखित निवेदन प्रस्तुत किए हैं :-
- (क) केन्द्रीय रेशम बोर्ड (जिसे आगे “घरेलू उद्योग” कहा गया है)
- (ख) चाईना चेम्बर आफ कामर्स फॉर इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ टेक्स्टाईल्स (जिसे आगे “सीसीसीटी” कहा गया है)
- (ग) साईनो इम्पोर्टस् एंड एक्सपोर्टस् प्राईवेट लिमिटेड
- (xiii) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों और प्रमाणों के अगोपनीय वृत्तान्त, सार्वजनिक फाईल के रूप में उपलब्ध कराए हैं जो कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा जाँच करने के लिए खुले रखे हुए हैं।
- (xiv) उत्पादन की लागत और निर्माण लागत तथा घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं की बिक्रियों के आधार पर गैर-क्षति कीमत का परिकलन किया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करने के लिए पाटन मार्जिन से कम पाटन-रोधी शुल्क लगाना पर्याप्त होगा।
- (xv) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की गोपनीय के दावों की उनकी पर्याप्तता के संदर्भ में जाँच की गई है। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी उचित था, गोपनीयता के ऐसे दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय समझा है और उसे अन्य पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है, वहां गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले हितबद्ध पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का अगोपनीय वृत्तान्त भी प्रस्तुत करें।
- (xvi) याचिकादाता द्वारा प्रदत्त सूचना की स्थल पर जांच, घरेलू उद्योग में शामिल यूनिटों के परिसरों में की गई थी। आवश्यक आशोधन सहित जाँच की गई सूचना पर जहां कहीं भी लागू होता है, मौजूदा निर्णय के प्रयोजनार्थ विश्वास किया गया है।
- (xvii) पाटन-रोधी नियमावली के नियम 6 (6) के अनुसार प्राधिकारी ने सभी ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को 24 सितंबर, 2015 को आयोजित आम सुनवाई में मौखिक रूप से सूचना प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया था। हितबद्ध पक्षकारों को प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना/किए गए विचारों पर पुनरुत्तर पेश करने का अवसर प्रदान किया गया था। प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए विचारों पर उपयुक्त रूप से विचार किया है।
- (xviii) मौजूदा जांच के प्रयोजनार्थ जाँच की अवधि 1 अप्रैल, 2013 से 30 मार्च, 2014 (जांच अवधि) तक है। तथापि, प्रवृत्तियों की जाँच करने के लिए क्षति का विश्लेषण करने के परिप्रेक्ष्य में अप्रैल, 2010-मार्च, 2011, अप्रैल, 2011 - मार्च, 2012, अप्रैल, 2012 - मार्च, 2013 और जाँच की अवधि (पीओआई) भी शामिल है।
- (xix) जाँच की अवधि के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों, दिए गए तर्कों और सूचना तथा उसके बाद किए गए प्रकटन जिसे साक्ष्य द्वारा समर्थन किया गया है और जिसे मौजूदा जाँच के लिए

प्रासंगिक माना गया है, पर प्राधिकारी द्वारा इस प्रकटन दस्तावेज में उपयुक्त रूप से विचार किया गया है।

(xx) अप्रैल, 2010 – मार्च, 2011, अप्रैल, 2011 - मार्च, 2012, अप्रैल, 2012 - मार्च, 2013 और जाँच की अवधि (पीओआई) के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों के कारोबार-वार आंकड़े, वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकीय महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से प्राप्त हो गए हैं तथा मौजूदा निर्णायक समीक्षा जाँच में विश्लेषण करने के लिए उन पर पर विश्वास किया गया है।

(xxi) इस अंतिम निर्णय में किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा ***सूचना को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत किया गया है तथा नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा उस पर विचार किया गया है।

(xxii) इस जाँच के लिए अपनाई गई औसत विनिमय दर, 1 अमरीकी डालर = 60.87 रूपए है।

ख. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु का कार्य क्षेत्र

4. मौजूदा जाँच में विचाराधीन उत्पाद, चीन जनवादी गणराज्य मूल की अथवा वहां से निर्यातित 3 क ग्रेड और उससे निम्न स्तर की शहतूती अपरिष्कृत रेशम (बिना-बटी हुई) है। ऐसी रेशम को बन्दी की स्थिति में (रेशम कृषि) पाले गए शहतूती रेशम कीड़ों *बम्बई मोरी* के लार्वों के कोयों से प्राप्त किया जाता है।

5. विचाराधीन उत्पाद को सीमी शुल्क के अध्याय-40 में “रेशम” शीर्ष के अंतर्गत और उससे आगे 5002 200 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, संबद्ध वस्तुओं के आयात, सीमा शुल्क के विभिन्न शीर्षों जैसे कि 5002 010, 5002 00 20, 5002 00 30 आदि के अंतर्गत भी किए गए हैं। ऐसा वर्गीकरण केवल निर्देशात्मक है और यह किसी भी तरह से मौजूदा जाँच के कार्य-क्षेत्र पर बाध्यकारी नहीं है।

निर्यातकों/आयातकों/प्रयोक्ताओं/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन

6. सभी पहलुओं में सभी ग्रेडों के भारतीय मानक, रॉ सिल्क टेस्टिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ दि आईएसए 1968 नामक नियम पुस्तिका में उल्लिखित मानक से काफी निम्नतर हैं, जिस के आधार पर सीमा शुल्क सामान्यतया उनके पुनः परीक्षण पर विश्वास करता है। चीन जनवादी गणराज्य वर्ष 1979 से अपरिष्कृत रेशम संबंधी अनिवार्य राष्ट्रीय मानकों का क्रियान्वयन कर रहा है और इसका वर्तमान वृत्तान्त जीवी/टी 1797-2008 है। जब भारतीय मानकों से तुलना की जाती है तो उपरोक्त 3 क ग्रेड की अपरिष्कृत रेशम के चीन के सभी मानक, भारतीय 3 क ग्रेड से काफी उच्चतर होते हैं। इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी कृपया इस आशय का विशिष्ट स्पष्टीकरण जारी करें कि 3 क ग्रेड से उच्च स्तर की रेशम, मौजूदा जाँच के कार्य-क्षेत्र से बाहर है।

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन

7. संबद्ध वस्तुएं जिनका पाटन भारत में किया जा रहा है, घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित की जा रही वस्तुओं के समान हैं। उनके बीच तकनीकी विनिर्देशनों, कार्यों की दृष्टि से अथवा पाटित आयातों के अंत प्रयोक्ताओं और घरेलू रूप से निर्मित संबद्ध वस्तुओं के रूप में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। ये दोनों वस्तुएं तकनीकी और वाणिज्यिक रूप में एक दूसरे के प्रतिस्थापन योग्य हैं और इसलिए पाटन-रोधी नियमावली के अंतर्गत इन्हें “समान वस्तुएं” ही माना जाना चाहिए।

8. घरेलू उद्योग ने यह निवेदन किया है कि पाटन-रोधी विधिशास्त्र में ऐसी स्थिति सिद्ध की गई है कि गुणवत्ता कोई मायने नहीं रखती है तथा यह विचाराधीन उत्पाद से किसी वस्तु को बाहर रखने की मांग का आधार नहीं हो सकती है, जब तक कि आयातित उत्पाद “समान वस्तु” होते हैं, तब तक उन्हें उत्पाद के कार्यक्षेत्र में शामिल किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग ने यह भी निवेदन किया है कि जाँच की शुरुआत की अधिसूचना में “विचाराधीन उत्पाद” की परिभाषा को सीसीसीटी द्वारा किसी भी अधिकारिक न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई और इसलिए किसी उपयुक्त मंच के समक्ष इसका समाधान करने के अनुरोध के बिना, निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसका समाधान नहीं किया जा सकता है, विशेषकर उस स्थिति में

जब कि पाटन-रोधी विधिशास्त्र के अनुसार उत्पाद के कार्य-क्षेत्र में परिवर्तन करने के लिए गुणवत्ता कारक नहीं है।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

9. मौजूदा जाँच में विचाराधीन उत्पाद, चीन जनवादी गणराज्य मूल की अथवा वहां से निर्यातित 3 क ग्रेड और उससे निम्न स्तर की शहतूती अपरिष्कृत रेशम (बिना-बटी हुई) है।

10. रेशम को बन्दी की स्थिति में (रेशमकृषि) पाले गए शहतूती रेशम कीड़ों *बम्बई मोरी* के लार्वों के कोयों से प्राप्त किया जाता है। रेशम एक प्रोटीन फाईबर है जिसे मुख्यतया फिब्रोईन से संघटित किया जाता है और इसे कोओं के रूप में लार्वों के कीट से बनाया किया जाता है। रेशम की झिलमिलाती दिखावट रेशम के फाईबर की त्रिकोणीय चमकीले स्वरूप के कारण होती है, जो कि रेशम के कपड़े को विभिन्न कोणों से पड़ने वाले प्रकाश से चमकदार बनाता है। इस प्रकार उसमें विभिन्न रंग चमकते लगते हैं। रेशम अन्य कीटों से भी निर्मित होती है लेकिन वस्त्र बनाने के लिए सामान्यतया केवल केटरपिलर्स कीड़े की रेशम का ही प्रयोग किया जाता है।

11. समान वस्तु के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (घ) में उल्लिखित व्यवस्था निम्नानुसार है :-

“समान वस्तु” से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटने के कारण जाँच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जो कि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरूप नहीं है, परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;

12. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए तथा प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक पाए गए निवेदनों की जाँच और समाधान इस प्रकार से किया गया है :-

(1) याचिकादाता ने यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तुओं में किसी भी प्रकार का ज्ञात अंतर नहीं है। घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित संबद्ध वस्तुएं और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तुएं अपनी तकनीकी विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रोद्योगिकी, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशनों, वितरण और बाजार और वस्तुओं के वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। आवेदक और प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत उत्पाद और आयात के आंकड़ों की जाँच करने पर ऐसा पता चलता है कि घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तुओं के बीच कोई अंतर नहीं है। उनके विनिर्माण प्रक्रिया और प्रतिस्थापन क्षमता में समानता को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी की यह धारणा है कि “विचाराधीन उत्पाद” को परिभाषित करने के प्रयोजन से इन दोनों वस्तुओं को एक समान उत्पाद ही माने जाने की आवश्यकता है।

(2) हितबद्ध पक्षकारों के इस निवेदन के संबंध में कि इस आशय का विशिष्ट स्पष्टीकरण जारी किया जाए कि 3 क ग्रेड से उच्च स्तर की रेशम को मौजूदा जाँच के कार्य-क्षेत्र से बाहर रखा जाए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि 3 क ग्रेड से उच्च स्तर की शहतूती अपरिष्कृत रेशम (बिना-बटी हुई), मौजूदा जाँच के उत्पाद के अधिकार-क्षेत्र से पहले से ही बाहर है, जैसा कि जाँच शुरू करने संबंधी अधिसूचना से स्वतः स्पष्ट होता है। ।

ग. घरेलू उद्योग का कार्य-क्षेत्र और उसका दर्जा

उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन

13. केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सीएसबी) एक सांविधिक निकाय है जिसकी स्थापना, केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 के अंतर्गत वस्त्र मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण अधीन की गई है। ऐस तर्क दिया गया है कि संबद्ध नियमावली के अनुसार व्यापारिक निवारक जाँच में घरेलू उद्योग के प्रतिनिधि के रूप में केन्द्रीय रेशम बोर्ड को कोई प्राधिकार नहीं दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त पाटन-रोधी नियमावली के नियम 2 (ग) के अंतर्गत उल्लिखित “हितबद्ध पक्षकार” की परिभाषा के अनुसार वह भारत सरकार का प्रतिनिधित्व भी

नहीं कर सकता है, क्योंकि आयातक देश की सरकार के एक हितबद्ध पक्षकार होने के रूप में परिकल्पना नहीं की गई है।

14. याचिका के साथ आवेदक एसोसिएशन और उसके सदस्यों के नामों और पतों को दर्शाने वाली एक उपयुक्त सूची दी जानी चाहिए। अनेक एसोसिएशनों ने अपने सदस्यों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सूचना दिए बिना ही अपने सदस्यों की केवल हस्त लिखित सूची प्रदान की है

15. हितबद्ध पक्षकारों ने निवेदन किया है कि याचिका में ऐसा उल्लेख किया गया है कि भारत में कुल घरेलू उत्पादन में आवेदक का अंशदान 57 प्रतिशत है। तथापि, आवेदक द्वारा स्वयं प्रस्तुत की गई वार्षिक रिपोर्टों में निर्दिष्ट आंकड़े भिन्न चित्र दर्शाते हैं।

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन

16. घरेलू उद्योग ने यह निवेदन किया है कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड भारत में एक स्वतंत्र निकाय है जिसकी स्थापना पृथक विधान अर्थात् केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम 1948 द्वारा देश में रेशम के क्रियाकलाप को नियंत्रित, विकसित और संवर्धित करने के प्रयोजन से की गई है। यह देश में एक नोडल निकाय है जो कि न केवल रेशम क्षेत्र के विकास और उन्नति के लिए ही उत्तरदायी है बल्कि यह रेशम क्षेत्र से संबंधित आवश्यक आंकड़ों का संकलन और रिकार्ड भी रखता है। इसलिए रेशम उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने आवेदन पत्र को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में समन्वयन किया है। केन्द्रीय रेशम बोर्ड का यह दायित्व है कि रेशम उद्योग के विकास को बढ़ाने के लिए ऐसे उपाय किए जाएं जिन्हें वह उचित समझता है। इस परिप्रेक्ष्य में अपने दावे की संपुष्टि के लिए घरेलू उद्योग ने केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 के संबद्ध पृष्ठों को भी प्रस्तुत किया है।

17. यह भी निवेदन किया गया है कि उपरोक्त नियमावली का नियम 5 (1) घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। नियमावली के अंतर्गत ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि किस प्राधिकारी को घरेलू उद्योग के लिए और उसकी ओर से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की शक्ति प्राप्त है। सीसीसीटी द्वारा प्रस्तावित तरीके से उक्त नियम को पढ़ने के फलस्वरूप नियम 5 (1) का विवेचन करने से केवल गैर-सरकारी संगठन ही परिभाषित घरेलू उद्योग के प्राधिकृत एजेंटों के रूप में माने जाएंगे। ऐसा विवेचन सांविधिक विवेचन के निर्धारित सिद्धांतों के विपरीत होता है। घरेलू उद्योग ने भी यह निवेदन किया है कि माननीय प्राधिकारी द्वारा रेशम उद्योग से संबंधित विभिन्न विगत जाँच में केन्द्रीय रेशम बोर्ड को घरेलू उद्योग माना गया है।

18. घरेलू उद्योग ने यह निवेदन किया है कि एक एसोसिएशन के सदस्य, किसी अन्य एसोसिएशन के सदस्य नहीं हैं और इन एसोसिएशनों के सभी सदस्य संबद्ध उत्पाद के विनिर्माता/उत्पादक हैं। घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी का ध्यान सीसीसीटी (जो कि एक हितबद्ध पक्षकार है) के इस तथ्य की ओर आकर्षित किया है कि एक ओर तो वह इस आधार पर एसोसिएशन के सदस्यों की सूची की मांग कर रहा है कि कुछ एसोसिएशनों ने अपने सदस्यों की हस्तलिखित सूची प्रस्तुत की है। तथापि, दूसरी ओर सार्वजनिक सुनवाई के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध के बावजूद भी उसने अपने सदस्यों की सूची उनके उत्पादन के व्यौरों के साथ प्रस्तुत नहीं की है जिससे कि नियम 2 (ग) के अनुसार उसके इस जाँच में एक हितबद्ध पक्षकार होने की पात्रता की संपुष्टि हो सके। घरेलू उद्योग ने यह भी निवेदन किया है कि आवेदक घरेलू उत्पादकों ने न ही संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के निर्यातकों अथवा आयातकों से संबंधित हैं तथा उनके आवश्यक घोषणा पत्र आवेदन पत्र के साथ अनुबंध 7 के रूप में पहले से ही संलग्न हैं। इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग ने यह भी निवेदन किया है कि हितबद्ध पक्षकारों ने कार्यवाही को पटरी से उतारने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा देशी भाषाओं में कुछेक सदस्यों के नाम प्रदान करने के मुद्दे को भी उठाया था। इस परिप्रेक्ष्य में घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया था कि सीसीसीटी ने दिनांक 06 अक्टूबर, 2015 के अपने लिखित निवेदनों के साथ प्रदर्श-3 संलग्न किया है। यह प्रदर्श-3 शहतूती अपरिष्कृत रेशम के चीन के मानकों के परिप्रेक्ष्य में है, जो कि

स्थानीय भाषा अर्थात् चीनी भाषा में है। सीसीसीटी ने उसका अंग्रेजी रूपान्तरण प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार यहां तक कुछ दस्तावेजों के मुद्दे का संबंध है, सीसीसीटी दोहरे मापदंड अपना रहा है।

19. वार्षिक रिपोर्टों में सूचित उत्पादन में अन्य उत्पाद भी शामिल हैं जो कि मौजूदा जाँच के अधिकार-क्षेत्र से बाहर हैं। इसलिए वार्षिक रिपोर्टों में आवेदक द्वारा प्रदत्त आंकड़ों को इस जाँच में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि वार्षिक रिपोर्ट में जिस उत्पाद के उत्पादन के आंकड़े निर्दिष्ट किए गए हैं उसका कार्य-क्षेत्र, मौजूदा जाँच के उत्पाद के कार्य-क्षेत्र की तुलना में काफी व्यापक है।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

20. पाटन रोधी नियमावली के नियम 2 (ख) में घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

“घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।

21. मौजूदा जाँच में घरेलू उद्योग की ओर से केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। जैसा कि आवेदक ने दावा किया है, वह भारत में एक स्वतंत्र निकाय है जिसकी स्थापना एक पृथक् विधान अर्थात् केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 द्वारा देश में रेशम के क्रियाकलाप को नियंत्रित, विकसित और संवर्धित करने के प्रयोजन से की गई है। यह देश में एक नोडल निकाय है जो कि न केवल रेशम क्षेत्र के विकास और उन्नति के लिए ही उत्तरदायी है बल्कि यह रेशम क्षेत्र से संबंधित आवश्यक आंकड़ों का संकलन और रिकार्ड भी रखता है। इसलिए रेशम उद्योग के विकास को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने आवेदन पत्र को प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में समन्वयन किया है। केन्द्रीय रेशम बोर्ड का यह दायित्व है कि रेशम उद्योग के विकास को बढ़ाने के लिए ऐसे उपाय किए जाएं जिन्हें वह उचित समझता है।

22. आवेदक ने यह भी निवेदन किया है कि उपरोक्त नियमावली का नियम 5 (1) घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति देता है

23. पाटन-रोधी नियमावली का नियम 5 (1) में उल्लिखित प्रावधान निम्नानुसार है :-

“5. जाँच शुरू करना - (1) जैसा कि उप-नियम (4) में व्यवस्था की गई है, उसको छोड़ कर, निर्दिष्ट प्राधिकारी केवल घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से प्रस्तुत किए गए लिखित आवेदन पत्र के प्राप्त होने पर ही किसी भी आरोपित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने के लिए जाँच की शुरुआत करेगा।”

24. प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटन-रोधी नियमावली का नियम 5 (1) ऐसे प्राधिकारियों को विनिश्चित नहीं करता है जो घरेलू उद्योग की ओर से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नियम 5 (1) आयातक देश की सरकार को भी घरेलू उद्योग की ओर से एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से प्रतिबंधित नहीं करता है। इसलिए प्राधिकारी की धारणा है कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड घरेलू उद्योग की ओर से आवेदन प्रस्तुत करने का पूर्णतया योग्य पात्र और सक्षम है।

25. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए इस मुद्दे के संबंध में कि घरेलू उद्योग ने अपनी याचिका के पृष्ठ संख्या 7 में यह उल्लेख किया है कि भारत में कुल घरेलू उत्पादन में उसका अंशदान 57 प्रतिशत है। जबकि आवेदक द्वारा स्वयं प्रस्तुत की गई वार्षिक रिपोर्ट में निर्दिष्ट आंकड़े भिन्न चित्र दर्शाते हैं, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वार्षिक रिपोर्ट में विभिन्न उत्पादों को शामिल किया जाता है जबकि इस जाँच के उत्पाद का कार्य-क्षेत्र 3 क ग्रेड और उससे निम्न स्तर की शहतूती अपरिष्कृत रेशम (बिना-बटी हुई) तक ही प्रतिबंधित है।

घ. गोपनीयता

उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं :-

26. गोपनीयता के संबंध में उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक पाए गए निवेदन निम्नानुसार हैं :-

- (1) याचिका में अत्यधिक गोपनीयता है। आवेदक ने भाग 6 लागत, मूल्यहास, ब्याज लागत आदि जैसी विभिन्न सूचनाओं की गोपनीयता का दावा किया है।
- (2) नियम 2 (ख) में ऐसा अपेक्षित है कि भागीदार घरेलू उत्पादक संबद्ध उत्पाद के संबंधित अपने आंकड़े प्रस्तुत करें। आवेदक के पाए ऐसे सभी विशिष्ट उत्पादकों से संबंधित सूचना नहीं है और इसलिए वह उनकी ओर से याचिका प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं हो सकता है।
- (3) आवेदक ने प्रत्येक घरेलू उत्पादक द्वारा निर्मित उत्पाद की वास्तविक मात्राओं के संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है।

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन

27. गोपनीयता के मुद्दों के संबंध में घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि घरेलू उद्योग ने पाटन-रोधी नियमावली के अनुसार और निर्धारित प्रपत्रों में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। साथ ही उसने यह भी निवेदन किया है कि घरेलू उद्योग ने कानूनी प्रावधानों और प्राधिकारी द्वारा अनुसरण किए जा रहे दिशा निर्देशों के अनुसार अपनी व्यावसायिक संवेदनशील सूचना की गोपनीयता का दावा किया है।

28. प्रमाणों के साथ विशिष्ट पृथक उत्पादकों की सूचना प्रदान करने के मुद्दे के बारे में घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि मौजूदा मामले में घरेलू उद्योग अत्यधिक बिखरा हुआ और फैला हुआ है, जिसमें हजारों यूनिट शामिल हैं। ये यूनिट कुटीर आधारित उद्योग हैं और मुख्यतया पृथक परिवारों द्वारा चलाए जाते हैं। तदनुसार ये यूनिट विभिन्न लेखाओं को बनाए रखने और विभिन्न अन्य यूनिटों की तरह अनुपालन की जा रही लेखाकरण प्रक्रियाओं का अनुपालन करने की स्थिति में नहीं हैं। इसके अतिरिक्त यह भी निवेदन किया गया है कि घरेलू उद्योग के सीमित और लघु प्रचालनों को ध्यान में रखते हुए पृथक विशिष्ट यूनिटों के लिए यह संभव नहीं है कि वे क्षति के विभिन्न प्राचलों के संबंध में निर्धारित प्रपत्र और तरीके से सूचना प्रस्तुत करें जैसा कि संगठित क्षेत्र में किसी उद्योग द्वारा सामान्यतया प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग के उत्पादन का परिकलन विभिन्न एसोसिएशनों, जिनके सदस्य संबद्ध उत्पाद के उत्पादन/विनिर्माण के कार्य में लगे हुए हैं, द्वारा प्रदत्त की गई सूचना के आधार पर किया गया है। उत्पादन के लिए विभिन्न एसोसिएशनों से प्राप्त ऐसी सूचना को आवेदन पत्र के साथ अनुबंध-6 के रूप में संलग्न किया गया है। इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी को प्रमाणों के साथ प्रमाणित लागत और कीमत संबंधी सूचना भी प्रस्तुत की है।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

29. गोपनीयता के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए तथा प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक पाए गए निवेदनों की जाँच की गई है। गोपनीयता के संबंध में पाटन-रोधी नियमावली के नियम 7 में उल्लिखित प्रावधान निम्नानुसार है :-

“8. गोपनीय सूचनाएं – (1) नियम 7 के उप-नियम (1), (2), (3) और (7) और नियम 14 के उप-नियम (2), नियम 17 के उप-नियम (4) और नियम 19 के उप-नियम (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जाँच की प्रक्रिया में नियम 6 के उप-नियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।

(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है, तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।

30. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीयता के आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की जांच, गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई है। प्राधिकारी ने संतुष्ट होने पर जहां कहीं भी आवश्यक पाया है, वहां ऐसे दावे को स्वीकार किया है और ऐसी गोपनीय सूचना को अन्य हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष प्रकट नहीं किया है। जहां कहीं भी संभव हुआ है गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों को निर्देश दिए गए थे कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के अगोपनीय वृत्तान्त प्रस्तुत करें। प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाणों के अगोपनीय वृत्तान्त को सार्वजनिक फाईल के रूप में उपलब्ध करा दिया है।

31. प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए इस निवेदन के संबंध में कि आवेदक को विशेष पृथक उत्पादकों की सूचना उपलब्ध करानी चाहिए थी, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मौजूदा मामले में घरेलू उद्योग अत्यधिक बिखरा हुआ और फैला हुआ है, जिसमें हजारों यूनिट शामिल हैं। ये यूनिट कुटीर आधारित उद्योग हैं और मुख्यतया पृथक परिवारों द्वारा चलाए जाते हैं। तदनुसार ये यूनिट विभिन्न लेखाओं को बनाए रखने और विभिन्न अन्य यूनिटों की तरह अनुपालन की जा रही लेखाकरण प्रक्रियाओं का अनुपालन करने की स्थिति में नहीं हैं। तथापि, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के दौरे के दौरान जाँच करने पर उसके आंकड़ों की वैधता को सत्यापित किया है।

32. प्राधिकारी की यह भी धारणा है कि अधिनियम और नियमावली में ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिससे यह अधिदेश हो कि क्षति आदि से संबंधित सूचना उद्यमी स्तर पर ही हो। नियमावली में विशेष रूप से “उद्योग की स्थिति” की जाँच करने का प्रावधान निहित है। इस परिप्रेक्ष्य में प्राधिकारी ने “चीन जनवादी गणराज्य मूल के अथवा वहां से निर्यातित 20-100 ग्राम प्रति मीटर के रेशम फैब्रिक” के मामले में दिनांक 05 दिसंबर, के अंतिम परिणाम संख्या एफ 15/24/2010-डीजीएडी का हवाला दिया है, जिसमें ऐसा स्पष्ट निर्णय किया गया है कि “ऐसी कोई विशिष्ट विधि नहीं है जिससे उद्योग के लिए संकलित सूचना को स्वीकार करना निषेध हो। इस प्रकार केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा ऐसी जाँच के किसी भी प्रयोजनार्थ प्रस्तुत की गई सूचना को स्वीकार करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसलिए प्राधिकारी का यह निर्णय है कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी भी आंकड़े अथवा सूचना को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है।”

ड. विविध निवेदन

उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन निम्नानुसार हैं :-

33. उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक पाए गए निवेदन निम्नानुसार हैं :-

(1) सीसीसीटी ने निवेदन किया है कि वह वास्तव में चीन जनवादी गणराज्य और विश्व में सबसे बड़ी वस्त्र और अपैरल की व्यापारिक एसोसिएशन है। उनके अनेक क्रियाशील विभाग और शाखाएं हैं जो कि अन्य उत्पादों के साथ-साथ वस्त्र, रेशम, परिधानों के व्यापार का कार्य करती हैं। उपरोक्त निवेदनों के आलोक में सीसीसीटी पाटन-रोधी नियमावली के नियम 2 (ग) के अंतर्गत एक योग्यता

प्राप्त हितबद्ध पक्षकार है । इसके अतिरिक्त यह निवेदन किया जाता है कि यह कुछ विलंब से निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास एक पक्षकार के रूप में पंजीकृत है ।

- (2) हितबद्ध पक्षकारों को आयात के आंकड़े की सॉफ्ट प्रति अधिमानतः माईक्रोसॉफ्ट एक्सल में प्रदान कराई जानी चाहिए ताकि सुबोधगम्य तरीके से उसकी जाँच की जा सके । हितबद्ध पक्षकारों को उस आधार पर सूचना की आवश्यकता होती है जिस पर निर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा घरेलू उद्योग ने डीजीसीआईएंड एस अथवा अन्य प्राईवेट एजेंसियों से अपरिष्कृत आंकड़ों की मांग की है । उसे डीजीसीआई एंडएस/ प्राईवेट एजेंसियों द्वारा प्रदत्त किए गए अपरिष्कृत कारोबार-वार आंकड़ों, अपरिष्कृत कारोबार-वार आंकड़ों के आशोध के लिए अपनाई गई क्रिया-विधि और आशोधित आंकड़ों और उसके सारांश की आवश्यकता होती है ।
- (3) निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए प्रपत्र में संबद्ध वस्तुओं के बारे में सूचना का प्रकटन करना अपेक्षित होता है जिनमें उनका आकार, कोटि, श्रेणी, किस्म, रैंज, मॉडल आदि शामिल है । आवेदक ऐसी सूचना को भारत में उत्पादकों से एकत्रित कर सकता था और उसे अपनी याचिका में प्रस्तुत कर सकता था ।
- (4) हितबद्ध पक्षकारों ने प्राधिकारी से अनुरोध किया था कि वे आवेदक को निर्देश दें कि ऐसी मानक नियम पुस्तिका की एक प्रति अपनी याचिका के साथ प्रस्तुत करे ।
- (5) चीन जनवादी गणराज्य से 3-क ग्रेड की अपरिष्कृत रेशम के आयात, घरेलू उद्योग पर कोई प्रभाव नहीं डाल रहे हैं । ऐसे आयात मुख्यतया भारतीय बाजार की ऐसी मांग की संपूर्ति कर रहे हैं, जो कि घरेलू उद्योग नहीं कर सकता है, क्योंकि वह पहले से ही अपनी अनुकूलतम क्षमता का उपयोग कर रहा है । विद्युत करघा उद्योग को चीन जनवादी गणराज्य से वाईवोल्टाईन श्रेणी की अपरिष्कृत रेशम का आयात करना होता है, क्योंकि भारतीय घरेलू उत्पादकों के पास वाईवोल्टाईन श्रेणी की अपरिष्कृत रेशम उपलब्ध नहीं है । प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वह पहले न केवल 2-क और 3-क ग्रेड के लिए ही बल्कि क्रमशः 2-क और 3-क ग्रेड के अंतर्गत उप-ग्रेड की 2 क की वाईवोल्टाईन श्रेणी की अपरिष्कृत रेशम की भी मद-वार-मद की तुलना करने के लिए उनके विभिन्न ग्रेडों का पृथक् करें और उसके बाद ही जाँच की प्रक्रिया के दौरान पाटन और क्षति का निर्धारण करें ।
- (6) पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-3 के पैरा (4) के उप-पैरा (3) में निर्दिष्ट प्राधिकारी से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि वे गैर-क्षति कीमत का निर्धारण करने के लिए विगत तीन वर्षों और जाँच की अवधि के दौरान श्रेष्ठतम क्षमता उपयोग पर विचार करें ।
- (7) घरेलू उद्योग द्वारा संयुक्त राज्य अमरीकी डालर के लिए भारतीय रूपयों में अपनाई गई औसत विनिमय दर 60.98 रूपए है । तथापि, संयुक्त राज्य अमरीकी डालर के लिए प्रचलित विनिमय दर 65.39 रूपए है । ऐसा भी अनुमान है कि रूपया एक बार फिर से उभरेगा नहीं और इसके मूल्य में और गिरावट आएगी । इसका तात्पर्य यह है कि इस समय भारत में हो रहे आयातों की कीमत, जाच अवधि के दौरान प्रचलित कीमत की तुलना में काफी अधिक हैं । इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री होने के स्तर की सही स्थिति प्राप्त करने के लिए प्रचलित विनिमय दर पर विचार किया जाए ।
- (8) आवेदक का यह आरोप है कि चीन जनवादी गणराज्य से संबद्ध उत्पाद पाटित किए जा रहे हैं और भारत सहित विश्व भर में विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा चीन जनवादी गणराज्य को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है । यह भी आरोप लगाया गया है कि मौजूदा मामले में चीन के उत्पादकों/निर्यातकों को, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि चीन में रेशम का उत्पादन और व्यापार, सर्वसम्मति से ऐसा स्वीकार किया गया है कि राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त नहीं है, बाजार-अर्थव्यवस्था दर्जा स्वीकृत नहीं किया जा सकता है । इस प्रयोजनार्थ आवेदक ने अपने दावे के समर्थन में चीन

जनवादी गणराज्य के अभिगमन संबंधी न्याचार और चाईना कोकून एंड सिल्क एक्सचेंज संस्था के अंतर्नियम प्रस्तुत किए हैं। कोआ देश में एक प्रकार का अल्प स्रोत है और इसका उत्पादन पर्याप्त रूप से बिखरे, अल्प-सुसज्जित और वित्तीय रूप से असुरक्षित औद्योगिक क्षेत्र द्वारा किया जाता है। चीन जनवादी गणराज्य में कोओं के कृषकों को जो कि अभी भी अलाभ प्राप्त स्थिति में हैं, के उत्तर जीवन के मूल अधिकार की रक्षा करने के लिए ही उसकी सरकार को ऐसे उपाय करने हैं जिनसे कोओं की कीमत में संतुलन बनाए रखा जा सके जो कि चीन जनवादी गणराज्य के अलाभप्रद क्षेत्रों का आर्थिक विकास करने और समाज की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण है।

- (9) निर्दिष्ट प्राधिकारी को अधिदेश है कि वह पहले तृतीय देश की बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा संरचित मूल्य अथवा भारत सहित ऐसे तृतीय देशों से कीमत के प्रमुख विकल्पों का प्रयोग करने के बाद ही इस मामले में चीन जनवादी गणराज्य जैसे गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से निर्यात के मामलों में सामान्य मूल्य का निर्धारण करें। ऐसे दोनों विकल्पों को प्रयुक्त करने के बाद ही निर्दिष्ट प्राधिकारी सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए किसी अन्य उचित आधार को प्रयुक्त कर सकते हैं, जिसमें भारत में अदा की गई कीमतें अथवा देय कीमतें शामिल हैं, जिसके लिए उचित समायोजन करना होगा।
- (10) आवेदक ने जिस आधार पर कुछ लागतों को अपनाया है, उसका कोई भी सकारात्मक प्रमाण अथवा आधार प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार यह प्रमाण की परिशुद्धता और पर्याप्तता के लिए विश्व व्यापार संगठन के एडीए के अनुच्छेद 5.3 को उल्लंघन है।
- (11) 6 से 8 लाख तक की संख्या में ऐसे विद्युत करघा बुनकर हैं जिनका जीवन खतरे में पड़ा हुआ है। यदि शुल्क लगाया जाता है तो 6 से 8 लाख तक की संख्या में ऐसे विद्युत करघा बुनकरों को भुखमरी और मौत का सामना करना पड़ेगा। घरेलू उद्योग ने उनको कभी भी अपेक्षित मात्रा में और कोटि की अपरिष्कृत रेशम की आपूर्ति नहीं की है। घरेलू उद्योग मुख्यतया हथकरघा बुनकरों को ही इसकी आपूर्ति कर रहा है और विद्युत करघा बुनकर कभी भी उसके बाजार नहीं रहे हैं। इस मामले में यदि शुल्क लगाए जाते हैं तो कम से कम विद्युत करघों के प्रयोजनार्थ प्रयुक्त होने वाली आयातित वस्तुओं को उनसे मुक्त रखा जाए। इस प्रकार की अंत-प्रयोक्ता छूट से घरेलू उद्योग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि वह अपनी अपरिष्कृत रेशम को अपने विद्यमान बाजार अर्थात् हथकरघा बुनकरों को बेच सकता है।
- (12) बुनकर एसोसिएशनों ने जो कि आयातक और प्रयोक्ता हैं, निवेदन किया है कि वे इस तथ्य से आश्चर्यचकित हैं कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड ने दिल्ली में पाटन-रोधी प्राधिकारियों को चीन जनवादी गणराज्य से आयातित 3 क अपरिष्कृत रेशम यार्न पर पाटन-रोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है। यदि इसे क्रियान्वित कर दिया जाता है तो इससे रेशम बुनकर उद्योग पर महाविपत्ति आ पड़ेगी।
- (13) घरेलू उत्पादकों को 10 वर्ष से भी अधिक की अवधि से पूर्व पाटन-रोधी जाँच परिणामों के अनुसरण में संबद्ध उत्पाद पर पहले से ही पर्याप्त संरक्षण मिला हुआ है। इसके अतिरिक्त वित्त मंत्रालय ने दिनांक 1 मार्च, 2013 की अधिसूना संख्या 12/2013-सीमा शुल्क द्वारा अपरिष्कृत रेशम पर सीमा शुल्क 5% से बढ़ा कर 15 % कर दिया है। ऐसे पर्याप्त संरक्षण के बावजूद भी घरेलू उद्योग, मौजूदा मामले में आंकड़ों के समर्थन के बिना कपटपूर्ण ढंग से ऐसा दावा कर रहा है कि उसे चीन जनवादी गणराज्य से आरोपित पाटित आयातों से आर्थिक क्षति हो रही है।
- (14) रेशम बुनकरों को कोटि के फैब्रिकों बनाने के लिए अत्यधिक मात्रा में समान कोटि की 2-क ग्रेड और उससे ऊपर ग्रेड की रेशम की जरूरत होती है जिसका देश में अत्यधिक मात्रा में उत्पादन नहीं होता है।
- (15) बुनकरों ने निवेदन किया है कि भारत चीन से बाईवोल्टाईन रेशम यार्न का आयात करता है जो कि भारतीय उद्योग, अनेक दशकों से सुस्थिर प्रयास करने के बावजूद भी संतोषजनक ढंग की गुणवत्ता युक्त अथवा मात्रा में देश में ही उत्पादन करने में सक्षम नहीं हो पाया है।

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए निवेदन

34. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक पाए गए विविध निवेदन निम्नानुसार हैं :-

- (1) घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि सीसीसीटी निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष तभी प्रतिनिधित्व कर सकता है जब वह निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष इस तथ्य को प्रमाणित कर दे कि वह नियम 2 (2) के अनुसार एक योग्यता प्राप्त हितबद्ध पक्षकार है। यह प्रमाणित किए जाने पर कि वह एक योग्यता प्राप्त हितबद्ध पक्षकार है, वह जाँच की प्रक्रिया में सहभागी बन सकता है। ऐसा कोई विवाद नहीं है कि सीसीसीटी उत्पादक, निर्यातक अथवा आयातक की श्रेणी में नहीं आता है। इसलिए वह नियम 2 (ग) के अंतर्गत एक व्यवसायिक एसोसिएशन का दावा कर सकता है। उपरोक्त तथ्य से ऐसा देखा जा सकता है कि केवल ऐसी एसोसिएशनों को ही "हितबद्ध पक्षकार" माना जा सकता है जिसके अधिकतर सदस्य "ऐसी वस्तु" के उत्पादक, निर्यातक अथवा आयातक हों। यह नोट करना अत्यावश्यक है कि ऐसी वस्तु अर्थात् "शहतूती अपरिष्कृत रेशम" के लिए सीसीसीटी के कुल सदस्यता के परिप्रेक्ष्य में बहुमत की जाँच लागू होती है। तथापि, सीसीसीटी ने अपने किसी भी पत्र द्वारा यह प्रकट नहीं किया है कि वह एक व्यवसायिक एसोसिएशन है और उसके अधिकतर सदस्य, विचाराधीन उत्पाद के उत्पादक, निर्यातक अथवा आयातक हैं तथा यहां तक कि उसने अपने सदस्यों की सूची भी, उनके संबंधित क्रियाकलापों को दर्शाने वाले विवरण सहित निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत नहीं की है, जिससे कि नियम 2 (ग) के अनुसार उसके संबंध में किसी भी प्रकार का निर्धारण किया जा सके। इसके विपरीत सीसीसीटी ने दिनांक 07 अप्रैल, 2015 के अपने निवेदन पत्र में यह उल्लेख किया है कि वह वस्त्र व्यापार के कारोबार में लगा हुआ है। ऐसे प्रमाणीकरण प्रस्तुत किए बिना सीसीसीटी को नियमावली के नियम 2 (ग) के अनुसार एक हितबद्ध पक्षकार नहीं माना जा सकता है। इसलिए घरेलू उद्योग ने यह प्रार्थना की है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी सीसीसीटी को एक हितबद्ध पक्षकार मानने से मना करें और उसके परिणामस्वरूप सीसीसीटी द्वारा किए गए सभी निवेदनों को अस्वीकार कर दें।
- (2) प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत करने और साथ ही घरेलू उद्योग के आवेदन पत्र पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए जाँच शुरूआत संबंधी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 18 जनवरी, 2015 तक 40 दिनों का समय दिया था। तथापि, निर्धारित विशिष्ट समय सीमा के बावजूद भी सीसीसीटी ने अपने निवेदन देय तारीख के काफी देर बाद अर्थात् 7 अप्रैल, 2015 और 3 जून, 2015 को प्रस्तुत किए थे। इसके अतिरिक्त सीसीसीटी ने प्राधिकारी को ऐसे बिलंब को माफ करने का कोई अनुरोध नहीं किया था। इसलिए घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि वे घरेलू उद्योग के आवेदन पत्र पर सीसीसीटी द्वारा अत्यधिक विलंब से प्रस्तुत किए गए निवेदनों को स्वीकार नहीं करें।
- (3) इसके अतिरिक्त प्राधिकारी द्वारा विशेष समय सीमा निर्धारित करने के बावजूद अखिल भारतीय रेशम बुनकर परिसंघ और साईनो इम्पोर्ट्स एंड एक्स्पॉर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड ने प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर घरेलू उद्योग के आवेदन पत्र पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की है। इसके अतिरिक्त घरेलू उद्योग ने यह भी निवेदन किया है कि साईनो इम्पोर्ट्स एंड एक्स्पॉर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड ने अनिवार्य प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं करके मौजूदा जाँच में उपयुक्त निर्णय देने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए वस्तुगत आवश्यक सूचना को भी छिपाए रखा है। इसको ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग का निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे भारतीय रेशम बुनकर परिसंघ और साईनो इम्पोर्ट्स एंड एक्स्पॉर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड द्वारा किए गए निवेदनों को स्वीकार नहीं करें।
- (4) घरेलू उद्योग ने अपने आवेदन पत्र के साथ संलग्न अनुबंध-1 में कारोबार-वार आयात के आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। आयात के आंकड़ों को भी उसी प्रपत्र में प्रस्तुत किया गया है, जिस प्रपत्र में प्राधिकारी ने

- अन्य मामलों में आयात आंकड़ों को स्वीकार किया है तथा संबद्ध वस्तुओं के आंकड़ों के छंटाई, आयात के आंकड़ों के प्रत्येक कारोबार में दिए गए विवरण के आधार पर की गई है ।
- (5) घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तुओं की सभी किस्मों, ग्रेड आदि का उत्पादन/विनिर्माण करने के कार्य में लगा हुआ है जैसे कि ग्रेड 2 क, ग्रेड 3 क, बाईवोल्टाईन किस्म, मल्टीवोल्टाईन किस्म की शहतूती अपरिष्कृत रेशम आदि। घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी को उनके घरेलू उद्योग के संघटकों के जाँच दौरे के दौरान इस तथ्य को प्रमाणित भी कर दिया है।
- (6) मानक नियम पुस्तिका की प्रति देने के लिए सीसीसीटी के अनुरोध के संबंध में घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि सीसीसीटी द्वारा किया गया ऐसा अनुरोध वास्तव में किसी तरह से ऐसा मुद्दा पैदा करना है जिससे कि जाँच प्रक्रिया में अडचन उत्पन्न हो। उनके द्वारा किए गए निवेदनों से ऐसा पता चलता है कि वे न केवल आईएसए मानकों और इस व्यापार में अन्य संबंधित अंतराष्ट्रीय मानदंडों से अवगत हैं बल्कि उन्होंने निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष उनकी प्रतियां भी प्रस्तुत की है।
- (7) ग्रेड-वार पाटन और क्षति के मार्जिन के लिए हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध के संबंध में यह निवेदन किया गया है कि संबद्ध देश के किसी भी निर्यातक ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए हितबद्ध पक्षकारों का असहयोग, वास्तव में जाँच में अडचन पैदा करना है, यहां तक कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्राधिकारी को निर्यातक-वार निर्यात के व्यौरे भी उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। किसी भी हितबद्ध पक्षकार से ऐसी वस्तुगत सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में ऐसे अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता है। किसी भी स्थिति में विभिन्न ग्रेड, वाणिज्यिक रूप से एक दूसरे के प्रतिस्थापन योग्य हैं, क्योंकि 3 क तक के विभिन्न ग्रेडों के बीच कीमत में कोई विशेष अंतर नहीं होता है।
- (8) हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि एनआईपी का परिकलन अनुबंध-3 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार किया जाए, घरेलू उद्योग ने यह निवेदन किया है कि इस जाँच में घरेलू उद्योग की प्रकृति बहुत विशिष्ट किस्म की है। घरेलू उद्योग अत्यधिक बिखरा हुआ और फैला हुआ है, जिसमें हजारों छोटे यूनिट शामिल हैं। ये यूनिट कुटीर आधारित उद्योग हैं और मुख्यतया पृथक विशिष्ट परिवारों द्वारा चलाए जाते हैं। इसलिए घरेलू उद्योग ने एनआईपी का परिकलन करने के लिए श्रेष्ठ उपलब्ध सूचना प्रस्तुत करने के सभी संभव प्रयास किए हैं। इसके अतिरिक्त उसने यह भी निवेदन किया है कि मौजूदा विधि में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे ऐसा अधिदेश हो कि जाँच केवल उन्हीं के लिए की जा सकती है जो विशेष तरीके से रिकार्ड को बना कर रखते हैं। अधिनियम और नियमावली में भी छोटे किसानों, कारीगरों, शिल्पियों आदि को पाटन-रोधी विधि को लागू करके उनको संरक्षण देने अथवा उपचारी कार्रवाई करने के अधिकार-क्षेत्र से बाहर नहीं रखा गया है।
- (9) घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि सामान्य मूल्य और गैर-क्षति कीमत आदि का परिकलन करने के लिए जाँच अवधि की विनिमय दर को अपनाया जाना एक मानक पद्धति है, जिसका अनुसरण, पाटन-रोधी प्राधिकारियों द्वारा ठोस आर्थिक और यौक्तिक लेखाकरण और युक्तिसंगत आधार पर किया गया है। प्राधिकारियों द्वारा सभी मामलों में इसी पद्धति का अनुसरण सुसंगत तरीके से किया गया है। इसके अतिरिक्त हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क भावी विनिमय दर के बारे में परिकल्पना पर आधारित है और इसलिए यह गुण-दोष के बिना है। प्राधिकारी की मानक पद्धति को ध्यान में रखते हुए ही घरेलू उद्योग ने भी निर्यात कीमत, सामान्य मूल्य आदि का परिकलन करने के प्रयोजनार्थ इसी पद्धति को अपनाया है। इसके अतिरिक्त हितबद्ध पक्षकारों ने उक्त उपागम में किसी भी प्रकार की कानूनी अथवा युक्तिसंगत कमी का कोई उल्लेख नहीं किया है।
- (10) यह निवेदन किया गया है कि भारत सहित विश्व भर में विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा चीन जनवादी गणराज्य को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है। इसलिए चीन के लिए सामान्य

मूल्य का निर्धारण पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में निर्धारित क्रिया-विधि के अनुसार किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह भी निवेदन किया गया है कि मौजूदा मामले में चीन के उत्पादकों/निर्यातकों को, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि चीन में रेशम का उत्पादन और व्यापार, सर्वसम्मति से ऐसा स्वीकार किया गया है कि राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त नहीं है, बाजार-अर्थव्यवस्था का दर्जा स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। अपने दावे को प्रमाणित करने के लिए आवेदन पत्र के साथ अनुबंध-8 के रूप में चीन जनवादी गणराज्य के अभिगमन संबंधी न्याचार की एक प्रति संलग्न की गई है, जिसमें चीन ने रेशम के कोयों की कीमतों पर राज्य के नियंत्रण को स्वीकार किया है।

- (11) घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि उसने लागत और कीमत के आंकड़ों के समर्थन में सभी प्रमाण प्राधिकारी को प्रस्तुत कर दिए हैं। तथापि, घरेलू उद्योग ने गोपनीयता के नियमों के अनुसार ऐसी सूचना/दस्तावेजों की गोपनीयता का दावा किया है।
- (12) घरेलू उद्योग ने निवेदन किया है कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिया गया यह तर्क गलत है कि घरेलू उद्योग मुख्यतया हथकरघा बुनकरों ही आपूर्ति कर रहा है। यह कहना तथ्यों को अयथार्थ रूप से प्रस्तुत करना है कि चीन की रेशम का प्रयोग, केवल विद्युतकरघों में ही किया जाता है, जबकि भारतीय रेशम का उपयोग हथकरघों में किया जाता है। हितबद्ध पक्षकारों ने कोई प्रमाण प्रस्तुत किए बिना ऐसा खोखला दावा किया है। देश के अधिकतर विद्युतकरघा समूहों में भारतीय रेशम का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार आयातित और घरेलू दोनों अपरिष्कृत रेशम वस्तुतः समान उत्पाद हैं, जिन्हें एक दूसरे के बदले प्रयुक्त किया जाता है, जो कि उसकी कीमत पर निर्भर करता है। हितबद्ध पक्षकारों के इस निवेदन के संबंध में कि यदि शुल्क लगाए जाते हैं तो 6 से 8 लाख तक की संख्या में विद्युतकरघा बुनकरों को भुखमरी और मौत का सामना करना पड़ेगा, यह निवेदन किया जाता है कि पाटन-रोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापारिक पद्धतियों से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करना है, जिससे कि भारतीय बाजार में खुली और प्रतिस्पर्द्धात्मक स्थिति बहाल हो सकेगी, जो कि देश के सामान्य हित में होगी। इसका उद्देश्य मुख्यतया घरेलू उद्योग के लिए समानान्तर व्यापारिक कार्य क्षेत्र सृजित करना है ताकि बाजार में अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रतिस्पर्द्धा की जा सके। इसलिए पाटन-रोधी शुल्क लगाने से उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।
- (13) यह निवेदन किया गया है कि पाटन-रोधी शुल्क लगाने का आधार, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के निर्यातक का कीमत निर्धारण करने का पक्षपातपूर्ण रवैया है। तथ्य यह है कि प्राधिकारी ने 10 वर्ष से भी अधिक अवधि से दिया गया संरक्षण यह सुनिश्चित नहीं करता है कि संबद्ध देश के निर्यातक ने अपने पक्षपातपूर्ण रवैये को बदला है। वास्तव में संबद्ध देश से पाटित कीमतों के निम्न मूल्य के आधार पर अत्यधिक पाटन और क्षति मार्जिन का निर्धारण किया गया है, जो यह सिद्ध करता है कि प्राधिकारी के 10 वर्षों से भी अधिक समय से दिए जा रहे संरक्षण के बावजूद भी संबद्ध देश के निर्यातकों ने अपने पक्षपातपूर्ण रवैये को नहीं बदला है। सीमा शुल्क को 5 % से बढ़ा कर 15 % तक करने के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्क के संबंध में यह निवेदन किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों ने इस तथ्य को रिकार्ड में नहीं लाया है कि प्रारंभ में सीमा शुल्क 30 % था जिसे घटा कर 5 % कर दिया गया था और बाद में उसे बढ़ा कर 15 % कर दिया गया था।
- (14) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिया गया यह तर्क गलत है कि 2 क ग्रेड और उससे उच्च स्तर की अपरिष्कृत रेशम, देश में अत्यधिक मात्रा में निर्मित नहीं की जाती है। हितबद्ध पक्षकारों ने इस संबंध में अनुमान मात्र लगाया है और उनका दावा खोखला है। अपने दावे को सिद्ध करने के लिए कि घरेलू उद्योग 2 क ग्रेड और उससे उच्च स्तर की अपरिष्कृत रेशम का उत्पादन करता है, उसने प्राधिकारी को

संबंधित उत्पाद की गुणवत्ता/ग्रेड को प्रमाणित करने वाले सिल्क कंडीशनिंग एंड टेस्टिंग हाउस (एससीटीएच) द्वारा जारी किए गए जाँच परिमाणपत्रों की प्रतियां प्रस्तुत की हैं।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

35. हितबद्ध पक्षकारों और घरेलू उद्योग द्वारा उठाए गए और प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक पाए गए विभिन्न मुद्दों की जाँच की गई है जो कि इस प्रकार है :-

- (1) सामान्य मूल्य का परिकलन करने के लिए प्रयुक्त की विनिमय दर के संबंध में कुछ हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्क के संबंध में प्राधिकारी ने केवल जाँच अवधि के दौरान प्रचलित विनिमय दर पर ही विचार किया है, जो कि प्राधिकारी द्वारा अपनाई जा रही सुसंगत पद्धति के अनुसार है।
- (2) हितबद्ध पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि यदि शुल्क लगाए जाते हैं तो 6 से 8 लाख तक की संख्या में विद्युतकरघा बुनकरों को भुखमरी और मौत का सामना करना पड़ेगा, प्राधिकारी का यह मानना है कि पाटन-रोधी शुल्क लगाने से किसी भी तरह से उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी। पाटन-रोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापारिक पद्धतियों से घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति दूर करके बाजार में अधिक प्रभावशाली ढंग से प्रतिस्पर्धा करने के लिए घरेलू उद्योग के लिए समानान्तर व्यापारिक कार्य क्षेत्र सृजित करना है, जो कि देश के सामान्य हित में है। इसके अतिरिक्त कम शुल्क लगाने से यह सुनिश्चित करना है कि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करके उसे पर्याप्त संरक्षण प्राप्त हो।
- (3) हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए इस मुद्दे के संबंध में कि घरेलू उद्योग को पहले से ही पर्याप्त संरक्षण मिला हुआ है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को पाटन-रोधी संरक्षण इसलिए दिया गया है ताकि घरेलू उद्योग को संबद्ध देश के निर्यातकों के कीमत संबंधी पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण होने वाली क्षति से बचाया जा सके। विगत वर्षों में घरेलू उद्योग को दिया गया संरक्षण, इस निर्णय के संबंध में कोई प्रासंगिक कारक नहीं है कि मौजूदा स्थिति में क्या पाटन-रोधी शुल्क लगाया जाए अथवा नहीं।
- (4) हितबद्ध पक्षकारों ने यह मुद्दा उठाया है कि रेशम बुनकरों को गुणवत्ता युक्त फैब्रिक बनाने के लिए समान गुणवत्ता युक्त 2 क और उससे उच्चतर ग्रेड की रेशम की अत्यधिक मात्रा की जरूरत होती है, जिसका देश में अत्यधिक मात्रा में उत्पादन नहीं होता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों ने अपने इस निवेदन के समर्थन में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है। किसी भी स्थिति में प्राधिकारी ने सत्यापन के समय यह नोट किया है कि घरेलू उत्पादक वास्तव में 2 क और उससे उच्चतर ग्रेड की रेशम का पर्याप्त मात्रा में उत्पादन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त नई स्वचालित मशीनों में भी अत्यधिक निवेश किया गया है जो कि समान गुणवत्ता युक्त 2 क और उससे उच्चतर ग्रेड की बाईवोल्टाईन और मल्टीवोल्टाईन किस्मों की रेशम का विनिर्माण सुनिश्चित करेगा।
- (5) एनआईपी का निर्धारण करने के लिए अनुबंध-3 में उल्लिखित प्रावधान को लागू करने और कुछ लागतों का निर्धारण करने के लिए अपनाए गए आधार के बारे में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दे के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनुबंध-3 में उल्लिखित प्रावधान को इस तरीके नहीं पढ़ा जा सकता है जिससे कि बेहतर सूचना प्राप्त करने के लिए प्राधिकारी की शक्तियां कम हो जाएं। इस जाँच में यह सुमान्य है कि घरेलू उद्योग का स्वरूप विशिष्ट संगठित घरेलू उद्योग से बहुत अनूठा और अनोखा है। घरेलू उद्योग अत्यधिक बिखरा हुआ और फैला हुआ है, जिसमें हजारों छोटे यूनिट शामिल हैं। ये यूनिट कुटीर आधारित उद्योग हैं और मुख्यतया पृथक विशिष्ट परिवारों द्वारा चलाए जाते हैं। यह मानते हुए कि उद्यम-विशिष्ट सूचना के आधार पर केवल एनआईपी का परिकलन करने के लिए विधि में ऐसा कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है, प्राधिकारी ने फिर भी संघटक

यूनिटों के जाँच दौरे के दौरान उनके आवेदन पत्र में घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त सूचना की परिशुद्धता को अभिपुष्ट किया है। ऐसी अभिपुष्ट सूचना ही एनआईपी का परिकलन का आधार बनी है।

- (6) हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि ग्रेड-वार पाटन और क्षति मार्जिन का परिकलन किया जाए, यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश के निर्यातकों ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है और उन्होंने पाटन मार्जिन का परिकलन करने के लिए अपेक्षित जरूरी वस्तुगत सूचना भी प्रस्तुत नहीं की है। ऐसी प्रासंगिक सूचना उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ग्रेड-वार पाटन और क्षति मार्जिन का परिकलन करना संभव नहीं है।
- (7) आयात के आंकड़ों के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि डीजीसीआईएंड एस के आयात आंकड़ों के अगोपनीय वृत्तान्त सार्वजनिक फाईल में उपलब्ध करा दिए गए थे।

क्रिया-विधि तथा पाटन और पाटन मार्जिन का निर्धारण

छ. सामान्य मूल्य

36. धारा 9 क (1) (ग) के अधीन, किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य का तात्पर्य है :

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप नियम (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:
- (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से किया गया हो; अथवा
- (ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उदगम वाले देश में उक्त वस्तु की उत्पादन लागत।

37. चीन जनवादी गणराज्य के किसी भी निर्यातक ने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी निर्यातक ने एनएमईटी प्रश्नावली के उत्तर भी प्रस्तुत नहीं किए हैं।

38. विश्व भर में विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा चीन को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना जाता है और हाल ही में भारत में भी चीन को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना गया है। इसलिए चीन के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण, पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध - 1 के पैरा 7 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार किया जाना अपेक्षित है। सुलभ संदर्भ के लिए पैरा 7 के प्रावधानों को नीचे उद्धृत किया जाता है :-

“गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत अथवा संरचित मूल्य अथवा किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव न हो, अथवा अन्य किसी समुचित आधार पर किया जाएगा जिसमें भारत में समान वस्तु के लिए वास्तविक रूप से संदत्त अथवा भुगतान योग्य कीमत, जिनमें यदि आवश्यक हो तो लाभ की समुचित गुंजाइश भी शामिल की जाएगी निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे समुचित देश का चयन उचित तरीके से किया जाएगा जिसमें संबंधित देश के विकास के स्तर तथा प्रश्नगत उत्पाद का ध्यान रखा जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना का भी ध्यान रखा जाएगा। जहां उचित हो, उचित समय सीमा के भीतर किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में की गई जाँच पर भी ध्यान दिया जाएगा। जाँच से संबंधित पक्षों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के

उपर्युक्त प्रकार से चयन के बारे में बिना किसी विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित अवधि प्रदान की जाएगी।”

39. चूंकि चीन को एक गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना जाता है, इसलिए नियमावली में ऐसा प्रावधान है कि चीन के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण, बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश के बाजार में संचरित मूल्य घरेलू बिक्री कीमतों अथवा बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश के बाजार में संचरित मूल्य अथवा भारत सहित किसी अन्य देश को तृतीय देश की निर्यात कीमत के आधार पर किया जाए। तथापि, यदि उपरोक्त विकल्पों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारण नहीं किया जा सकता है तो उस स्थिति में निर्दिष्ट प्राधिकारी सामान्य मूल्य का निर्धारण किसी भी अन्य उचित आधार पर कर सकते हैं जिनमें समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तविक रूप से अदा की गई कीमत अथवा देय कीमत शामिल है, जिसमें उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए ऐसी कीमत विधिवत् समायोजित हो।

40. किसी भी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तृतीय देश में संबद्ध वस्तुओं के लिए किसी भी कीमत और लागत के ब्यौरे उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में तथा इस तथ्य को नोट किए जाने पर कि किसी भी निर्यातक/ उत्पादक ने प्रश्नावली के उत्तर प्रस्तुत नहीं किए हैं और उन्होंने पाटन-रोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैराग्राफ 8 (3) के अनुसार बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे का दावा किया है, मौजूदा मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास इसके सिवाए और कोई विकल्प नहीं बचता है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण, किसी भी अन्य उचित आधार पर किया जाए जिसमें समान उत्पाद के लिए भारत में वास्तविक रूप से अदा की गई कीमत अथवा देय कीमत शामिल है, जिसमें उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए ऐसी कीमत विधिवत् समायोजित हो। तथापि, प्राधिकारी ने मौजूदा जाँच के लिए चाईना कोकून एंड सिल्क एक्सचेंज द्वारा यथा प्रकाशित कोओं की अंतर्राष्ट्रीय दरों को अपनाया है।

41. घरेलू उद्योग के द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना तथा प्राधिकारी के पास उपलब्ध अन्य सूचना के आधार पर सम्बद्ध वस्तुओं का सामान्य मूल्य चीन गणराज्य के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए नीचे दिए अनुसार निर्मित किए गए हैं :-

| | | |
|---|--------------------------|-----------------------------------|
| चीन गणराज्य के सभी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य | 3619 रु. प्रति कि. ग्रा. | 59.45 अमरीकी डालर प्रति कि. ग्रा. |
|---|--------------------------|-----------------------------------|

चीन के उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए निर्यात मूल्य

42. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि संबद्ध देश के किसी भी निर्यातक ने प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर नहीं किया है/ इसलिए, प्राधिकारी ने महासागर माल भाड़े, समुद्री बीमा, कमीशन, बैंक प्रभार, पत्तन रखरखाव व्यय और अंतर्देशीय माल भाड़ा खर्चों को समायोजित करने के लिए पाटन-रोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध सर्वोत्तम तथ्यों के आधार पर संबद्ध देश के सभी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत निर्धारित की है। इस प्रकार निर्धारित प्रस्तावित निवल निर्यात कीमत नीचे दिए अनुसार है :-

| | | |
|--|--------------------------|-----------------------------------|
| चीन गणराज्य के सभी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत | 2669 रु. प्रति कि. ग्रा. | 43.85 अमरीकी डालर प्रति कि. ग्रा. |
|--|--------------------------|-----------------------------------|

पाटन मार्जिन

43. सम्बद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य पर विचार करते हुए प्राधिकारी ने चीन गणराज्य के निर्यातकों के लिए सम्बद्ध वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन निर्धारित करने का प्रस्ताव किया है, जो नीचे अनुसार है :-

| विवरण | सामान्य मूल्य | पुराना फैक्टरी मूल्य | पाटन मार्जिन | पाटन मार्जिन (%) | पाटन मार्जिन (रैंज %) |
|------------------------|---------------|----------------------|--------------|------------------|-----------------------|
| रु./ कि. ग्रा. | 3619 | 2669 | 949 | 35.57 | 30-40 |
| अमरीकी डालर/ कि. ग्रा. | 59.45 | 43.85 | 15.60 | 35.57 | 30-40 |

यह देखा गया है कि सम्बद्ध वस्तुओं के लिए पाटन मार्जिन ही-मिनिमस से अधिक और पर्याप्त है।

छ. क्षति – निर्धारण

उत्पादकों/ निर्यातकों/ आयातकों/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा किए गए निवेदन

44. उत्पादकों/ निर्यातकों/ आयातकों/ अन्य हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा किए गए क्षति संबंधित निवेदन निम्नलिखित हैं :-

- i. अद्यतन याचिका से यह देखा जा सकता है कि संबद्ध वस्तुओं के आयातों में न तो किसी प्रकार की सुनिश्चित और न ही संगत वृद्धि हुई है। सम्बद्ध उत्पाद के आयातों में पिछले 4 वर्षों में कभी सार्थक नहीं थे, जिससे भारतीय बाजार को नियंत्रित किया जा सके। भारतीय घरेलू उत्पादकों का उत्पादन, बिक्री और क्षमता उपयोग बढ़ा है। सम्बद्ध निर्यातों और घरेलू उद्योग की लाभप्रदता के बीच कोई संबंध नहीं है। अतः यह कहना सही नहीं है कि भारतीय घरेलू उत्पादकों को उक्त जाँच अवधि के दौरान क्षति हुई।
- ii. चीन गणराज्य के निर्यातों का पहुंच मूल्य में पूरी क्षति विश्लेषण अवधि के दौरान समनुरूप से वृद्धि हुई। इसी अवधि के दौरान पहुंच मूल्य में वृद्धि के अनुरूप घरेलू विक्रय मूल्य में भी पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में सकारात्मक रूप से कम दाम होने की कोई संभावना नहीं है। चीन से आयातित सिल्क को गुणवत्ता के आधार पर 3250 रु. से 3400 रु. मूल्य पर स्वदेश में बेचा जा रहा है। स्वदेशी सिल्क के मूल्य से जब इस दर की तुलना की गई तो यह प्रति किलोग्राम 1000 रु. अधिक है। अतः कोई पाटन नहीं है।
- iii. औसत कीमतें, अन्य देशों की आयात कीमतें क्षति अवधि के दौरान चीन गणराज्य की आयात कीमतों से काफी कम थी। इसलिए अन्य देशों के कीमत प्रभाव की उपेक्षा नहीं की जा सकती है।
- iv. घरेलू उद्योग के द्वारा बाजार शेयर की हानि का कारण संबद्ध देश से आयात नहीं है अपितु उसकी अनुप्रवाह वस्तुओं का घटिया निर्यात निष्पादन है।
- v. वर्ष 2014-15 के दौरान, जुलाई 2015 तक मलबरी रेशम का आयात लगभग 1139 मी. टन था, इसकी तुलना में पूर्व वर्ष की इसी अवधि के दौरान इसका आयात 1166 मी. टन था। अतः यह स्पष्ट रूप से दर्शाया है कि यद्यपि पाटनरोधी शुल्क जनवरी 2014 से लागू नहीं था, परंतु आयात में बढ़ती हुई प्रवृत्ति नहीं दर्शायी है।

घरेलू उद्योग के द्वारा किया गया निवेदन

45. घरेलू उद्योग के द्वारा किए गए क्षति संबंधी निवेदन निम्नलिखित हैं :-

- i. कुल आयातों में संबद्ध देश से आयातों का हिस्सा जाँच की अवधि के दौरान 97.14 प्रतिशत के समान था। यह भी देखा जा सकता है कि संबद्ध देश से आयात आधार वर्ष में 100 (सूचित) से पर्याप्त रूप से बढ़कर जाँच की अवधि के दौरान 199 (सूचित) हो गया है।

- ii. घरेलू उद्योग ने यह निवेदन किया है कि कुल भारतीय मांग में संबद्ध देश का शेयर आधार वर्ष के दौरान केवल 8.53 प्रतिशत था। तथापि, भारत में कुल भारतीय मांग में संबद्ध देश का हिस्सा जाँच अवधि के दौरान 14.02 प्रतिशत तक बढ़ गया है।
- iii. उत्पादन में संबद्ध देश से आयातों का हिस्सा आधार वर्ष के 17.9 प्रतिशत से पर्याप्त रूप से बढ़कर जाँच अवधि के दौरान 28.5 प्रतिशत हो गया है।
- iv. घरेलू उद्योग की लागत आधार वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में जाँच अवधि के दौरान काफी बढ़ गई है। दुर्भाग्यवश, संबद्ध देश से कम कीमत के पाटित आयातों की वजह से हुई लागत में बढ़ोत्तरी के समनुरूप घरेलू उद्योग विक्रय मूल्य को बढ़ा नहीं सका है। तदनुसार, यह स्पष्ट है कि संबद्ध देश से पाटित आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को नियंत्रित किया है।
- v. एक ही अवधि के दौरान पहुंच कीमत में हुई वृद्धि के अनुरूप घरेलू विक्रय मूल्य में बढ़ोत्तरी तथा सकारात्मक कम दाम होने की कोई संभावना नहीं है, इस बारे में हितबद्ध पक्षकारों के निवेदन के संबंध में घरेलू उद्योग ने यह निवेदन किया है कि आवेदन पत्र में उपलब्ध कराये गये सूचकांकों के आधार पर हितबद्ध पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि पहुंच कीमत जाँच अवधि के दौरान घरेलू विक्रय मूल्य से काफी अधिक है और मूल्य पर कोई नियंत्रण अथवा दबाव नहीं है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने यह निवेदन किया है कि कभी-कभी सूचकांक सही निष्कर्ष नहीं देता है। इस मामले में यही स्थिति जारी है, जहां पर घरेलू विक्रय मूल्य (134 – सूचित) जाँच अवधि के दौरान पहुंच कीमत (142 – सूचित) से काफी अधिक है। तथापि, घरेलू विक्रय मूल्य और पहुंच मूल्य/कीमत के सूचकांकों की तुलना एक विपरीत राय देती है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने यह निवेदन किया है कि आवेदन-पत्र के अनुबंध-11 में उपलब्ध कराए अनुसार सकारात्मक मूल्य को कम करना बिना किसी शंका के यह साबित करता है कि संबद्ध वस्तुओं का घरेलू विक्रय मूल्य, संबद्ध देश से पहुंच कीमत से अधिक है।
- vi. घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि संबद्ध देश के अलावा 4 स्रोतों से संबद्ध वस्तुओं के निर्यात जाँच की अवधि के दौरान डी-मिनिमिस होते हैं। अतः उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर यह बहुत स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग के लिए क्षति का वास्तविक कारण संबद्ध देश से पाटित निर्यात है।
- vii. क्षति का वास्तविक कारण संबद्ध देश से कम कीमत का पाटित आयात है। संबद्ध देश से कम कीमत के पाटित आयातों लागत में बढ़ोत्तरी होने के समनुरूप घरेलू उद्योग घरेलू विक्रय मूल्य को बढ़ा नहीं सका है। इसके अलावा, संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं की निर्यात मात्रा आधार वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान लगभग दुगुनी हो गई थी। इसके परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योग का निष्पादन बहुत ही विकृत हो गया है। इसलिए हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा उत्तरदायी ठहराए गए कारण बिना किसी तर्क और प्रमाणीकरण के हैं।
- viii. पूर्ववर्ती वर्ष की इसी अवधि के दौरान आयातों की तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान आयातों ने कोई बढ़ती हुई प्रवृत्ति नहीं दर्शायी है, इस बारे में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया यह दावा बिना किसी गुण-दोष के है। हितबद्ध पक्षकारों ने अपने दावे के बारे में सबूत देने हेतु अयात संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए हैं। इसके अलावा, 2014-15 के आयात आंकड़ों के संसाधन भी उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। उपरोक्त के दृष्टिगत, घरेलू उद्योग इस बारे में कोई सार्थक टिप्पणियां देने में असमर्थ हैं।
- ix. संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में तेजी से और वस्तुगत कमी हुई है।
- x. निवेशों पर आय में तेजी से कमी आयी है। पीओआई का वर्तमान स्तर वांछनीय और न्यायसंगत स्तरों से काफी कम है, जिसको पाटित आयातों के न होने की स्थिति में घरेलू उद्योग के द्वारा प्राप्त कर लेना चाहिए।
- xi. संबद्ध देश का पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम स्तरों से अधिक है, अपितु बहुत ही सार्थक है।
- xii. संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों की वजह से घरेलू उद्योग को वस्तुगत क्षति हुई है।

- xiii. बहुत ही कम मूल्यों पर आयात होने से निवेश लागत में वृद्धि की सीमा तक उनके मूल्य को बढ़ाने से घरेलू उद्योग रुक रहा है, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य को नियंत्रित किया जा रहा है।
- xiv. लाभों में कमी से लगायी गई पूंजी पर आय और नकद लाभों में प्रत्यक्षतः कमी हुई है। घरेलू उद्योग पूंजीगत लागत को प्राप्त नहीं कर सका है। अतः लाभों, लगायी गई पूंजी पर आय तथा नकद प्रवाह भी और नकद लाभ में कमी प्रत्यक्षतः पाटित आयातों की वजह से है।

प्राधिकारी के द्वारा जाँच

46. डब्ल्यूटीओ करार के अनुच्छेद 3.1 और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II में इन दोनों की विषयपरक जाँच का प्रावधान है – (क) समान उत्पादों के लिए घरेलू बाजार में पाटित आयातों की मात्रा तथा मूल्यों पर पाटित आयातों का प्रभाव; तथा (ख) ऐसे उत्पादों का घरेलू उत्पादकों के मात्रात्मक प्रभाव के संबंध में प्राधिकारी के द्वारा यह जाँच करना अपेक्षित होता है कि क्या पाटित आयातों का पूर्णतः अथवा भारत में उत्पादन अथवा खपत के संदर्भ में पर्याप्त वृद्धि हुई है। पाटित आयातों के मूल्य संबंधी प्रभाव के बारे में प्राधिकारी के द्वारा यह जाँच करना अपेक्षित होता है कि क्या भारत में समान उत्पादन के मूल्य की तुलना में पाटित आयातों से मूल्य में काफी कमी की गई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव एक पर्याप्त सीमा तक मूल्यों को अन्यथा नियंत्रित करना अथवा मूल्यों में वृद्धि को रोकना है, जो एक पर्याप्त सीमा तक अन्यथा होंगी।
47. जहाँ तक घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा (IV) में निम्नानुसार उल्लेख है :-
"संबंधित घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जाँच में बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में स्वाभाविक और संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले सभी संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों, घरेलू कीमतों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों का मूल्यांकन शामिल होगा।"
48. प्राधिकारी द्वारा नीचे किया गया क्षति विश्लेषण हितबद्ध पक्षकारों के द्वारा किए गए विभिन्न निवेदनों को स्वतः ही लिख कर भेजे जाते हैं।

घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क) मांग और बाजार शेयर

49. भारत में उत्पाद मांग और प्रत्यक्ष उपभोग को भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्रियों और सभी संसाधनों से आयातों के जोड़ के रूप में लिया गया है। इस प्रकार आकलन की गई मांग नीचे सारणी में दी गई है :

i. मांग

| वर्ष | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | जाँच अवधि | वार्षिक जाँच अवधि |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|-------------------|
| संबद्ध देश से आयात (कि. ग्रा.) | 1262809 | 2074747 | 2245835 | 2216838 | 1773470 |
| अन्य देशों से आयात (कि. ग्रा.) | 9003 | 126776 | 104152 | 19202 | 15362 |
| कुल आयात (कि. ग्रा.) | 1271812 | 2201523 | 2349987 | 2236040 | 1788832 |
| आयात में संबद्ध देश की शेयर प्रतिशतता | 99.3% | 94.24% | 95.57% | 99.14% | 99.14% |
| प्रवृत्ति देश | 100 | 164 | 178 | 176 | 140 |
| घरेलू उद्योग की बिक्री | 5678324 | 6750702 | 6748971 | 8891243 | 7112994 |
| अन्य उत्पादकों की बिक्री | 5134166 | 5437185 | 5653499 | 6573311 | 5258649 |
| कुल मांग (कि. ग्रा.) | 12084302 | 14389410 | 14752457 | 17700594 | 14160475 |

50. यह नोट किया जाता है कि आधार वर्ष की तुलना में जाँच अवधि में देश में मांग बढ़ी है। जबकि पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में वार्षिक कीमतों में कमी हुई है, कमी सीमांत है और मांग का सामान्य स्तर कम अथवा ज्यादा एक समान ही रहा है।

ii. मांग में बाजार का शेयर

51. प्राधिकारी ने भारत में कुल मांग के संबंध में आयातों का बाजार शेयर का विश्लेषण करने के लिए भारतीय उत्पादकों के सभी आयातों और विक्रियों के बारे में विचार किया है। स्थिति नीचे दिए अनुसार है :

| विवरण | इकाई | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | जाँच अवधि |
|--------------------|------|---------|---------|---------|-----------|
| चीन | % | 10.45 | 14.42 | 15.22 | 12.52 |
| अन्य देश | % | 0.07 | 0.88 | 0.71 | 0.11 |
| घरेलू उद्योग | % | 46.99 | 46.91 | 45.75 | 50.23 |
| अन्य घरेलू उत्पादक | % | 42.49 | 37.79 | 38.32 | 37.14 |

52. उपर्युक्त सारणी से यह देखा गया है कि आधार वर्ष की तुलना में चीन से बाजार की हिस्सेदारी बढ़ी है, जबकि तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में सीमांत कमी हुई है। तथापि, यह नोट किया जाता है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग के लिए क्षति हेतु बाजार का हिस्सा अभी पर्याप्त है कि सम्बद्ध वस्तुएं भारतीय बाजार में पाटित कीमतों पर प्रदान की जाती हैं।

iii. आयात की मात्रा और बाजार का हिस्सा

53. प्राधिकारी ने डीजीसीआई एंड एस से प्राप्त हुए आयात आंकड़ों के आधार पर संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा की जाँच की है। संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं की आयात की मात्रा और संबद्ध वस्तुओं के कुल आयातों में उसके शेयर का ब्यौरा नीचे दी गई सारणी में उपलब्ध है :

| विवरण | | इकाई | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | जांच अवधि | वार्षिक पीओआई |
|----------------------------|------------|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------------|
| मात्रा | चीन | कि. ग्रा. | 1262809 | 2074747 | 2245835 | 2216838 | 1773470 |
| | अन्य देश | कि. ग्रा. | 9003 | 126776 | 104152 | 19202 | 15362 |
| | कुल अयात | कि. ग्रा. | 1271812 | 2201523 | 2349987 | 2236040 | 1788832 |
| आयातों में बाजार का हिस्सा | संबद्ध देश | % | 99.3 | 94.24 | 95.57 | 99.14 | 99.14 |
| | अन्य | % | 0.71 | 5.76 | 4.43 | 0.86 | 0.86 |

54. उपर्युक्त सारणी से यह देखा गया है कि संबद्ध देश से आयात आधार वर्ष में 1262809 कि. ग्रा. से बढ़कर जाँच अवधि (वार्षिक) के दौरान 1773470 कि. ग्रा. हो गया। यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध देश से आयात जाँच अवधि के दौरान भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल आयातों का 99.14 प्रतिशत लेखे में लिया है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि आधार वर्ष की तुलना में जाँच अवधि में आयातों के शेयर में

सीमांत कमी हुई है। मात्रा के समग्र प्रभाव के बारे में भी उन कीमतों के संदर्भ में जाँच करनी होगी जिस पर चीन से आयात आ रहे हैं।

iv. उत्पादन के संबंध में आयातों का हिस्सा

55. प्राधिकारी यह देखते हैं कि आधार वर्ष की तुलना में घरेलू उद्योग के उत्पादन के संबंध में देश से आयातों में वृद्धि हुई है, यद्यपि, तत्काल पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में जाँच अवधि के दौरान कमी हुई है। यह निम्नलिखित सारणी से स्पष्ट है :

| विवरण | इकाई | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | जाँच अवधि | वार्षिक पीओआई |
|--|-----------|---------|---------|---------|-----------|---------------|
| चीन से आयात | कि. ग्रा. | 1262809 | 2074747 | 2245835 | 2216838 | 1773470 |
| घरेलू उद्योग का उत्पादन | कि. ग्रा. | 5678324 | 6750702 | 6748971 | 8891243 | 7112994 |
| घरेलू उद्योग के उत्पाद के संबंध में पाटित आयात | % | 22.2 | 30.7 | 33.3 | 24.9 | 24.9 |

v. क्षमता और क्षमता उपयोग

56. यह नोट किया जाता है कि आधार वर्ष की तुलना में जाँच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में वृद्धि हुई है। घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में वृद्धि मांग में वृद्धि होने के कारण हुई और इस कारण भी हुई कि 5 जनवरी, 2014 तक रॉ-सिल्क पर पाटन रोधी शुल्क था।

| विवरण | इकाई | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | पीओआई | वार्षिक पीओआई |
|------------------|------|---------|---------|---------|----------|---------------|
| क्षमता कि. ग्रा. | KG | 9893000 | 9893000 | 9893000 | 12366250 | 9893000 |
| उत्पादन | KG | 5678324 | 6750702 | 6748971 | 8891243 | 7112994 |
| क्षमता उपयोग | % | 57.40 | 68.24 | 68.22 | 71.90 | 71.90 |

उत्पादन

57. यह नोट किया जाता है कि मांग में वृद्धि होने तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 5 जनवरी, 2014 तक रॉ-सिल्क पर पाटन रोधी शुल्क था, जैसा कि अन्य पैरामीटरों के लिए भी देखा गया है, आधार वर्ष और पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन में वृद्धि हुई है।

| विवरण | इकाई | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | पीओआई | वार्षिक पीओआई |
|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| उत्पाद | कि. ग्रा. | 5678324 | 6750702 | 6748971 | 8891243 | 7112994 |
| प्रवृत्ति | सूचित | 100 | 119 | 119 | 157 | 125 |
| मांग | कि. ग्रा. | 12084302 | 14389410 | 14752457 | 17700594 | 14160475 |
| प्रवृत्ति | सूचित | 100 | 119 | 122 | 146 | 117 |

vi. बिक्री की मात्रा

58. यह देखा गया है कि मांग में वृद्धि होने के कारण आधार वर्ष और तत्काल पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में पीओआई के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री में वृद्धि हुई है।

| विवरण | इकाई | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | पीओआई | वार्षिक पीओआई |
|--|-----------|----------|----------|----------|----------|---------------|
| घरेलू उद्योग | कि. ग्रा. | 5678324 | 6750702 | 6748971 | 8891243 | 7112994 |
| प्रवृत्ति | सूचित | 100 | 119 | 119 | - | 125 |
| मांग | कि. ग्रा. | 12084302 | 14389410 | 14752457 | 17700594 | 14160475 |
| प्रवृत्ति | सूचित | 100 | 119 | 122 | - | 117 |
| मांग में घरेलू उद्योग के बाजार भागीदार | % | 46.99 | 46.91 | 45.75 | - | 50.23 |

घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

59. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के बारे में निर्दिष्ट प्राधिकारी के द्वारा इस बारे में विचार करना अपेक्षित है कि क्या पाटित आयातों का पूर्णतः अथवा भारत में उत्पादन अथवा खपत के संदर्भ में पर्याप्त वृद्धि हुई है। पाटित आयातों के मूल्य संबंधी प्रभाव के बारे में प्राधिकारी के द्वारा यह जाँच करना अपेक्षित होता है कि क्या भारत में समान उत्पादन के मूल्य की तुलना में पाटित आयातों से मूल्य में काफी कमी की गई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव एक पर्याप्त सीमा तक मूल्यों को अन्यथा नियंत्रित करना अथवा मूल्यों में वृद्धि को रोकना है, जो एक पर्याप्त सीमा तक अन्यथा होंगी। इस विश्लेषण के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग के उत्पादन की औसत लागत (सीओपी), औसत निवल विक्रय वसूली (एनएसआर) और क्षति रहित कीमत (एनआईपी) की संबद्ध देश से आयातों की पहुंच कीमत के साथ तुलना की गई है।

i. कीमत कम करना

60. निवल बिक्री प्राप्ति, फैक्टरी के बाद के खर्चों अर्थात् बाहरी माल-भाड़ा और करों की कटौती करने के बाद में निकाली गई थी। आयातों की पहुंच कीमत की 1 प्रतिशत रखरखाव प्रभार तथा संबद्ध आयातों के सीआईएफ मूल्य के लिए लागू उपकर सहित लागू आधारभूत सीमा शुल्क को जोड़कर गणना की गई है। आयातों की पहुंच कीमत की घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति के साथ तुलना की गई थी और यह पाया गया कि पाटित आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतें कम हो रही हैं जैसा कि नीचे दी गई सारणी में देखा जा सकता है :

| विवरण | इकाई | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | पीओआई |
|---------------------------|----------------|---------|----------|---------|-------|
| आयातों की पहुंच कीमत | रु./ कि. ग्रा. | 2336 | 2365 | 2688 | 3281 |
| डीआई का निवल विक्रय मूल्य | रु./ कि. ग्रा. | *** | *** | *** | *** |
| कीमत कम करना | रु./ कि. ग्रा. | *** | *** | *** | *** |
| कीमत कम करना | % | *** | *** | *** | *** |
| कीमत कम करना | रैंज | 5-15 | (5)-(10) | 5-10 | 5-10 |

61. उपर्युक्त सारणी से यह देखा गया है कि कीमत को कम करना सार्थक है। संबद्ध देश की अत्यधिक बाजार भागीदारी से घरेलू उद्योग कीमत संबंधी दबाव डालने के लिए बाध्य होता है, जो संबद्ध देश से आयातों की पहुंच कीमतों से अपनी कीमतों को अनुरूप रखने के लिए घरेलू उत्पादकों को बाध्य करती है। कीमत संबंधी दबाव घरेलू उद्योग के वित्तीय निष्पादन को पर्याप्त रूप से दर्शाता है।

ii. कीमत से सस्ता बेचना

62. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि कीमत से सस्ता बेचना क्षति का आकलन करने का एक महत्वपूर्ण सूचक है। सस्ती कीमत पर बेचने के लिए क्षति रहित कीमत निकाली गई है और संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमत

से उसकी तुलना की गई है। लागू सीमा तक पाटन रोधी नियमावली के अनुबंध 111 के अनुसार पीओआई के दौरान विचाराधीन उत्पाद के लिए घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत पर विचार करते हुए क्षति रहित कीमत निर्धारित की गई है। विश्लेषण यह दर्शाता है कि संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत क्षति रहित कीमत से कम थी, जैसा कि नीचे दी गई सारणी से देखा जा सकता है :

| विवरण | चीन (रु. कि. ग्रा.) | चीन (डालर कि. ग्रा.) |
|----------------------------|---------------------|----------------------|
| एनआईपी | *** | *** |
| आयातों की पहुंच कीमत | 3281 | 53.90 |
| सस्ती कीमत पर बेचना | *** | *** |
| सस्ती कीमत पर बेचना (%) | *** | *** |
| सस्ती कीमत पर बेचना (रैंज) | 0-10 | 0-10 |

iii. कीमत पर रोक/कमी

63. प्राधिकारी यह जाँच करते हैं कि क्या पाटित आयातों का प्रभाव भारत में समान वस्तुओं की कीमतों में कमी लाना अथवा कीमत में बढोत्तरी को रोकना है जो अन्यथा हुई होगी।

| विवरण | इकाई | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | पीओआई |
|----------------|-------------|---------|---------|---------|-------|
| बिक्री की लागत | रु./किग्रा. | *** | *** | *** | *** |
| सूचीबद्ध | प्रवृत्ति | 100 | 85 | 110 | 136 |
| बिक्री कीमत | रु./किग्रा. | *** | *** | *** | *** |
| सूचीबद्ध | प्रवृत्ति | 100 | 85 | 112 | 134 |
| पहुंच कीमत | रु./किग्रा. | 2336 | 2365 | 2688 | 3281 |
| सूचीबद्ध | प्रवृत्ति | 100 | 101 | 115 | 140 |

64. उपर्युक्त सारणी से यह देखा गया है कि आधार वर्ष से पीओआई तक बिक्री की लागत का सूचकांक 100 से बढ़कर 136 हो गया है। एक ही अवधि के दौरान विक्रय मूल्य केवल 100 से बढ़कर 134 यह दर्शाते हुए हुआ कि कीमतों पर पाटित आयातों की वजह से नियंत्रण लगा था क्योंकि घरेलू उद्योग लागतों में वृद्धि के अनुरूप अपनी कीमतें बढ़ा नहीं सका था।

ज. घरेलू उद्योग के आर्थिक पैरामीटर

i. लाभ/हानि

65. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में आधार वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान काफी कमी हुई थी। नकद लाभ और निवेश पर आय में भी यही प्रवृत्ति हुई।

| विवरण | इकाई | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | पीओआई |
|---------|----------------|---------|---------|---------|-------|
| लाभ | रु./ कि. ग्रा. | *** | *** | *** | *** |
| सूचित | प्रवृत्ति | (100) | (87) | (30) | (209) |
| नकद लाभ | रु./ कि. ग्रा. | *** | *** | *** | *** |
| सूचित | प्रवृत्ति | (100) | (71) | 49 | (334) |
| आरओसीई | % | *** | *** | *** | *** |
| सूचित | प्रवृत्ति | (100) | (104) | (38) | (281) |

ii. नकद प्रवाह

66. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की नकद प्रवाह की स्थिति पर पाटन के प्रभाव की जाँच करने के लिए नकद लाभों में की प्रवृत्तियों की जाँच की है। यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग के नकद लाभों में आधार वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान काफी कमी हुई है। घरेलू उद्योग के नकद लाभ के संबंध में सूचना नीचे सारणी में दी गई है :

| विवरण | इकाई | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | पीओआई |
|----------|----------------|---------|---------|---------|-------|
| नकद लाभ | रु./ कि. ग्रा. | *** | *** | *** | *** |
| सूचीबद्ध | प्रवृत्ति | (100) | (71) | 49 | (334) |

iii. सामान्य सूचियां

67. वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए समान-सूचियों से संबंधित विवरण उपलब्ध नहीं हैं तथा इस कारक का विश्लेषण किया नहीं जा सकता है।

iv. उत्पादकता

68. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि वर्तमान मामले में इस कारक का विश्लेषण नहीं किया जा सकता क्योंकि नियोजित कर्मचारियों की सही संख्या का पता नहीं लगाया जा सकता है। ज्यादा अथवा कम परिवार उद्यम होने की वजह से कामगारों की वास्तविक संख्या नहीं रखी जाती है। तथापि, विश्वास करने का कारण यह है कि प्रति कर्मचारी/ कामगार उत्पादकता में वृद्धि होगी, विशेषकर जब उत्पादन बढ़ा हो और प्रति बेसिन कामगारों की संख्या वही रही हो।

v. रोजगार एवं मजदूरी

69. घरेलू उद्योग की विशिष्ट प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जहां उत्पादन यूनिटों को मुख्य रूप से अलग-अलग परिवारों के द्वारा चलाया जाता है और परिवार के सभी सदस्य उत्पादन की प्रक्रिया में लगे हैं, कर्मचारियों की सही संख्या और उन्हें भुगतान की गई मजदूरी को निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तथापि, यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि इस व्यापार में नियोजित कामगार संबंधित राज्यों में प्रचलित न्यूनतम मजदूरी भी प्राप्त कर रहे हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि न्यूनतम मजदूरी प्राप्त न करना भी वस्तुगत क्षति का एक महत्वपूर्ण सूचक है।

vi. पाटन की मात्रा

70. जिस सीमा तक पाटित आयातों से घरेलू उद्योग क्षतिग्रस्त हो सकता है, उस सीमा तक सूचक के रूप में पाटन की मात्रा यह दर्शाती है कि संबद्ध देश के विरुद्ध निर्धारित पाटन मार्जिन अधिक न्यूनतम और महत्वपूर्ण होता है।

vii. विकास

71. नीचे दी गई सारणी से प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग का विकास लाभप्रदता, नकद प्रवाह और आरओसीई के मामले में, विशेष तौर पर आधार वर्ष की तुलना में पीओआई के दौरान नकारात्मक था। घरेलू उद्योग के लिए संबद्ध देश से कम मूल्य पर पाटित आयातों की वजह से लाभप्रदता में बड़ोत्तरी के रूप में बढ़ती हुई मांग का लाभ लेने से मनाही थी।

| विवरण | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | पीओआई |
|----------------------------|---------|---------|---------|-------|
| प्रति यूनिट लाभप्रदता (%) | 0 | 13 | 70 | (109) |
| प्रति यूनिट नकद प्रवाह (%) | 0 | 29 | 149 | (234) |
| आरओसीई (%) | 0 | शून्य | 62 | (181) |

viii. पूजी निवेश प्राप्त करने की क्षमता

72. यह नोट किया जाता है कि इस उत्पाद में कोई अतिरिक्त निवेश करने की घरेलू उद्योग की क्षमता बाजार की स्थिति पर निर्भर करती है। यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में चीन से संबद्ध वस्तुओं

के कम मूल्य के पाटित आयातों के कारण आधार वर्ष की तुलना में क्षति की अवधि के दौरान कमी हुई है। अतः उत्पाद के पाटन से उत्पाद के लिए पूंजी निवेश प्राप्त करने के लिए घरेलू उद्योग की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

झ. क्षति संबंधी निष्कर्ष

73. उपर्युक्त के आधार पर प्राधिकारी का निष्कर्ष यह है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों में आधार वर्ष से तुलना करने पर पूरी तरह से और भारत में संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और खपत में बढ़ोत्तरी हुई है। तथापि, क्षति का महत्वपूर्ण प्रभाव कीमत पर हुआ जहां पर चीन से हुए आयातों से बाजार में घरेलू उद्योग की कीमतों में कमी होती हुई पायी गई है। संबद्ध वस्तुओं की पहुंच कीमत एनआईपी से काफी कम है, यह तथ्य स्पष्टतः वस्तुओं के सस्ते मूल्य पर बेचने के अस्तित्व को दर्शाता है। इसके अलावा, क्षति की अवधि उत्पादन लागत यद्यपि बढ़ती हुई गई, परंतु विक्रय मूल्य में वृद्धि उत्पादन लागत में वृद्धि के अनुरूप नहीं थी। अतः आयातों की वजह से घरेलू उद्योग की कीमतों पर दबाव का सामना करना पड़ रहा है और ये कीमतों में वृद्धि को रोक रहे हैं, जो पाटित आयातों के न होने की स्थिति में अन्यथा होगी। घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में यह देखा गया कि उत्पाद की मांग में यद्यपि काफी अधिक वृद्धि हुई, परंतु संबद्ध देश से कम मूल्य के पाटित आयातों की वजह से घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में कमी हुई।

74. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति हुई है, जिसके परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में कमी आयी है। लगायी गई पूंजी पर आय और नकद लाभ में भी लाभों की तरह की वही प्रवृत्ति हुई। लगायी गई पूंजी पर आय और नकद लाभ दोनों ने क्षति की अवधि के दौरान नकारात्मक वृद्धि दर्शायी थी। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन में लगे कामगार न्यूनतम मजदूरी अर्जित नहीं कर रहे हैं। अतः लाभ, नकद लाभ, और लगायी गई पूंजी पर आय, मजदूरी आदि जैसे अधिकांश पैरामीटरों में वृद्धि घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाते हैं। अतः प्राधिकारी का निष्कर्ष यह है कि घरेलू उद्योग को वस्तुतः क्षति हुई है।

ञ. कारणात्मक संबंध और अन्य कारक

75. घरेलू उद्योग की कीमतों पर पाटित आयातों से बहुत अधिक हानि, मात्रा और कीमत के प्रभावों की मौजूदगी की जाँच करने के बाद, भारतीय नियमावली और पाटन रोधी करार के अंतर्गत सूचीबद्ध इसकी कम कीमत पर बिक्री और कीमत पर दबाव तथा ह्रास के प्रभावों के आधार पर अन्य सांकेतिक मानदंडों की इस बात की जाँच की है कि क्या पाटित आयातों के अलावा कोई अन्य कारक घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकते थे। तदनुसार निम्नलिखित पैरामीटरों की जाँच की गई है :

(क) तृतीय दशों से आयातों की मात्रा और कीमतें

76. जांच की अवधि के दौरान चीन को छोड़कर अन्य देशों से संबद्ध वस्तुओं के आयातों की मात्रा बहुत अधिक रही है। इस कारण से अन्य स्रोतों से आयातों को इस बाबत विचार नहीं किया जा सकता है कि इसने घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाई है।

(ख) विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं एवं प्रतिस्पर्धा

77. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तुओं के लिए यह एकमात्र बाजार है जहां संबद्ध देश से पाटित आयातों की सीधी प्रतिस्पर्धा घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किए गए संबद्ध वस्तुओं से होती है। यह भी नोट किया जाता है कि आयात किए गए संबद्ध वस्तुओं और घरेलू रूप से उत्पादित वस्तुएं समान वस्तु हैं और उनका उपयोग समान उपयोगों/ अंतिम प्रयोगों के लिए किया जाता है। विदेशी उत्पादकों और घरेलू उत्पादकों के बीच व्यापार प्रतिबंधात्मक प्रथाओं और प्रतिस्पर्धा का ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति पहुंच रही हो।

(ग) मांग का संकुचन तथा उपभोग के पैटर्न में परिवर्तन

78. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि तत्काल पहले वर्षों की तुलना में पीओआई में मांग में सीमांत रूप से कम आयी थी, परंतु जाँच की सम्पूर्ण अवधि के दौरान इस उत्पाद के लिए मांग में बहुत अधिक वृद्धि दर्शायी गई और इस प्रकार से यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि घरेलू उद्योग को क्षति मांग में संकुचन के कारण नहीं हुई थी।

(घ) प्रौद्योगिकी में विकास

79. किसी भी हितवद्ध पक्षकारों में यह दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया है कि प्रौद्योगिकी में बहुत अधिक परिवर्तन हुए हैं जिससे घरेलू उद्योग को बहुत अधिक हानि हुई हो।

(ङ) घरेलू उद्योग का निर्यात कार्य निष्पादन

80. घरेलू उद्योग क्षति जाँच की सम्पूर्ण अवधि के दौरान निर्यात बिक्री में शामिल नहीं है। अतः प्राधिकारी यह निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग के लिए क्षति का कारण घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन नहीं था।

(च) घरेलू उद्योग की उत्पादकता

81. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि क्षति जाँच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन में वर्ष 2011-12 की तुलना में वर्ष 2012-13 के दौरान हुई सीमांत कमी को छोड़कर बढ़ोत्तरी हुई है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रति बेसिन कामगारों की संख्या समान रही है, इस बात पर भरोसा करने का कारण यह है कि उत्पादकता में वस्तुतः बढ़ोत्तरी हुई है।
82. पूर्वोक्त के आधार पर प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि पाटन के अलावा दूसरे कोई प्रमाण नहीं हैं, जिनसे क्षति हुई है।

ट. कारणात्मक संबंध स्थापित करने वाले कारक

83. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग के कार्य निष्पादन का विश्लेषण यह दर्शाता है कि घरेलू उद्योग का निष्पादन संबद्ध देश से कम मूल्य पर पाटित आयातों की वजह से क्षति की अवधि में पर्याप्त मात्रा में गिरावट हुई है। पाटित आयातों और घरेलू उद्योग की क्षति के बीच कारणात्मक संबंध निम्नलिखित आधारों पर स्थापित किया गया है :

क) संबद्ध देश से आयातों की वजह से घरेलू उद्योग की कीमतों में कमी हो रही है। परिणामतः लाभप्रदता में कमी आयी है, जबकि अन्य वित्तीय पैरामीटर जाँच की अवधि के दौरान प्रतिकूल रूप से काफी प्रभावित हो रहे हैं।

ख) घरेलू उद्योग को अपने निवेशों और श्रम पर उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसे दर्शाते हुए वस्तुओं को काफी सस्ता बेचा जा रहा है।

ग) पाटित आयातों की कीमतों के अस्तित्व में होने से लागतों में वृद्धि होने के अनुरूप घरेलू उद्योग अपनी कीमतों को बढ़ाने से रोकी जा रही है, जो कीमतों को नियंत्रित कर रही है, जिसके परिणामस्वरूप आधार वर्ष की तुलना में जाँच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में कमी हुई है।

घ) लाभ, नियोजित पूंजी पर आय और नकद लाभ में गिरावट तथा न्यूनतम मजदूरी भी न अर्जित कर पाना पाटित आयातों का प्रत्यक्ष परिणाम है।

ङ) घरेलू उद्योग में वृद्धि कीमत से संबंधित आर्थिक तथा मात्रात्मक पैरामीटरों के मामले में नकारात्मक हो गई है।

84. उपर्युक्त आधार पाटित आयातों और घरेलू उद्योगों को क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के मौजूद होने को स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है। अतः प्राधिकारी का यह मत है कि संबद्ध देश में उद्भूत अथवा वहां से निर्यात की गई संबद्ध वस्तुओं के कम कीमत के पाटित निर्यातों की वजह से काफी क्षति हुई।

ठ. क्षति और क्षति मार्जिन का आकार

85. प्राधिकारी ने नियमावली में यथा संशोधित निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत का निर्धारण किया है। इस प्रकार से निर्धारित क्षति रहित कीमत की तुलना संबद्ध देश से आयातों की पहुंच मूल्य से की गई है। चीन गणराज्य के सभी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए क्षति मार्जिन सर्वोत्तम उपलब्ध तथ्यों के आधार पर प्राधिकारी के द्वारा निर्धारित करने का प्रस्ताव किया गया, जो नीचे दिए अनुसार है।

| विवरण | क्षति रहित कीमत अमरीकी डालर/ कि. ग्रा. | पहुंच मूल्य अमरीकी डालर/ कि. ग्रा. | क्षति मार्जिन - अमरीकी डालर/ कि. ग्रा. | क्षति मार्जिन % | क्षति मार्जिन रेंज - % |
|--|---|---------------------------------------|--|--------------------|---------------------------|
| चीन जन.गण. के सभी उत्पादक और निर्यातक | *** | 53.90 | *** | *** | 0-10 |

86. प्रकटन पश्चात विवरण/निवेदन

घरेलू उद्योग द्वारा निवेदन

87. घरेलू उद्योग ने जाँच के विभिन्न चरणों के दौरान प्राधिकारी को पहले अपने विस्तार से टिप्पणियाँ/निवेदन/खंडन प्रस्तुत किए थे। अब कोई नया निवेदन नहीं है और उन्हें संक्षिप्त रखने के लिए दोबारा यहां पर दोहराया नहीं जा रहा है और दोहराने से बचा जा रहा है। मुख्य टिप्पणियों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

(क) सी सी सी टी द्वारा किए गए निवेदन को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि सी सी सी टी ने किसी भी पत्र के द्वारा यह निवेदन नहीं किया है कि वह एक व्यावसायिक एशोसिएशन है और उसके अधिकतर सदस्य संबद्ध उत्पाद के उत्पादक, निर्यातक अथवा आयातक हैं। इसलिए नियमावली के नियम 2(ग) के अनुसार उसे एक हितबद्ध पक्षकार नहीं माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अंतिम तारीख के काफी समय बाद निवेदन किया था और विलंब का कोई कारण नहीं बताया था। इसके अलावा, सी सी सी टी द्वारा प्रस्तुत किए गए लिखित आवेदनों पर अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं इसलिए उन्हें मौजूदा कार्रवाई के लिए कानूनी रूप से स्वीकार्य दस्तावेज नहीं माना जा सकता है। इस अतिरिक्त कारण से हम प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि सी सी सी टी द्वारा किए गए निवेदनों को रिकॉर्ड में नहीं लिया जाए।

(ख) अखिल भारतीय रेशम बुनकर संघ ने प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर घरेलू उद्योग के आवेदन पत्र पर टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की है। इसको ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह अखिल भारतीय रेशम बुनकर परिसंघ द्वारा किए गए निवेदनों को स्वीकार न करें। (ग) साइनों इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स प्रा. लि. ने भी निर्धारित समय सीमा के बाद ही अपने लिखित निवेदन प्रस्तुत किए हैं। इसको भी ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे देर से प्रस्तुत किए गए उनके लिखित निवेदनों को स्वीकार नहीं करें।

उत्पादकों/निर्यातकों/आयातकों/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदन :

88. चाइना चैम्बर ऑफ कामर्स फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ टैक्सटाइल, वीवर्स एसोसिएशन जोकि आयातित सामग्री के प्रयोक्ता हैं तथा मैसर्स साइनो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रा.लि. जोकि आयातक हैं, ने भी प्रकटन विवरण पर निवेदन प्रस्तुत किए हैं। कोई अतिरिक्त बिन्दु नहीं है। निवेदन के संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार हैं :-

क. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने मौजूदा जाँच में विश्लेषण करने के लिए डी जी सी आई एंड एस के कारोबार-वार आयात आंकड़ों पर विश्वास किया है। प्रतिवादी का यह निवेदन है कि उत्पाद के कार्यक्षेत्र में “ 3-क ग्रेड और उससे निम्न स्तर की शहतूती अपरिष्कृत रेशम (न बटी हुई)” शामिल नहीं हैं। इसलिए जिनमें उपरोक्त 3-क ग्रेड को शामिल किया गया है, उन सभी कारोबार को विचाराधीन उत्पाद से बाहर रखा जाना चाहिए क्योंकि इनके कारोबार विचाराधीन उत्पाद के कारोबार नहीं बनते हैं। इसके अतिरिक्त जिन सभी कारोबार के उत्पादों में “नहीं बटी हुई” उल्लेख नहीं किया गया है, उनको भी विचाराधीन उत्पाद से बाहर रखा जाना चाहिए। केवल उन्हीं कारोबारों को विचाराधीन उत्पाद के भाग के रूप में माना जाना चाहिए जिनकी मदों में 3-क अथवा उससे निचले के ग्रेड का उल्लेख किया गया है।

ख. प्रतिवादी का यह निवेदन है कि चीन जन.गण. से 3-क ग्रेड के आयात घरेलू उद्योग पर प्रवाह नहीं डाल रहे हैं। आयात मुख्यतः भारतीय बाजार की ऐसी मांग को पूरा करते हैं जिसे कि घरेलू उद्योग पूरा नहीं कर सकता है। घरेलू बाजार पहले से ही अपनी अनुकूलतम क्षमता का उपयोग कर रहा है। विद्युतकरघा उद्योग को बाइवोल्टाइन श्रेणी की अपरिष्कृत रेशम जोकि भारतीय घरेलू उत्पादकों के पास उपलब्ध नहीं

है, इस कारण से ही उसे मुख्यतः चीन जन.गण. से बाइवोल्टाइन श्रेणी की रेशम का आयात करना पड़ रहा है। प्रतिवादी का निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह मद-वार मद तुलना करने के लिए विभिन्न ग्रेडों को पृथक् करें न कि केवल ग्रेड 2 क और 3क को ही बल्कि क्रमशः ग्रेड 2 क और 3क के उप ग्रेडों-बाइवोल्टाइन और मल्टी बाइवोल्टाइन को भी अलग करे और उसके बाद जाँच की प्रक्रिया के अनुसार पाटन और क्षति का निर्धारण करें।

- ग. प्रतिवादी के साथ-साथ अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भी पूरी जाँच के दौरान यह तर्क दिया है कि घरेलू उद्योग पर्याप्त मात्रा में 3-क ग्रेड की आपूर्ति नहीं कर सकता है, इसलिए 3-क ग्रेड को उत्पाद के कार्य क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए।
- घ. चूंकि घरेलू उद्योग अत्यधिक फैला हुआ और बिखरा हुआ है, और उसके हजारों छोटे यूनिट हैं जोकि परिवारों द्वारा चलाए जाते हैं, इसलिए यह नहीं समझा जाना चाहिए कि जाँच दौरे के दौरान की गई जाँच में उद्योग के आंकड़े वैध थे और किस प्रकार के रिकॉर्ड की जाँच की गई और उन्हें सत्यापित किया गया।
- ङ. नियम-11 (2) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी को यह अधिदेश है कि वह क्षति का निर्धारण करे, क्षति के खतरे और घरेलू उद्योग की अवस्थापना के गतिरोध का पता लगाए, और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों के लिए पाटित आयातों और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का पता लगाए। संबंधित घरेलू उत्पादकों की पहचान किए और क्षति संबंधी सूचना को एकत्रित किए बिना ऐसी कार्रवाई संभव नहीं होगी। निर्दिष्ट प्राधिकारी को केवल उद्यमी स्तर पर उनकी क्षति की सूचना के आधार पर ऐसे उत्पादकों को हुई क्षति का निर्धारण करने तथा घरेलू उत्पादकों का पता लगाने का अधिदेश है।
- च. घरेलू उद्योग का यह तर्क है कि प्रतिवादी को एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में नहीं माना जाना सही नहीं है। प्रतिवादी को पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ग) के साथ पठित डब्ल्यू टी ओ के पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 6.11 के अनुसार इस मामले में एक सही रूप से प्रतिवादी ही माना जाना चाहिए।
- छ. चीन से अपरिष्कृत रेशमी यार्न के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से समस्त देश का रेशम बुनाई उद्योग बुरी तरह से प्रभावित होगा। करघों में काम कर रहे 20 मिलियन बुनकरों से भी अधिक बुनकर यूनिटों के बंद हो जाने के कारण अपना रोजगार खो देंगे।
- ज. प्रकटन विवरण के पैराग्राफ-35 (4) में निर्दिष्ट प्राधिकारी यह पाते हैं कि घरेलू उद्योग ने नई स्वचालित मशीनों में काफी निवेश किया हुआ है। तथापि, प्रतिवादी का यह निवेदन है कि यह स्पष्ट नहीं है कि इस घरेलू उत्पादक ने ऐसा निवेश किया है क्योंकि प्रकटन विवरण में किसी भी उत्पादक का नाम नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या ऐसा निवेश जाँच की अवधि के दौरान अथवा जाँच की अवधि के बाद किया गया है। यदि ऐसा निवेश जाँच अवधि के बाद किया गया है तो ऐसे निवेश को इस जाँच के प्रयोजनार्थ अप्रासंगिक माना जाना चाहिए।
- झ. प्रकटन विवरण के पैराग्राफ-50 में निर्दिष्ट प्राधिकारी यह पाते हैं कि आधार वर्ष 2010-11 की तुलना में जाँच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई है। प्रतिवादी सम्मानपूर्वक इस तथ्य से सहमत नहीं हैं और उसका यह निवेदन है कि संबद्ध वस्तुओं की मांग वास्तव में वर्ष-वार वर्ष के आधार पर कम हुई है। वर्ष 2010-11 में कुल मांग 12,084,302 किग्रा. थी जोकि वर्ष 2011-12 में बढ़कर 14,389,410 कि.ग्रा. हो गई। वर्ष 2012-13 में कुल मांग में और वृद्धि हुई जोकि 14,752,457 किग्रा. हो गई, लेकिन जाँच अवधि के दौरान (वर्षीकृत) मांग में तेजी से गिरावट आई जोकि 14,160, 475 किग्रा. हो गई। इसलिए विगत दो वर्षों की तुलना में जाँच अवधि (वर्षीकृत) के दौरान संबद्ध वस्तुओं की मांग में गिरावट आई है। निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे उपरोक्त तर्क के आलोक में पैराग्राफ-50 के अपने प्रेक्षण में संशोधन करें।
- ट. प्रकटन विवरण के अनुबंध-4 में निर्दिष्ट प्राधिकारी यह पाते हैं कि भारत में अपरिष्कृत शहतूती रेशम के उत्पादक औपचारिक लेखाओं को बनाकर रखने की स्थिति में नहीं हैं और वे लेखाकरण की वैसी क्रियाविधियों का अनुसरण नहीं करते हैं जैसा कि संगठित क्षेत्र में किया जाता है और न ही उनके पास ऐसे रिकॉर्डों को रखने के लिए संसाधन हैं। निर्दिष्ट प्राधिकारी आगे यह भी पाते हैं कि दिनांक 3 जुलाई, 2003 के उनके अंतिम जाँच परिणाम सं. 14/28/2012-डी जी ए डी द्वारा निर्दिष्ट प्राधिकारी ने इसी प्रकार की परिस्थितियों में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की थी। प्रतिवादी का यह निवेदन

है कि जिस समय उपरोक्त अंतिम जाँच परिणाम जारी किए गए थे, उस समय क्षतिरहित कीमत का निर्धारण करने के लिए कोई संहितायुक्त नियमावली उपलब्ध नहीं थी। तथापि, पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-3 में क्षतिरहित कीमत का निर्धारण करने के लिए कोई अब अनिवार्य संहितायुक्त नियमावली दी गई है। पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-3 में उल्लिखित सिद्धांतों का बिना किसी अपवाद के सभी मामलों में अनुसरण किया जाना चाहिए। इसलिए इस मामले में उपरोक्त निर्णयों पर विश्वास करना सही नहीं है। उपरोक्त तर्कों के आलोक में निर्दिष्ट प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे कृपया प्रकटन विवरण के अनुबंध-4 में किए गए अपने प्रेक्षण में संशोधन करें।

प्राधिकारी द्वारा जाँच

89. निर्यातक द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों और घरेलू उद्योग द्वारा दिए गए तर्कों का निदान उपर्युक्त पैराओं में किया गया है लेकिन स्पष्टता की दृष्टि से उनका समाधान पुनः किया जाता है जो इस प्रकार है :-

- i. सी सी सी टी में यह निवेदन किया है कि वह वस्तुतः चीन जन.गण. और विश्व दोनों में ही सबसे बड़ा वस्त्र और अपैरल व्यापार की एसोसिएशन है। उनके अनेक प्रचालनात्मक विभाग और शाखाएं हैं जोकि अन्य उत्पादों के साथ-साथ वस्त्रों, रेशम, परिधानों आदि के व्यवसाय में लगी हुई हैं। उपरोक्त निवेदनों के आलोक में सी सी सी टी पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ग) के अंतर्गत एक योग्यता प्राप्त हितबद्ध पक्षकार है। इसके अतिरिक्त यह भी निवेदन है कि वह थोड़े विलंब से निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकृत है। निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उन्हें एक हितबद्ध पक्षकार के रूप में माना है और यह निर्णय लिया है कि सभी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए निवेदनों को स्वीकार किया जाए और उनकी जाँच की जाए।
- ii. हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि ऐसे सभी आयात के कारोबारों को जिनमें "3क" से उपरोक्त ग्रेड उल्लिखित है और/अथवा "न बंटी हुई" शब्द उल्लिखित नहीं किया गया है, को बाहर रखा जाए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उपरोक्त 3-क और/अथवा न बंटी हुई अपरिष्कृत रेशम की कीमत, 3-क ग्रेड और उससे निचले ग्रेड की अपरिष्कृत शहतूती रेशम (न बंटी हुई) की कीमतों से अधिक है क्योंकि इसके अतिरिक्त लागत लगती है। तथापि, डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों से यह नोट किया गया है कि अनेक कारोबार में चीन जन.गण. से ग्रेड 3-क से ऊपर की अपरिष्कृत कच्चे रेशम और/अथवा बंटी हुई किस्म की रेशम की आयात की कीमतें, ग्रेड 3-क और उससे निचले ग्रेड की अपरिष्कृत शहतूती रेशम (न बंटी हुई) की कीमत से काफी कम हैं। इसलिए प्राधिकारी ने केवल उन्हीं कारोबारों को उत्पाद के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा है जिनका विवरण विशेष रूप से उपरोक्त 3-क और /अथवा न बंटी हुई दिया गया है। और इन कारोबारों के आयात की कीमत ग्रेड 3-क और उससे निचले ग्रेड की अपरिष्कृत शहतूती रेशम (न बंटी हुई) की कीमत से अधिक हैं।
- iii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए इस मुद्दे के संबंध में कि यदि शुल्क लगाए जाते हैं तो 6 से 8 लाख विद्युतकरघा बुनकरों को भुखमरी और मौत का सामना करना पड़ेगा, प्राधिकारी यह बताते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लागू करना किसी भी स्थिति में उपभोक्ताओं के उत्पाद की उपलब्धता को प्रभावित नहीं करेगा। पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापारिक पद्धतियों को समाप्त करके घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करके बाजार में अधिक प्रभावशाली ढंग से व्यवसाय करने के लिए समानांतर कार्यक्षेत्र का सृजन करना है जोकि देश के सामान्य जनहित में है। इसके अतिरिक्त कम शुल्क लगाने से यह सुनिश्चित होगा कि घरेलू उद्योग को पर्याप्त संरक्षण मिले ताकि उसको होने वाली क्षति को दूर किया जा सके।

- iv. हितबद्ध पक्षकारों ने यह मुद्दा उठाया है कि विद्युतकरघा उद्योग को भारतीय घरेलू उत्पादकों के पास बाइवोल्टाइन किस्म की अपरिष्कृत रेशम उपलब्ध नहीं होने के मुख्य कारणवश ही चीन जन.गण. से बाइवोल्टाइन किस्म की अपरिष्कृत रेशम का आयात करना पड़ता है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि जाँच के दौरान यह देखा गया है कि घरेलू उत्पादक 2-क, 3-क की बाइवोल्टाइन और मल्टी वोल्टाइन दोनों किस्मों की रेशम सहित विभिन्न ग्रेड की रेशम का विनिर्माण कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, हालांकि इस जाँच के लिए यह प्रासंगिक नहीं है फिर भी यह नोट किया जाता है कि नई स्वचालित मशीनों में अत्यधिक निवेश भी किया गया है जिससे 2-क, 3-क सहित विभिन्न ग्रेड की शहतूती अपरिष्कृत रेशम की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में बढ़ेगी।
- v. एन आई पी का निर्धारण करने के लिए अनुबंध-3 का प्रयोग करने तथा कुछ लागतों का निर्धारण करने के लिए जिस आधार को अपनाया गया है, उसके संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दे के संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि अनुबंध-3 में उल्लिखित प्रावधानों को इस तरह से नहीं पढ़ा जाए कि उससे प्राधिकारी को बेहतर सूचना प्राप्त करने के लिए अपनी शक्तियों से विचलित होना पड़े। यह सुस्थापित सिद्धांत है कि इस जाँच में घरेलू उद्योग विशिष्ट संगठित घरेलू उद्योग से विशेष रूप से अत्यधिक भिन्न है। यह घरेलू उद्योग अत्यधिक बिखरा और फैला हुआ है और इसमें सैंकड़ों छोटे यूनिट शामिल हैं। ये यूनिट कुटीर आधारित उद्योग हैं और इन्हें मुख्यतः विशिष्ट पृथक परिवारों द्वारा चलाया जाता है। यह मानते हुए कि उद्यम विशिष्ट सूचना के आधार पर ही एन आई पी को परिकलित करने की नियम में कोई विशेष आवश्यकता है, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग में शामिल यूनिटों की जाँच के दौरे के दौरान उनके आवेदन पत्र में घरेलू उद्योग द्वारा प्रदत्त की गई सूचना की परिशुद्धता को वैध ठहराया गया है। यही वैध सूचना एन आई पी का परिकलन करने का आधार बनी है।
- vi. हितबद्ध पक्षकारों के इस अनुरोध के संबंध में कि पाटन और क्षति मार्जिन का परिकलन ग्रेड-वार किया जाए। यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश के निर्यातकों ने प्रश्नावली का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है और उन्होंने पाटन मार्जिन का परिकलन करने के लिए जरूरी वस्तुगत सूचना प्रस्तुत नहीं की है। ऐसी आवश्यक सूचना के न होने की स्थिति में ग्रेड-वार पाटन और क्षति मार्जिन का निर्धारण करना संभव नहीं है।
- vii. प्रतिवादी हितबद्ध पक्षकारों के इस निवेदन के संबंध में कि आवेदन पत्र में पृथक उत्पादकों की सूचना उपलब्ध होनी चाहिए, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मौजूदा मामले में घरेलू उद्योग अत्यधिक बिखरा हुआ और फैला हुआ है और इसमें अनेक छोटे यूनिट शामिल हैं, ये यूनिट कुटीर उद्योग आधारित हैं और इनको मुख्यतः विशिष्ट पृथक परिवारों द्वारा चलाया जाता है। तदनुसार, ये यूनिट संगठित क्षेत्र में विभिन्न अन्य यूनिटों द्वारा अपनाई जा रही लेखाकरण की विभिन्न पद्धतियों को बनाए रखने की स्थिति में नहीं है और न ही उनके पास ऐसे रिकॉर्ड को रखने के साधन हैं। प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के विभिन्न संघटकों के जाँच के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों की वैधता के लिए प्रयुक्त किए गए कोओ विनिमय के साथ-साथ रीलरों द्वारा बनाकर रखे गए रिकॉर्डों की जाँच की है और उनको वैध माना है।
- viii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए इस मुद्दे के संबंध में कि निर्दिष्ट प्राधिकारी को उद्यमी स्तर पर क्षति की सूचना को ध्यान में रखते हुए क्षति का निर्धारण करने का अधिदेश है, प्राधिकारी की यह धारणा है कि अधिनियम नियमावली में ऐसा कुछ नहीं है जिससे कि क्षति आदि से संबंधित सूचना को उद्यमी स्तर पर भी होना चाहिए। नियमावली में विशेष रूप से "उद्योग को होने वाली क्षति" की जाँच करने का प्रावधान

निहित है। इस परिप्रेक्ष्य में प्राधिकारी “चीन जन.गण. के मूल की और वहां से निर्यातित 20-100 ग्राम के रेशमी फैब्रिक” के मामले में दिनांक 5 दिसंबर, 1911 के अपने अंतिम जाँच परिणाम फा.सं. 15/24/2010-डी जी ए डी का भी हवाला दिया है जिसमें इस आशय का स्पष्ट विचार प्रकट किया गया है कि “ऐसी कोई विशेष विधि नहीं है जोकि उद्योग के लिए एकीकृत सूचना को स्वीकार करना निर्धारित करती हो। इस प्रकार इस जाँच के किसी भी पहलू के प्रयोजनार्थ केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा प्रदान की गई सूचना को स्वीकार करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसलिए प्राधिकारी यह पाते हैं कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा प्रदत्त किसी भी आंकड़े अथवा सूचना को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है।”

- ix. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए इस मुद्दे के संबंध में कि यदि शुल्क लगाए जाते हैं तो पूरे देश में रेशम बुनाई उद्योग बुरी तरह से प्रभावित होगा, प्राधिकारी यह बताते हैं कि पाटनरोधी शुल्क लागू करना किसी भी स्थिति में उपभोक्ताओं के उत्पाद की उपलब्धता को प्रभावित नहीं करेगा। पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापारिक पद्धतियों को समाप्त करके घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को दूर करके बाजार में अधिक प्रभावशाली ढंग से व्यवसाय करने के लिए समानांतर कार्यक्षेत्र का सृजन करना है जोकि देश के सामान्य जनहित में है। इसके अतिरिक्त कम शुल्क लगाने से यह सुनिश्चित होगा कि घरेलू उद्योग को पर्याप्त संरक्षण मिले ताकि उसको होने वाली क्षति को दूर किया जा सके।
- x. हितबद्ध पक्षकारों ने उस अवधि का मुद्दा भी उठाया है जिसके दौरान ऐसी जाँच की गई है। इसके अतिरिक्त हितबद्ध पक्षकारों ने ऐसे घरेलू उत्पादकों के नामों को प्रकट करने का भी मुद्दा उठाया है जिन्होंने अत्यधिक निवेश किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि स्वचालित मशीनों में अनेक रीलरों ने निवेश किया है। ऐसा निवेश जाँच अवधि के साथ-साथ जाँच अवधि के बाद की अवधि में किया गया है। घरेलू उद्योग की अत्यधिक बिखरे और फैले होने की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ही प्राधिकारी ने केवल उसके कुछ यूनिटों का ही दौरान किया है।
- xi. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा इस अनुरोध के संबंध में कि प्रकटन विवरण के पैराग्राफ-50 में किए गए प्रेक्षण में संशोधन इस तथ्य के आधार पर किया जाए, कि विगत दो वर्षों की तुलना में जाँच अवधि (वर्षीकृत) के दौरान संबद्ध वस्तुओं की मांग में गिरावट आई है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि भारत में संबद्ध वस्तुओं की मांग के संबंध में पैरा-50 में की गई जाँच मामले के तथ्यों के अनुसार है। यह नोट किया जाता है कि आधार वर्ष की तुलना में जाँच अवधि में देश में मांग में बड़ी वृद्धि हुई है। जबकि विगत वर्षों की तुलना में जाँच अवधि में मांग के वर्षीकृत मूल्यों में गिरावट आई है, यह गिरावट मामूली है और मांग का सामान्य स्तर कुल मिलाकर वही बना हुआ है।
- xii. प्रकटन विवरण के अनुबंध-4 में अपने प्रेक्षण में संशोधन करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध के संबंध में यह नोट किया जाता है कि यह तथ्य है कि 1 मार्च, 2011 से अनुबंध-3 द्वारा क्षतिरहित कीमतों का निर्धारण करने के लिए नियमावली को संहितायुक्त किया गया है और प्राधिकारी को इस अनुबंध में विनिश्चित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए घरेलू उत्पाद जैसी वस्तु की उचित बिक्री कीमत अथवा क्षतिरहित कीमत का निर्धारण करने की आवश्यकता है। ये नियम लागत के निर्धारित सिद्धांतों पर आधारित हैं जोकि अधिसूचना के पहले से ही प्रचलित हैं। इसलिए ऐसे सिद्धांतों पर विगत निर्णयों का हवाला देने का तात्पर्य यह नहीं है कि अनुबंध-3 में विनिश्चित नियमों का प्राधिकारी द्वारा विगत मामले में क्षतिरहित कीमत का निर्धारण करने के लिए अनुपालन नहीं किया गया। हितबद्ध पक्षकारों का यह तर्क

कि अनुबंध-3 में निर्दिष्ट दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से अनुपालन किया जाए, प्राधिकारी यह पाते हैं कि उक्त अनुबंध में निहित दिशा-निर्देशों को अधिनियम और नियमावली के अन्य प्रावधानों के साथ सुसंगत रूप से पढ़ा जाए। यह तथ्य कि प्राधिकारी को अनुबंध-3 में निहित सभी दिशानिर्देशों और सिद्धांतों का अनुपालन करने के लिए समर्थ बनाने के लिए उच्च स्तर पर सूचना उपलब्ध नहीं है, का तात्पर्य यह नहीं है कि प्राधिकारी को किसी भी मामले में तथ्यों और परिस्थितियों में उपलब्ध बेहतर सूचना का उपयोग करने से विचलित नहीं करता है।

- xiii. जैसा कि प्रकटन विवरण के अनुबंध-4 में विस्तार से दिया गया है, उत्पाद की क्षतिरहित कीमत का निर्धारण अनुबंध-3 में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार किया गया है। वस्तुगत लागत जोकि उत्पादन की कुल लागत का लगभग 80 प्रतिशत बनती है, उसको बेहतर उपयोगिता मानदंडों पर लिया गया है। उत्पादन की लागत के लिए प्रभावित सभी व्यय की पुनरीक्षा की गई है और यह सुनिश्चित किया गया है कि उत्पादन की लागत पर केवल उचित राशि ही प्रभावित की जाए। अनुबंध-3 के पैरा 4 (vii) में विनिश्चित किसी भी व्यय को उत्पादन की लागत में शामिल नहीं किया गया है। उक्त अनुबंध के अनुसार उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी पर कोई उचित प्रतिलाभ नहीं दिया गया है।

निष्कर्ष

90. उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखने के बाद प्राधिकारी का यह निष्कर्ष है कि :
- क. संबद्ध वस्तुओं का निर्यात भारत में संबद्ध देश से इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर भारत में निर्यात किया गया है;
 - ख. घरेलू उद्योग को सामग्रीगत क्षति हुई है;
 - ग. सामग्री की क्षति संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के पाटित आयातों के कारण हुई है;

भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे

91. प्राधिकारी इस तथ्य को मानते हैं कि पाटन रोधी शुल्कों को लगाये जाने से भारत में उत्पाद के कीमत के स्तर पर प्रभावित हो सकता है। तथापि, पाटन रोधी उपाय करने से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके प्रतिकूल पाटन रोधी उपायों करने से पाटन की पद्धतियों द्वारा अनुचित लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया समाप्त होगी, घरेलू उद्योग में होने वाली गिरावट रूकेगी और उपभोक्ताओं की व्यापक पसंद की संबद्ध वस्तुओं की उपलब्धता बढ़ाने में सहायता मिलेगी। उपभोक्ता अभी भी आपूर्ति के दो या उससे अधिक स्रोतों को बनाए रख सकते हैं।
92. प्राधिकारी नोट करते हैं पाटन रोधी शुल्कों का प्रयोजन सामान्यतया पाटन की अनुचित व्यावहारिक पद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है, ताकि भारतीय बाजार में ऐसे खुले और उचित प्रतिस्पर्धा का वातावरण बहाल किया जा सके, जो कि देश के सामान्य हित में हो। पाटन रोधी उपाय करने से किसी भी तरह से संबद्ध देश से आयात प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए इनसे उपभोक्ताओं को उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी।

(ख) सिफारिशें

93. प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस जाँच को शुरू किया गया था और इसे सभी हितबद्ध पक्षकारों को अधिसूचित किया गया था और पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर सकारात्मक सूचना देने के लिए निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को समुचित अवसर दिया गया था। पाटन रोधी नियमावली के संबंध में पाटन, क्षति और उसके कारणात्मक संबंध की जाँच शुरू करने तथा आयोजित करने के बाद और ऐसे पाटित आयातों से घरेलू उद्योग को हुई अत्यधिक क्षति तथा सकारात्मक पाटन मार्जिन स्थापित करने के बाद, प्राधिकारी का यह मत है कि पाटन रोधी शुल्क को पाटन और क्षति को रोकने के लिए लगाया जाना अपेक्षित है। अतः प्राधिकारी इसे आवश्यक समझते हैं कि वह नीचे दिए गए

रूप में और तरीके से संबद्ध देश संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर निश्चयात्मक पाटन रोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की जाये।

94. प्राधिकारी द्वारा अपनाये जा रहे अपेक्षाकृत कम शुल्क के नियम के संबंध में प्राधिकारी पाटन के मार्जिन और हानि के मार्जिन में से जो भी कम है उसके बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को होने वाली हानि को दूर किया जा सके। तदनुसार, नीचे दी गई तालिका के कॉलम 9 में दर्शायी गई राशि के समतुल्य पाटन रोधी शुल्क को संबद्ध देश में उत्पादित अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के सभी आयातों पर केंद्र सरकार द्वारा लगाये जाने की सिफारिश की जाती है।

| शुल्क तालिका | | | | | | | | | |
|--------------|------------|---|-------------------|--|--|---------|----------|------------------------|-------------|
| क्र. स. | शुल्क मद | वस्तुओं का विवरण | विनिर्देशन | उद्गम का देश | निर्यातक देश | उत्पादक | निर्यातक | राशि (अमरीकी डालर में) | माप की इकाई |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1. | 5002 00 10 | 3 क ग्रेड और उससे निम्न स्तर की शहतूती अपरिष्कृत रेशम (मलबरी रॉ सिल्क) (बिना - बटी हुई) | कोई भी विनिर्देशन | चीन जन. गण. | चीन जन. गण. | कोई | कोई | 1.85 | कि.ग्रा. |
| 2. | 5002 00 10 | 3 क ग्रेड और उससे निम्न स्तर की शहतूती अपरिष्कृत रेशम (मलबरी रॉ सिल्क) (बिना - बटी हुई) | कोई भी विनिर्देशन | चीन जन. गण. | चीन जनवादी गण राज्य से अन्य कोई भी देश | कोई | कोई | 1.85 | कि.ग्रा. |
| 3. | 5002 00 10 | 3 क ग्रेड और उससे निम्न स्तर की शहतूती अपरिष्कृत रेशम (मलबरी रॉ सिल्क) (बिना - बटी हुई) | कोई भी विनिर्देशन | चीन जनवादी गण राज्य से अन्य कोई भी देश | चीन जन. गण. | कोई | कोई | 1.85 | कि.ग्रा. |

95. इस अधिसूचना के प्रयोजन से आयातों का पहुंच मूल्य, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अंतर्गत सीमा शुल्क द्वारा यथा निर्धारित मूल्यांकन योग्य मूल्य होगा और उसमें उक्त अधिनियम धाराएं 3, 3क, 8ख, 9 और 9क के अंतर्गत शुल्कों को छोड़कर सभी प्रकार के सीमा शुल्क शामिल होंगे।

96. इस अंतिम जाँच परिणाम से उत्पन्न केंद्र सरकार के विरुद्ध कोई अपील सीमा शुल्क अधिनियम के अनुरूप सीमा शुल्क, उत्पाद और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

ए. के. भल्ला, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

[DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES]

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th December, 2015

(Final Findings)

Subject: Anti-dumping investigation concerning imports of Mulberry Raw Silk (not thrown) of grade 3A and below originating in or exported from China PR.

BACKGROUND

F. No. 14/17/2014-DGAD.—Whereas, Central Silk Board on behalf of the domestic producers/reelers through their below named associations/societies in the States of Karnataka, Tamil Nadu and Andhra Pradesh filed an application, alleging dumping of Mulberry Raw Silk (not thrown) of grade 3A and below (hereinafter also referred to as the "subject goods"), originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the "subject country") and requested for initiation of anti-dumping investigations for levy of anti-dumping duty on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country.

- i. M/s. Silk Reelers Association, Karnataka
- ii. M/s. Ramanagaram Silk reelers welfare association, Ramanagaram (District), Karnataka
- iii. M/s. Kolar Silk Reelers Industrial Co-operative Society Ltd., Kolar District, Karnataka
- iv. M/s. Sidlaghatta Taluk Silk Reelers Association, Sidlaghatta, Karnataka
- v. M/s. Karnatak State Multiend Silk Reelers Welfare Association (Regd.), Ramanagaram, Karnataka
- vi. M/s. Kyalnur Silk Reelers Industrial Co-operative Society, Ltd., Kolar District
- vii. M/s. Dharmapuri District Silk Reelers Association, Kamakshiamman Cross, Dharmapuri
- viii. M/s. Silk Reelers Welfare Association, Reg. No. Cocoon Market, Hindupur, Anathapur District (AP)
- ix. M/s. Dharmavaram Silk Reelers Association, (Society reg. Dharmavaram, Anathapur District, (AP)
2. And whereas, the Authority on the basis of sufficient evidence, submitted by the applicant issued a Notification dated 09th December 2014, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti-dumping investigations concerning imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country, in accordance with sub-Rule 5(5) of the Rules, to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

A. PROCEDURE

3. The procedure described below has been followed by the Authority after issuance of the Notification notifying the initiation of the present investigation:
 - i. The Authority notified the Embassy/Representatives of the subject country in India about the receipt of the anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with sub-rule (5) of Rule 5 supra.
 - ii. The Authority on the basis of sufficient evidence submitted by the applicant on behalf of the domestic industry, issued a public notice dated 09th December, 2014 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating Anti-Dumping investigations concerning imports of the subject goods, originating in or exported from the subject country, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which, if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

- iii. The copy of the Initiation Notification was sent to the known producers/exporters of the subject goods in the subject country, Embassy of the subject country in India, importers/users of the subject goods in India, the domestic producers and other known interested parties requesting them to file response and make their views known in writing in accordance with the Rule 6(2) of the AD Rules.
- iv. The Authority had provided the copies of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters of the subject goods in the subject country and to the Embassy/Representatives of the subject country in India in accordance with Rule 6(3) supra.
- v. A copy of the letter and questionnaire sent to the exporters were also sent to the Embassy/Representatives of the subject country in India, along with the names and addresses of the exporters with the request to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time.
- vi. The initiation notification was sent to the following producers/exporters of the subject goods in the subject country:
 - a) M/s. Zhejiang Silk Import Export Corporation
 - b) M/s. Sichuan Province Silk Import & Export Group
 - c) M/s. Zhejiang Weilai I & E Corporation Limited
 - d) M/s. Jaingsu Haian Cocoon Silk Group Co., Limited
 - e) M/s. Jiangsu Soho International Group Corporation
 - f) M/s. China National Silk Import & Export Corporation
 - g) M/s. Sichuan Dryad Imp. & Exp. Trading Co., Ltd
 - h) M/s. Sichuan Wusheng Antai Silks Company
 - i) M/s. Nanjing Textiles Imp & Exp Corp., Ltd
 - j) M/s. Bazhong Yongyi Cocoon Silk Co., Ltd
 - k) M/s. Zhejiang Tscashmere Co., Ltd
 - l) M/s. Liaoning Silk I & E Corporation
 - m) M/s. Chengdu Tianyou Silk Co. Ltd
 - n) M/s. Chengdu Tianyou Development Co., Ltd.
- vii. None of the producers/exporters from the subject country submitted the questionnaire response.
- viii. Submissions have been made by the China Chamber of Commerce for Imports & Exports of Textiles on behalf of China Silk Industry
- ix. Importers Questionnaire was sent to the following known importers and/or consumers of subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules:
 - a) M/s. Asha Silk Exports
 - b) M/s. Akhil Exports & Imports
 - c) M/s. Bharat Silks
 - d) M/s. Chamundi Textiles (Silk Mills) Ltd
 - e) M/s. Chaitra Prints
 - f) M/s. Dattatreya Silk Exports
 - g) M/s. Ethnic Exports
 - h) M/s. Gajananya Silk Fabrics
 - i) M/s. Harmony Silks Pvt. Ltd
 - j) M/s. J.J. Exporters Ltd
 - k) M/s. Himatsingka Seide Ltd

- l) M/s. Swan Silk Ltd
 - m) M/s. Pathi Prints
 - n) M/s. Shah Silk And Fabrics Pvt. Ltd
 - o) M/s. Elite Inc.
 - p) M/s. Rama textiles(P) Limited
 - q) M/s. Riltika silk & Sarees
 - r) M/s. triveni Sarees
 - s) M/s. B. R. Exporters (India)
 - t) M/s. Chetan Exports
 - u) M.s Classic Creations
 - v) M/s. Alok Exports
 - w) M/s. Jaykey International
 - x) M/s. Shalimar Exports
 - y) M.s Amrita Exports
- X. None of the importers has filed the questionnaire response.
- Xi. The Authority has received representations/submissions from the following Associations on behalf of users/importers:
- a) All India Silk Weavers Federation
 - b) The Mysore Power Loom Silk Manufacturers Co-Operative Society Ltd
 - c) Karnataka State Nekara (Weavers) Sangha (R.)
 - d) Silk Trade Association (Regd.) Varanasi
 - e) The Southern Gujarat Chamber of Commerce & Industry
 - f) Aloka Exports
 - g) Banarasi Vastra Udyog Association
 - h) Pure Silk Weavers Association
 - i) Resham Taga Association, Varanasi
 - j) Federation of Indian Art Silk weaving Industry
- xii. Following interested parties had filed the written submissions:
- a) Central Silk Board (hereinafter referred to as "domestic industry")
 - b) China Chamber of Commerce for Imports & Exports of Textiles (hereinafter referred to as "CCCT")
 - c) Sino Imports & Exports Pvt Ltd
- xiii. The Authority made available non-confidential version of the documents and evidences presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.
- xiv. The Non-injurious Price is calculated based on the cost of production and cost to make and sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry so as to ascertain whether Anti-Dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- xv. Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis was directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

- xvi. On site verification of the information provided by the petitioner were conducted at the premises of the units comprising the Domestic Industry. Such verified information with necessary rectification wherever applicable is relied upon for the purpose of present findings.
- xvii. The Authority held oral hearing on 24th September 2015 to provide an opportunity to the interested parties to present information orally in accordance with Rule 6(6). The interested parties were allowed to present rebuttal arguments/rejoinders on the views/information presented by other interested parties. The Authority has considered submissions received from interested parties appropriately.
- xviii. Investigation was carried out for the period starting from 1st April 2013 to 30th June, 2014 (POI). The examination of trends, in the context of injury analysis, covered the periods April 2010-March 2011, April 2011-March 2012, April 2012-March 2013 and the POI.
- xix. A disclosure statement was issued on 24.11.2015 containing essential facts under consideration of the Designated Authority, which have formed the basis for this Final Finding Notification. A time up to 30.11.2015 was given to furnish comments, if any, on Disclosure Statement. The Authority has considered post disclosure comments received from interested parties appropriately.
- xx. Transaction-wise imports data has been procured from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) for the periods April 2010-March 2011, April 2011-March 2012, April 2012-March 2013 and the POI and has been relied upon for the analysis in present SSR investigation.
- xxi. ***In this Final Finding represents information furnished by an interested party on confidential basis, and so considered by the Authority under the Rules.
- xxii. The exchange rate adopted for the POI is 1 US\$ = Rs. 60.87

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND DOMESTIC LIKE ARTICLE

4. The product under consideration in the present investigation is Mulberry Raw Silk (not thrown) of 3A grade and below, originating in or exported from China PR. The silk is obtained from the cocoons of the larvae of the mulberry silkworm *Bombyx mori* reared in captivity (sericulture).
5. Product under Consideration is classified under the heading “Silk” in Chapter 50 and further under 5002 00. The classification at 8-digit level is 5002 00 10. However, the subject goods are also been imported under different customs classifications such as 5002 0010, 5002 00 20, 5002 00 30 etc. The classification is only indicative and in no way binding on the scope of the present investigation.

Submissions made by producers/exporters/importers/other interested parties

6. Indian standards of all grades in all aspects are much lower than standard manual of Raw Silk Testing & Classification of the ISA 1968, on which Indian Customs generally relies for retest. China PR has been implementing the mandatory national standards on raw silk since 1979 and the current version is GB/T 1797-2008. When compared to Indian standards, all Chinese standards of raw silk above 3A grade are much higher than Indian 3A grade. Therefore, the Designated Authority may kindly issue a specific clarification that raw silk above 3A grade is outside the purview of the present investigation.

Submissions by the domestic industry

7. The subject goods, which are being dumped into India, are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no differences either in the technical specifications, functions or end-uses of the dumped imports and the domestically produced subject goods. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as ‘like articles’ under the Anti-dumping Rules.
8. Domestic industry has submitted that it is settled position in anti-dumping jurisprudence that quality does not matter and cannot be a basis to seek any exclusion from the product under consideration as long as the imported products are “like article”, they can be covered within the product scope. Further, domestic industry has submitted that the definition of the “product under consideration” in the initiation notification has not been challenged before any writ court by CCCT and, therefore, the remedy that is sought without seeking appropriate redressal before a proper forum cannot be provided by the Designated Authority specifically when as per anti-dumping jurisprudence, quality is not a factor to change the product scope.

Examination by the Authority

9. The product under consideration in the present investigation is “Mulberry Raw Silk (not thrown) of 3A grade and below”, originating in or exported from China PR.

10. The silk is obtained from the cocoons of the larvae of the mulberry silkworm *Bombyx mori* reared in captivity (sericulture). The silk is a protein fibre composed mainly of fibroin and produced by the insect larvae to form cocoons. The shimmering appearance of silk is due to the triangular prism-like structure of the silk fibre, which allows silk cloth to refract incoming light at different angles, thus producing different colours. Silks are also produced by several other insects, but generally only the silk of moth caterpillars has been used for textile manufacturing.
11. With regard to like article, Rule 2(d) of the AD Rules provides as under: -

"like article " means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;
12. The submissions made by the interested parties with regard to the scope of PUC and like article and considered relevant by the Authority are examined and addressed as follows:
 - i. The petitioner has claimed that there is no known difference in the subject goods produced by the domestic industry and that imported from the subject country. The subject goods produced by the domestic industry and the subject goods imported from the subject country are comparable in terms of characteristics such as technical characteristics, manufacturing process and technology, functions and uses, product specifications, distribution and market and tariff classification of the goods. Examination of the product and import data submitted by the applicant and the respondent exporters indicates that there is no difference between subject goods produced by the Domestic Industry and imported from the subject country. In view of the similarity in manufacturing process and substitutability, the Authority holds that the two are required to be treated as like product for the purpose of defining the 'product under consideration' in this case.
 - ii. With regard to the request of the interested parties to issue a specific clarification that raw silk above 3A grade is outside the purview of the present investigation, the Authority notes that Mulberry Raw Silk (not thrown) of grade above 3A is outside the purview of the product scope of the current investigation as is apparent from the initiation notification itself.

C. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

Submissions made by producers/exporters/importers/other interested parties

13. Central Silk Board (CSB) is a statutory body established as per Central Silk Board Act, 1948 under the administrative control of the Ministry of Textiles. It is argued that according to relevant rules, no authorization can be given to the CSB to represent domestic industry in trade remedy investigations. In addition, it also cannot represent the Government of India in this case as according to the definition of "interested party" provided under Rule 2(c) of the AD Rules, the government of an importing country is not envisaged to be an interested party.
14. A proper list containing the names and addresses of the Applicant association and its members should have been provided in the petition. A number of associations have only provided handwritten list of its members, without actually providing certain critical information about its members.
15. Interested parties have submitted that in the petition, the Applicant holds a share of 57% in total domestic production in India. However, the statistics provided by the Applicant itself in the Annual Reports show a different picture.

Submissions by the domestic industry

16. Domestic industry has submitted that Central Silk Board is an independent body in India which has been formed by way of a separate legislation, i.e., Central Silk Board Act, 1948 to regulate, develop and augment the activity of the silk in the country. It is the nodal agency in the country which is responsible for not only the development and growth of the silk sector but also to compile and record the necessary statistics relating to the silk sector. Therefore, in order to promote the development of the silk industry Central Silk Board has coordinated the process of filing of the application. It is the duty of the Central Silk Board to promote the development of the silk industry by such measures as it thinks fit. Domestic industry has also filed the relevant pages from the Central Silk Board Act, 1948, to substantiate their claim in this context.
17. It has also submitted that Rule 5(1) permits filing of the application by or on behalf of the domestic industry. There is no bar under the Rules as to which authority has the power to file the application for and on behalf of the domestic industry. Reading of the said Rule in the manner proposed by CCCCT would result in interpreting Rule 5(1) being available only to non-government organizations as authorized agents of defined domestic industry. Such an interpretation goes against the settled principles of statutory interpretation. The domestic industry has also submitted that Central Silk Board has been considered as the domestic industry in various previous investigations relating to the silk industry by the Hon'ble Authority.

18. Domestic industry has submitted that the members of one association are not the member of other association and all the members of these associations are the manufacturer/producers of the product concerned. Domestic industry has invited the attention of the Authority to the fact that the CCCT (one of the so-called interested party) on the one hand is requesting proper list of members of the association on the ground that some associations have provided handwritten list of its members. However, on the other hand it has not provided the list of its members along with their production details to substantiate their eligibility as an interested party in terms of Rule 2 (c) to this investigation despite specific request made by the domestic industry during the public hearing. The domestic industry has also submitted that the applicant domestic producers have neither imported the subject goods nor they are related to the exporters or the importers of the subject goods from the subject country and necessary declaration are already enclosed as Annexure 7 with the application. Further, domestic industry has submitted that the interested parties had raised the issue of providing the names of some of the members in vernacular languages by the domestic industry just to derail the proceedings. In this context, domestic industry has invited the attention of the Authority to the fact that the CCCT has enclosed Exhibit 3 in their written submissions dated 06th October, 2015. The Exhibit 3 is in the context of the Chinese standards of Mulberry Raw Silk which is in the local language i.e. Chinese. CCCT has not provided the translated English version of the same. Thereof, CCCT is following double standards as far as the issue of the language of certain documents is concerned.
19. The production reported in the Annual Report includes other products as well which are outside the scope of the present investigation. Therefore, statistics provided by the Applicant in the Annual Reports cannot be used in this investigation, as the scope of product of which the production figures is reported in the Annual report is much wider than the product scope of the present investigation.

EXAMINATION BY THE AUTHORITY

20. Rule 2(b) of the AD Rules defines domestic industry as under: -

“domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”.

21. The application in the present investigation has been filed by Central Silk Board on behalf of the domestic industry. As claimed by the applicant, it is an independent body in India which has been formed by way of a separate legislation i.e., Central Silk Board Act, 1948 to regulate, develop and augment the activity of the silk in the country. It is the nodal agency in the country which is responsible for not only the development and growth of the silk sector but also to compile and record the necessary statistics relating to the silk sector. Therefore, in order to promote the development of the silk industry Central Silk Board has coordinated the process of filing of the application. It is the duty of the Central Silk Board to promote the development of the silk industry by such measures as it thinks fit.
22. The applicant has also submitted that Rule 5(1) permits filing of the application by or on behalf of the domestic industry.
23. Rule 5(1) of the AD Rules are as under: -
- “5. Initiation of investigation - (1) Except as provided in sub-rule (4), the designated authority shall initiate an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping only upon receipt of a written application by or on behalf of the domestic industry.”*
24. The Authority notes that Rule 5(1) of the AD Rules does not specify the Authorities who can file the application on behalf of the domestic industry. Further, Rule 5(1) does not restrict the Government of the importing country from filing an application on behalf of the domestic industry. Therefore, Authority holds that CSB is fully eligible and competent to file the application on behalf of the domestic industry.
25. As regards the issue raised by the interested parties that on page number 7 of the petition domestic industry has stated that the Applicant holds a share of 57% in total domestic production in India while the statistics provided by the Applicant itself in the Annual Reports show a different picture, the Authority notes that the Annual Report covers various products while the product scope of this investigation is restricted to Mulberry Raw Silk (not thrown) of grade 3A and below.

D. CONFIDENTIALITY

Submissions made by producers/exporters/importers/other interested parties

26. Various submissions made by the producers/exporters/importers/other interested parties with regard to confidentiality and considered relevant by the Authority are as follows:

- i. The petition suffers from excessive confidentiality. Applicant has claimed confidentiality on various information like Part VI costing, Depreciation, Interest cost etc.
- ii. Rule 2(b) requires that each of the participating domestic producers provides its data relating to the subject product. The Applicant does not have information with respect to all such individual producers and hence cannot be in a position to file the petition on their behalf.
- iii. Applicant has not produced any evidence regarding the actual quantities produced by each of the domestic producers.

Submissions made by the domestic industry

27. With regard to the issues of confidentiality, the domestic industry has submitted that domestic industry has filed the application in accordance with the AD Rules and the prescribed formats. It is further submitted that the domestic industry has claimed confidentiality on their business sensitive information with adequate reasons in accordance with the legal provisions and the guidelines being followed by the Authority.
28. As regards issue of providing the information of the individual producers along with the evidences, domestic industry has submitted that in the present case domestic industry is highly fragmented and scattered, comprising of thousands of tiny units. These units are cottage based industry and are run predominantly by individual families. Accordingly, these units are in no position to maintain or keep the various accounts and follow the accounting procedures as followed by various other units in the organized sector nor do they have the resources to maintain such records. Further, it is submitted that in view of the limited and small operations of the domestic industry, it is not possible for the individual units to submit the information in the form and manner regarding the various injury parameters as normally required to be submitted by an industry in the organized sector. In view thereof, production of the domestic industry has been calculated based on the information provided by the various associations whose members are involved in the production/manufacture of the product concerned. The information received by various associations for production has been enclosed as Annexure 6 of the application. Moreover, the domestic industry has also provided to the Authority cost and price information duly substantiated with evidences.

Examination by the Authority

29. The various submissions made by the interested parties with regard to confidentiality and considered relevant by the Authority have been examined. Rule 7 of Anti-dumping Rules provides as follows:-

Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules and (7) of rule 6, sub-rule (2), (3) (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.

(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information.

30. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted and such information has been considered confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis was directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis. The Authority made available the non-confidential version of the evidences submitted by various interested parties in the form of public file.
31. With regard to the submission of the opposite interested parties that the applicant should make available information of the individual producers, the Authority notes that in the present case domestic industry is highly fragmented and scattered, comprising of thousands of tiny units. These units are cottage based industry and are run predominantly by individual families. Accordingly, these units are in no position to maintain or keep the various accounts as followed by various other units in the organized sector nor do they have the resources to

maintain such records. The Authority has, however, validated the Authenticity of the data during the verification visit of the domestic industry.

32. The Authority further holds that there is nothing in the scheme of the Act and the Rules which mandates that the information regarding injury etc. has to be at the enterprise level. The rules specifically provide for examination of the “state of the industry”. In this context, the Authority also refers to its Final Findings F. No. 15/24/2010-DGAD dated 05th December, 2011 in case of "Silk Fabrics 20-100 gms per meter originating in or exported from China PR" wherein a clear view had been taken that *“there is no specific of law which proscribes the acceptance of aggregated information for the industry as such. Thus, there is no bar in accepting information provided by the Central Silk Board for the purpose of any aspect of these investigations. Therefore, the Authority finds no reason to reject any data or information provided by the CSB”*.

E. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

Submissions made by producers/exporters/importers/other interested parties

33. The miscellaneous submissions made by producers/exporters/importers/other interested parties and considered relevant by the Authority are as follows:
- i. CCCT has submitted that it is in fact the largest textile and apparel trade association both in China PR and the world. They have several functional departments and branches that deal, inter alia, with textiles, silk, garments etc. In light of the above submissions, CCCT is qualified to be an interested party under Rule 2(c) of the AD Rules. Further, it has submitted that it is registered as an interested party with the Designated Authority with minor delay.
 - ii. Import statistics should be provided to interested parties in soft copy, preferably in Microsoft Excel format so that the same can be examined in an intelligible manner. Interested parties require the information on the basis on which raw data is sought by the Designated Authority or the domestic industry from DGCI&S or other private agencies, the raw transaction-wise data as provided by the DGCI&S/private agency, the methodology followed to refine the raw transaction-wise data and the refined data and its summary.
 - iii. The format of application prescribed by the Designated Authority requires the disclosure of information about the subject goods including the size, quality, category, type, range, models, etc. The Applicant could have collected this information from producers in India and provided the same in the petition.
 - iv. Interested parties had requested the Authority to direct the Applicant to provide a copy of such standard manual that has been relied upon in the petition.
 - v. Imports of 3A grade from China PR are not affecting the domestic industry. Imports are primarily supplementing the demand in Indian market which could not be met by the domestic industry, which is already operating at optimal capacity utilization. The power loom industry has to import bivoltine category from China PR mainly due to the non-availability of bivoltine category of raw silk with the Indian domestic producers. Respondent requests the Designated Authority to separate different grades for apple-to-apple comparison for not only grades 2A and 3A, but also for sub-grades – bivoltine and multivoltine under grades 2A and 3A, respectively and thereafter make dumping and injury determination accordingly during the investigation process.
 - vi. Sub-para (iii) of para (4) of Annexure III to the AD Rules requires the Designated Authority to consider the best capacity utilization over the past three years and the period of investigation, while arriving at the non-injurious price.
 - vii. The exchange rate for USD that has been adopted by domestic industry as INR 60.98. However, the prevailing rate of USD, as per the RBI, is currently INR 65.39. It is also predicted that the Rupee will not appreciate once again and may get depreciated further. This means that imports into India currently are priced significantly higher than what they used to be during the POI. It is important that prevailing exchange rate is considered for an accurate picture of the level of price undercutting and price underselling, if any in this case.
 - viii. The Applicant is alleging that the subject product is being dumped from China PR, and China PR has been treated as a non-market economy country by various authorities world over and in recent cases China PR has been treated as non-market economy country in India also. It is also alleged that Chinese producers/exporters in the present case cannot be granted market economy status in view of the fact that the silk production and trade is admittedly not free from state interference. For this purpose, the Applicant provided the Protocol on Accession of People’s Republic of China and Articles of Association of China Cocoon & Silk Exchange to support its claim. Cocoon is a kind of scarce resource and produced by a much fragmented, ill-equipped and financially

unsecured industrial sector in any country. In order to protect the basic survival right of the cocoon farmers, who are still in the position as disadvantaged group in China PR, the government has to undertake measures to balance the price of cocoon, which also is of significance to the stability of the society and the economic development of disadvantaged territories of China PR.

- ix. Designated Authority is mandated to arrive at normal value in cases of exports from non-market economy countries such as China PR in this case, by first exhausting the main options of using the price or constructed value in a market economy third country or the price from such a third country to other countries including India. Only when the first two options have been exhausted, the Designated Authority may apply any other reasonable basis to arrive at the normal value including prices paid or payable in India giving due account to reasonable adjustments. However, in the present petition, Applicant only claimed to take third option.
- X. The Applicant did not provide any positive evidence or the basis on which certain costs were adopted, thus, it is in the violation of Article 5.3 of the WTO ADA for the accuracy and adequacy of the evidence.
- xi. There are more than 6 to 8 lakh power loom weavers whose livelihood is at stake. If the duties are levied, then all the 6 to 8 lakh power loom weavers will have to face starvation and death. The domestic industry has never supplied them raw silk of required quantity and quality. The domestic industry has been supplying principally to handloom weavers and power loom weavers were not their market. In this case, if the duties are levied, at least duty on goods imported for the purpose of using in power looms shall be exempt. Such an end-use exemption will not affect the domestic industry as they can continue to sell their raw silk to their existing markets i.e., handloom weavers.
- xii. The Weavers' Associations, who are importers and users, have submitted that they are rather surprised that the Central Silk Board has made an application to the Anti-dumping authorities in Delhi requesting them to levy Anti-dumping duty on raw silk yarn of 3A grade imported from China. If this is implemented, it will lead to a catastrophe for the silk weaving industry.
- xiii. The domestic producers have already been provided adequate protection on the subject product for more than 10 years pursuant to earlier anti-dumping investigations. In addition, the Ministry of Finance has increased customs duty on raw silk from 5% to 15% via Notification No.12/2013-Customs dated 1 March 2013. Despite such adequate protection, the domestic industry is deceptively claiming to have suffered material injury caused by alleged dumped imports from China PR in the present case without any supporting data.
- xiv. The silk weavers require bulk quantity of uniform quality of 2A and above grade silk for their production of quality fabrics which is not being produced indigenously in bulk.
- xv. The Weavers have submitted that India imports bivoltine silk yarn from China which Indian Industry has not been able to produce indigenously, in satisfactory quality or quantity, despite sustained support for several decades.

Submissions made by the domestic industry

34. The miscellaneous submissions made by the domestic industry and considered relevant by the Authority are as follows:

- i. Domestic industry has submitted that CCCT can be represented before the Designated Authority only when they establish before the Designated Authority that they are an interested party in terms of Rule 2(c). Once they are in a position to establish that they are an interested party, only then they participate in the investigation process. There is no dispute that CCCT is not falling under the category of a Producer, Exporter or an Importer. It may therefore, claim the status of a business Association under Rule 2(c). It may be seen from the above that only those Associations can be considered as "interested party" the majority of the members of which are producers, exporters or importers of "such an article". It is pertinent to note that the majority test is to be applied in the context of total membership of the CCCT for such an article i.e., Mulberry Raw Silk. However, CCCT has not disclosed by way of any communication that they are a business association and their majority of the members are producers, exporters or importers of product under consideration and has also not even provided the list of their members along with their respective activities for the Designated Authority to reach any determination in terms of Rule 2(c). On the contrary, CCCT has categorically mentioned in their submissions dated 07th April, 2015 that they are engaged in textile trade business. In the absence of such substantiation, they cannot be considered as an interested party in terms of Rule 2(c) of the Rules. Therefore, domestic industry has prayed that

the Designated Authority may decline to treat CCCT as an interested party and consequently may reject all submissions advanced by CCCT.

- ii. The Authority had granted to all the interested parties 40 days from the date of publication of initiation Notification i.e., till 18th January, 2015 to file the questionnaire response and also to offer the comment on the domestic industry's application. However, despite the specific timeline prescribed by the Authority CCCT has filed their submissions much beyond the due date i.e., on 7th April, 2015 and 3rd June, 2015. Further, no request for condonation of delay has been filed with the Authority. Therefore, domestic industry has requested the Authority not to accept the belated submissions filed by CCCT on the application of the domestic industry.
- iii. Further, despite the specific timeline prescribed by the Authority, All India Silk Weaver's Federation and Sino Imports & Exports Pvt. Ltd have not filed the comment on the domestic industry's application within the timeline prescribed by the Authority. Further, it has also submitted that Sino Imports & Exports Pvt. Ltd had withheld material information necessary for the Designated Authority to arrive at proper conclusions in the present investigation by not filing the mandatory questionnaire response. In view thereof, the Domestic Industry requested the Authority not to accept the submissions filed by All India Silk Weaver's Federation and Sino Imports & Exports Pvt. Ltd.
- iv. Transaction wise raw import data has been enclosed as Annexure 1 to the application filed with the Authority. The import data has been provided in the same format in which the import data has been accepted by the Authority in other cases and import data for the subject goods has been sorted based on the description given in each transaction of the import data.
- v. The domestic industry is involved in the production/manufacture of all types, grades etc of the subject goods like grade 2A, grade 3A, bivoltine type, multivoltine type of raw silk etc. The domestic industry has also substantiated the same to the Authority during the verification visit of the constituents of domestic industry.
- vi. As regards the request of the CCCT for the copy of the standard manual, the domestic industry has submitted that the request made by CCCT is evidently to somehow create an issue that can impede the investigation process. From the submissions made by them it is evident that they are not only aware of the ISA standards and other related international norms in this trade but also filed copies of the same before the Designated Authority.
- vii. With regard to the request of the interest parties for grade wise dumping and injury margin, the domestic industry has submitted that none of the exporters from the subject country has filed the questionnaire response. Therefore, non-cooperation by the interested parties is in fact an attempt to impede the investigation as even the exporter-wise export details have not been made available to the Authority. In the absence of such material information from any of the interested parties, the request cannot be considered. In any case, the various grades are commercially substitutable as the price variation between various grades upto 3A is very insignificant.
- viii. As regards the request of the interested parties to calculate the NIP in terms of Annexure III, the domestic industry has submitted that that the nature of the domestic industry in this investigation is very peculiar in nature. The domestic industry is highly fragmented and scattered, comprising of thousands of tiny units. These units are cottage based industry and are run predominantly by individual families. Therefore, domestic industry has made all possible efforts to provide the best available information for the purpose of the calculation of the NIP. Further, it has also submitted that there is no provision under the present law which mandates that the investigation can be undertaken only for those who maintain the records in a particular manner. The Act and the Rules also do not exclude small farmers, artisans, craftsmen etc. from the protection or remedial action through invocation of anti-dumping law.
- ix. The domestic industry has submitted that adopting the exchange rate of the POI for calculating Normal Value, Non-injurious Price etc. is the standard practice being followed by the anti-dumping Authorities that are based on sound economic and accounting rationale and logic. This practice is being followed consistently by the Authority in all cases. Further, the contention of the interested parties is based on conjecture about the future exchange rates and, hence, without any merit. Considering the standard practice of the Authority, the same has been adopted by the domestic industry for the purpose of calculating Export Price, Normal Value etc. Moreover, the interested parties have not pointed out any legal or logical infirmity in the said approach.
- x. It has been submitted that China is treated as a non-market economy country by various authorities world over and in recent cases China has been treated as non-market economy country in India

also. Therefore, the normal value for China is required to be determined as per the procedure described in Para 7 of the Annexure I to the Anti-dumping Rules. Further, it is submitted that Chinese producers/exporters in the present case cannot be granted market economy status in view of the fact that the silk production and trade is admittedly not free from State interference. Since the fact of State interference is admitted, the question of granting MET to any of the exporters/producers, does not arise. In order to substantiate our claim Protocol on Accession of People's Republic of China wherein China has admitted state control over the silk cocoon prices has been enclosed as Annexure 8A to the application.

- xi. The domestic industry has submitted that it has provided all evidences to support the cost and price data submitted to the Authority. However, the domestic industry has claimed confidentiality on such information/documents in terms of the rules of confidentiality.
- xii. The domestic industry has submitted that the contention raised by the interested parties that the domestic industry has been supplying principally to handloom weavers is wrong. It is a misrepresentation of facts to say that Chinese silk is used only on power looms whereas the Indian silk is used only on handlooms. The interested parties had made a hollow claim without providing any supporting evidence. The Indian raw silk used in many power loom clusters of the country. Thus, both imported and domestic raw silk yarn are indeed like products that can be interchanged depending upon the price. As regards the submissions of the interested parties that if the duties are levied then all the 6 to 8 lakh power loom weavers will have to face starvation and death, it is submitted that the objective of the anti dumping duties is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Its objective is basically to create a level playing field for the domestic industry to compete more effectively in the market. The imposition of anti dumping, therefore, would not affect the availability of the product to the consumers.
- xiii. It has submitted that the basis for levying the anti-dumping duty is discriminatory pricing behaviour of the exporter of the subject goods from the subject country. The fact that Authority has given the protection for more than 10 year does not ensure that the exporter from the subject country has mended his discriminatory pricing behaviour. In fact, the significant dumping and injury margin calculated based on the low value dumped prices from the subject country proves that despite protection from the Authority for more than 10 years the exporters from the subject country have not mended their discriminatory pricing behaviour. As regards the submission of the interested parties regarding increase in the customs duty from 5% to 15%, it is submitted that interested parties has not brought on record the fact that initially the customs duty was 30% which was reduced to 5% and then increased to 15%.
- xiv. The contention raised by the interest parties that the raw silk of grade 2A and above is not being produced indigenously in bulk is wrong. Interested parties have just made a guess and hollow claim. In order to substantiate their claim that domestic industry produces grade 2A and above sample copies of the test certificate issued by Silk Conditioning and Testing House (SCTH) certifying the quality/grade of the product concerned has been provide to the Authority.

EXAMINATION BY THE AUTHORITY

35. Various issues raised by the interested parties and the domestic industry considered relevant by the Authority are examined herein below:

- i. As regards the contention of some interested parties regarding the exchange rate used for the calculation of normal value etc., the Authority has considered the exchange rate for the Period of Investigation only, which is in accordance with the consistent practice followed by the Authority.
- ii. With regard to the issue raised by the interested parties that if the duties are levied, then all the 6 to 8 lakh power loom weavers will have to face starvation and death, the Authority states that the imposition of anti-dumping does not, in any case, affect the availability of the product to the consumers. The objective of the anti-dumping duties is to create a level playing field for the domestic industry to compete more effectively in the market by eliminating injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping in the general interest of the country. Further, the application of the lesser duty rule ensures that the Domestic Industry gets the protection that is sufficient to remove the injury.
- iii. As regards the issue raised by the interest parties that adequate protection has already been provided to the domestic producers, the Authority notes that the anti-dumping protection is granted to the domestic industry so as to protect them from the discriminatory price behaviour of the exporter

from the subject country causing injury to the Domestic Industry. Protection provided to the domestic industry in previous years is not a relevant factor in respect of the decision whether to levy Anti-dumping duties or not in the present scenario.

- iv. The interested parties have raised an issue that the silk weavers require bulk quantity of uniform quality of 2A and above grade silk for their production of quality fabrics which is not being produced indigenously in bulk. The Authority notes that the interested parties have not provided any evidence in support of their submissions. In any case, it was noticed during the verification that the domestic producers are indeed manufacturing silk of 2A and above grades in sufficient quantities. Further, significant investments have also been made in the new automated machines which will ensure manufacture of the uniform quality of silk of 2A grade and above of both bivoltine and multivoltine varieties, in sufficient quantities.
- v. As regards to the issue raised by the interested parties for the application of Annexure III to determine the NIP and the basis on which certain costs were adopted, the Authority notes that the provisions of Annexure III cannot be read in a manner so as to dilute the powers of the Authority to resort to the best information. It is well recognized that the nature of the domestic industry in this investigation is very peculiar and distinct from the typical organized Domestic Industry. The domestic industry is highly fragmented and scattered, comprising of hundreds of tiny units. These units are cottage based industry and are run predominantly by individual families. While recognizing that there is no specific requirement in law to compute the NIP only on the basis of enterprise-specific information, the Authority has nevertheless validated the accuracy of the information provided by the domestic industry in their application during the verification visit of the constituent units. It is this validated information that has formed the basis for the calculation of the NIP.
- vi. With regard to the request of the interested parties to calculate the grade wise dumping and injury margin, it is noted that the exporters from the subject country have not filed the questionnaire response and have not given material information necessarily required for the calculation of the dumping margin. In the absence of the relevant information, it is not possible to determine grade wise dumping and injury margin.
- vii. With regard to the issue of import data, the Authority notes that the non-Confidential version of the DGCI&S import data was made available in the public file.

METHODOLOGY AND DETERMINATION OF DUMPING AND DUMPING MARGINGS

F. Normal Value

36. Under section 9A (1) (c) normal value in relation to an article means:
 - (i) The comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article, when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6), or
 - (ii) When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either
 - (a) comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or
 - (b) the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6);
37. None of the exporters from China PR has filed the questionnaire response. Also none of the exporters have filed response to NMET Questionnaire.
38. China has been treated as a non-market economy country by various authorities world over and in recent cases China has been treated as non-market economy country in India also. Therefore, the normal value for China is required to be determined as per the procedure described in Para 7 of the Annexure I to the Anti-dumping Rules. For the ready reference the provisions of Para 7 are quoted below:

“7. In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a

reasonable manner keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Account shall also be taken within time limits, where appropriate, of the investigation if any made in similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.”

39. Since China is being considered as Non Market Economy, the Rules provide that the normal value for China is required to be determined based on domestic selling prices in a market economy third country or the constructed value in a market economy third country or the export prices from such a third country to any other country including India. However, if the normal value cannot be determined on the basis of the alternatives mentioned above, the Designated Authority may determine the normal value on any other reasonable basis including the price actually paid or payable in India for the like product duly adjusted to include reasonable profit margin.
40. In the absence of any price and cost details for the subject goods in any market economy third country and the fact noted that none of the exporters/producers has filed the questionnaire response and claimed market economy treatment in terms of Paragraph 8(3) of Annexure 1 to the Anti-dumping Rules, the Designated Authority is left with no alternative in the current case but to determine normal value estimated on the basis of price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, to include a reasonable profit margin. However, the Authority has adopted international rates of cocoon for POI as published by China Cocoon and Silk exchange.
41. Based on the information made available by the domestic industry and other information available with the Authority, the normal value for the subject goods has been constructed as below for all producers/exporters from China PR.

| | | |
|--|-----------------|------------------|
| Normal value for all producers/exporters from China PR | Rs. 3619 per KG | USD 59.45 per KG |
|--|-----------------|------------------|

Export price for Producers/Exporters from China

42. The Authority notes that none of the exporters from the subject country has filed the questionnaire response. Therefore, Authority has determined the export price for all producers and exporters from the subject country on the basis of the best facts available in terms of Rule 6(8) of the Anti-dumping Rules after adjusting for Ocean Freight, Marine Insurance, Commission, Bank Charges, Port Handling Expenses and Inland Freight Expenses. The net export price so determined is as below:

| | | |
|--|-----------------|-----------------|
| Export price for all producers/exporters from China PR | Rs. 2669 per KG | USD 43.85per KG |
|--|-----------------|-----------------|

Dumping Margin

43. Considering the normal value and export price for subject goods, the Authority has determined the dumping margin for the subject goods for the exporters from China PR, as follows:

| Particulars | Normal Value | Ex-factory price | Dumping margin | Dumping margin (%) | Dumping margin (Range %) |
|-------------|--------------|------------------|----------------|--------------------|--------------------------|
| Rs/KG | 3619 | 2669 | 949 | 35.57 | 30-40 |
| USD/KG | 59.45 | 43.85 | 15.60 | 35.57 | 30-40 |

It is seen that the dumping margin for the subject goods is more than de-minimus and significant.

G. INJURY DETERMINATION**Submissions made by the producers/exporters/importers/other interested parties**

44. The following are the injury related submissions made by the producers/exporters/importers/other interested parties:

- vi. It may be seen from the updated petition that there is neither any absolute nor relative increase in imports of subject goods. Imports of subject product were never significant in the last 4 years so as to command the Indian market. Production, sales as well as capacity utilization of Indian domestic producers increased. There is no link between the subject imports and profitability of the domestic industry. Thus, it is incorrect to state that Indian domestic producers suffered injury during the said POI.
- vii. Landed value of imports from China PR increased consistently throughout the injury analysis period. The domestic selling price also significantly increased in line with the increase in landed value during the same period. Therefore, it is submitted that there is no possibility of a positive undercutting in the present case. The Chinese imported silk is being sold indigenously at Rs 3250-3400 based on quality. This rate when compared to indigenous silk is higher by Rs. 1000 per kg. Hence, there is no dumping.
- viii. The average prices, import prices from other countries were much lower than import prices from China PR throughout the injury period. Therefore, price influence from other countries cannot be neglected.
- ix. The loss of market share by domestic industry is not due to the imports from the subject country but because of the poor export performance of its downstream goods.
- x. The imports of mulberry silk during the year 2014-15 up to July 2015 was around 1139 MT compared to 1166 MT imported during the corresponding period of the previous year. Thus, it clearly indicated that even though anti-dumping duty was not in force from January 2014 the import has not shown an increasing trend.

Submissions made by the domestic industry

45. The following are the injury related submissions made by the domestic industry:

- i. Share of the imports from the subject country in the total imports is as high as 97.14% during the period of investigation. It may also be seen that imports from subject country has increased significantly from 100 (Indexed) in the base year to 199 (Indexed) during the period of investigation.
- ii. Domestic industry has submitted that share of the subject country in the total Indian demand was only 8.53% during the base year. However, the share of subject country in total Indian demand in India has increased to 14.02% in the POI.
- iii. Share of imports from the subject country in the production has increased significantly from 17.9% in the base year to 28.5% in the POI.
- iv. Cost of the domestic industry has increased substantially in the POI as compared to base year as well as preceding years. Unfortunately, the Domestic Industry has not been able to increase the selling price commensurate with the increase in the cost due to low value dumped imports from the subject country. Accordingly, it is clear that dumped imports from the subject country have suppressed the prices of the domestic industry.
- v. With regard to the submission of the interested parties that the domestic selling price increased in line with the increase in landed value during the same period and there is no possibility of a positive undercutting, domestic industry has submitted that based on the index numbers provided in the application interested parties have argued that the landed value is much higher than the domestic selling price during the POI and there is no price suppression or depression. Further, domestic industry has submitted that sometime index no may not lead to right conclusion. The same situation persists in this case where the domestic selling price (134 - Indexed) is much higher than the landed value (142 - Indexed) during the POI. However, comparison of the index numbers of domestic selling price and the landed value/price gives a contrary impression. Furthermore, domestic industry has submitted that the positive price undercutting as provided in Annexure 11 of the application proves without any doubt that the domestic selling prices of the subject goods is higher than the landed value from the subject country.

- vi. The Domestic industry has submitted that the imports of subject goods from sources other than subject country are *de minimis* during the period of investigation. Thus, based on the available data, it is amply clear that the real cause of the injury to the domestic industry is the dumped imports from the subject country.
- vii. The real cause of injury is low value dumped imports from the subject country. The domestic industry is not able to increase the domestic selling price commensurate with the increase in the cost due to low value dumped imports from the subject country. Moreover, the imports volume of the subject goods from the subject country almost doubled in the POI as compared to the base year. As a result, the performance of the domestic industry has deteriorated significantly. The reason attributed by interested parties is therefore without logic and substantiation.
- viii. The contention raised by the interested parties that during the year 2014-15 the imports have not shown an increasing trend vis-à-vis imports during the corresponding period of the previous year, is without any merit. Interested parties have not provided the import data to substantiate their claim. Further, even the source of the import data for the year 2014-15 has not been provided. In view of the above, the Domestic Industry is unable to offer any meaningful comments on the same.
- ix. The profitability of the domestic industry sharply and materially declined due to dumping from subject country due to dumped imports from the subject country.
- x. Return on investments has declined sharply. The current level of ROI is much less than the desirable and legitimate levels which should have been achieved by the domestic industry in the absence of dumped imports.
- xi. The dumping margin from subject country is not only more than de-minimis levels but is very significant.
- xii. The domestic industry has suffered material injury due to dumped imports of the subject goods from the subject country.
- xiii. Presence of import at very low prices preventing domestic industry to increase their price to the extent of increase in input cost resulting into suppression of the selling prices of the domestic industry.
- xiv. Reduction in profits directly resulted in deterioration in return on capital employed and cash profits. The domestic industry has not been able to cover the cost of capital. Thus, deterioration in profits, return on capital employed and also cash flow and cash profit is directly due to dumped imports.

Examination by the Authority

- 46. Article 3.1 of the WTO Agreement and Annexure-II of the AD Rules provide for an objective examination of both, (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices, in the domestic market, for the like products; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree.
- 47. As regards the impact of the dumped imports on the domestic industry Para (iv) of Annexure-II of the AD Rules states as follows:

“The examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the Industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of margin of dumping actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.”
- 48. The injury analysis made by the Authority hereunder ipso facto addresses the various submissions made by the interested parties.

Volume Effect of the Dumped imports on the Domestic Industrya) **Demand and market share**

49. Demand or apparent consumption of the product in India has been taken as the sum of domestic sales of the Indian Producers and imports from all sources. The demand so assessed is given in the table below:

i. **Demand**

| Year | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | POI | Annualized POI |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------------|
| Imports from subject country (KG) | 1262809 | 2074747 | 2245835 | 2216838 | 1773470 |
| Imports from other countries (KG) | 9003 | 126776 | 104152 | 19202 | 15362 |
| Total Imports (KG) | 1271812 | 2201523 | 2349987 | 2236040 | 1788832 |
| % share of subject country in Imports | 99.3% | 94.24% | 95.57% | 99.14% | 99.14% |
| Trend country | 100 | 164 | 178 | 176 | 140 |
| Sales of Domestic Industry | 5678324 | 6750702 | 6748971 | 8891243 | 7112994 |
| Sale of other producers | 5134166 | 5437185 | 5653499 | 6573311 | 5258649 |
| Total demand (KG) | 12084302 | 14389410 | 14752457 | 17700594 | 14160475 |

50. It is noted that the demand in the country has increased in the POI as compared to the base year. While there is a decline in the annualized values as compared to the preceding years, the decline is marginal and the general level of demand remained more or less in the same band.

ii. **Market Share in Demand**

51. The Authority has considered all imports and sales of the Indian Producers to analyze the market share of subject imports in relation to the total demand in India. The position is as follows:

| Particulars | Unit | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | POI |
|--------------------------|------|---------|---------|---------|-------|
| China | % | 10.45 | 14.42 | 15.22 | 12.52 |
| Other Countries | % | 0.07 | 0.88 | 0.71 | 0.11 |
| Domestic Industry | % | 46.99 | 46.91 | 45.75 | 50.23 |
| Other Domestic Producers | % | 42.49 | 37.79 | 38.32 | 37.14 |

52. It is seen from the above table that the market share from China has increased as compared to the base year while there is a marginal decline as compared to the immediately preceding year. However, it is noted that the market share is still significant enough to cause injury to the Domestic Industry considering the fact that the subject goods are offered in the Indian market at dumped prices.

iii. **Import volume and market share**

53. The Authority has examined the volume of imports of the subject goods on the import data received from the DGCI&S. Details of the import volumes of the subject goods from the subject country and its share in the total imports of the subject goods are provided in the table below:-

| Particulars | | Unit | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | POI | Annualized POI |
|-------------------------|-----------------|------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| Volume | China | KG | 1262809 | 2074747 | 2245835 | 2216838 | 1773470 |
| | Other country | KG | 9003 | 126776 | 104152 | 19202 | 15362 |
| | Total imports | KG | 1271812 | 2201523 | 2349987 | 2236040 | 1788832 |
| Market Share in Imports | Subject Country | % | 99.3 | 94.24 | 95.57 | 99.14 | 99.14 |
| | Other country | % | 0.71 | 5.76 | 4.43 | 0.86 | 0.86 |

54. It is seen from the above table that imports from subject country increased from 1262809 KG in the base year to 1773470 KG during the POI (Annualized). It is also noted that imports from subject country account for 99.14% of the total imports of product under consideration in India during the POI. The Authority also notes that there is a marginal decline in the share of imports in the POI as compared to the base year. The overall impact of the volumes has also to be examined in the context of the prices at which imports are coming from China.

iv. **Share of imports in relation to production**

55. Authority observes that the imports from subject country have increased in relation to the production of the domestic industry during the POI as compared to the base year, though there is a decline during the POI as compared to the immediately preceding years. It is evident from the following table:

| Particulars | Unit | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | POI | Annualized POI |
|--|------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| Imports from China | KG | 1262809 | 2074747 | 2245835 | 2216838 | 1773470 |
| Production of domestic industry | KG | 5678324 | 6750702 | 6748971 | 8891243 | 7112994 |
| Dumped Imports in relation to production of domestic industry. | % | 22.2 | 30.7 | 33.3 | 24.9 | 24.9 |

v. **Capacity & capacity utilization**

56. It is noted that capacity utilization of the domestic industry increased during the POI as compared to the base year. The increase in the capacity utilization of the domestic industry is on account of the increase in the demand and the fact that there was an anti-dumping duty on raw silk until January 5, 2014.

| Particulars | Unit | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | POI | Annualized POI |
|----------------------|------|---------|---------|---------|----------|----------------|
| Capacity KG | KG | 9893000 | 9893000 | 9893000 | 12366250 | 9893000 |
| Production | KG | 5678324 | 6750702 | 6748971 | 8891243 | 7112994 |
| Capacity utilization | % | 57.40 | 68.24 | 68.22 | 71.90 | 71.90 |

Production

57. It is noted that production of the domestic industry has increased during POI as compared to the base year as well as the preceding years in view of the increase in demand and the fact that there was an anti-dumping duty on raw silk until January 5, 2014, as is seen for other parameters as well.

| Particulars | Unit | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | POI | Annualized POI |
|-------------|---------|---------|---------|----------|---------|-------------------|
| Production | KG | 5678324 | 6750702 | 6748971 | 8891243 | 7112994 |
| Trend | Indexed | 100 | 119 | 119 | 157 | 125 |
| Demand | KG | 1208430 | 1438941 | 14752457 | 1770059 | 14160475 |
| Trend | Indexed | 100 | 119 | 122 | 146 | 117 |

vi. **Sales volume**

58. It is observed that sales of the domestic industry have increased during POI as compared with the base year as well as the immediately preceding years on account of the increase in the demand:

| Particulars | Unit | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | POI | Annualized POI |
|---|---------|----------|----------|----------|----------|-------------------|
| Domestic Industry sales | KG | 5678324 | 6750702 | 6748971 | 8891243 | 7112994 |
| Trend | Indexed | 100 | 119 | 119 | - | 125 |
| Demand | KG | 12084302 | 14389410 | 14752457 | 17700594 | 14160475 |
| Trend | Indexed | 100 | 119 | 122 | - | 117 |
| Market Share of domestic industry in Demand | % | 46.99 | 46.91 | 45.75 | - | 50.23 |

Price Effect of the Dumped imports on the Domestic Industry

59. With regard to the effect of the dumped imports on prices, the Designated Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the purpose of this analysis, the average cost of production (COP), average Net Sales Realization (NSR) and the Non-Injurious Price (NIP) of the domestic industry have been compared with the landed cost of imports from the subject country.

i. **Price Undercutting**

60. The net sales realization was arrived after deducting post factory expenses i.e., outward freight and taxes. Landed value of imports has been calculated by adding 1% handling charge and applicable basic customs duty including applicable cess to the CIF value of subject imports. The landed value of imports was compared with net sales realization of the domestic industry and it was found that the dumped imports are undercutting the prices of the domestic industry as can be seen from the table below:

| Particulars | Unit | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | POI |
|-------------------------|-------|---------|----------|---------|------|
| Landed price of imports | Rs/KG | 2336 | 2365 | 2688 | 3281 |
| Net selling price of DI | Rs/KG | *** | *** | *** | *** |
| Price undercutting | Rs/KG | *** | *** | *** | *** |
| Price undercutting | % | *** | *** | *** | *** |
| Price undercutting | Range | 5-15 | (5)-(10) | 5-10 | 5-10 |

61. It is observed from the above table that the price undercutting is positive. The overwhelming market share of the subject country is bound to put price pressure on the Domestic Industry which compels the domestic producers to match their prices with the landed values of the imports from the subject country. The price pressure is adequately reflected in the financial performance of the Domestic Industry.

ii. **Price Underselling**

62. Authority notes that the price underselling is an important indicator of assessment of injury. Non injurious price has been worked out and compared with the landed value of the subject goods to arrive at the extent of price underselling. The non- injurious price has been determined considering the cost of production of the domestic industry for the product under consideration during the POI, in accordance with Annexure III of the Anti-dumping Rules to the extent applicable. The analysis shows that the landed value of subject imports was below the non-injurious price as can be seen from the table below.

| Particulars | China (Rs/KG) | China (\$/KG) |
|----------------------------|---------------|---------------|
| NIP | *** | *** |
| Landed price of imports | 3281 | 53.90 |
| Price underselling | *** | *** |
| Price underselling (%) | *** | *** |
| Price underselling (Range) | 0-10 | 0-10 |

iii. **Price suppression/depression**

63. The Authority examined whether the effect of the dumped imports was to depress the prices of the like article in India, or prevent price increase that would have otherwise occurred.

| Particulars | Unit | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | POI |
|---------------|--------|---------|---------|---------|------|
| Cost of Sales | Rs./KG | *** | *** | *** | *** |
| Indexed | Trend | 100 | 85 | 110 | 136 |
| Selling Price | Rs./KG | *** | *** | *** | *** |
| Indexed | Trend | 100 | 85 | 112 | 134 |
| Landed Value | Rs./KG | 2336 | 2365 | 2688 | 3281 |
| Indexed | Trend | 100 | 101 | 115 | 140 |

64. It is seen from the table above that the index of cost of sales has increased from 100 to 136 from base year to POI. The selling price increased only from 100 to 134 during the same period indicating that the prices were suppressed on account of dumped imports as the domestic industry was not able to increase its prices commensurate to the increase in costs.

H. Economic parameters of the domestic industryi. **Profit/Loss**

65. It is seen that profitability of the domestic industry declined significantly during the POI as compared to the base year. Cash profits as well as return on investment have also followed the same trend.

| Particulars | Unit | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | POI |
|-------------|--------|---------|---------|---------|-------|
| Profits | Rs./KG | *** | *** | *** | *** |
| Indexed | Trend | (100) | (87) | (30) | (209) |
| Cash Profit | Rs./KG | *** | *** | *** | *** |
| Indexed | Trend | (100) | (71) | 49 | (334) |
| ROCE | % | *** | *** | *** | *** |
| Indexed | Trend | (100) | (104) | (38) | (281) |

ii. **Cash Flow**

66. Authority has examined the trends in cash profits in order to examine the impact of dumping on cash flow situation of the domestic industry. It is seen that the cash profits of the domestic industry has declined significantly during the POI as compared to the base year. Information regarding cash profit of the domestic industry is given in the following table.

| Particulars | Unit | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | POI |
|--------------|--------|---------|---------|---------|-------|
| Cash profits | Rs./KG | *** | *** | *** | *** |
| Indexed | Trend | (100) | (71) | 49 | (334) |

iii. **Inventories**

67. Considering the nature of the domestic industry in the present case, the details relating to the inventories are not available and the analysis for this factor cannot be made.

iv. **Productivity**

68. The Authority notes that this factor in the present case cannot be analyzed as the exact number of employees deployed is not accurately ascertainable. Being more or less a family enterprise, the actual number of workers is not maintained. However, there is reason to believe that the productivity per employee/worker would have increased particularly when the production has gone up and the number of workers per basin has remained the same.

v. **Employment and Wages**

69. In view of the peculiar nature of the domestic industry where the producing units are mainly run by individual families and all the family members are engaged in the production process, the exact number of employees as well as wages paid to them is not determinable. However, it is important to note that the workers employed in this business are not even getting the minimum wages prevalent in the respective states. This is a matter of serious concern as the inability to earn even the minimum wages is clearly a significant indicator of material injury.

vi. **Magnitude of Dumping**

70. Magnitude of dumping as an indicator of the extent to which the dumped imports can cause injury to the domestic industry shows that the dumping margin determined against the subject country are above *de minimis* and significant.

vii. **Growth**

71. The Authority notes from the table below that the growth of the domestic industry in respect of profitability, cash flow and ROCE was negative particularly in the POI as compared to the base year. The domestic industry was prohibited from taking benefits of the increasing demand in the form of increase in profitability on account of low value dumped imports from the subject country.

| Particulars | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | POI |
|----------------------------|---------|---------|---------|-------|
| Profitability per unit (%) | 0 | 13 | 70 | (109) |
| Cash Flow per unit (%) | 0 | 29 | 149 | (234) |
| ROCE (%) | 0 | nil | 62 | (181) |

viii. **Ability to Raise Capital Investment**

72. The Authority notes that the domestic industry's ability to put in additional investments in the product depends upon the market situation. It is evident that the profitability of the domestic industry has declined during the POI as compared to the base year on account of low value dumped imports of the subject goods from China. Hence, dumping of the product would certainly have an adverse impact on the ability of the domestic industry to raise capital investment.

I. CONCLUSION ON MATERIAL INJURY

73. Based on the above, the Authority concludes that the dumped imports of the subject goods from the subject country have increased in absolute terms as well as in relation to production and consumption of the subject goods in India when compared to the base year. However, the significant cause of injury is on the price front where imports from China have been found to be undercutting the prices of the domestic industry in the market. The fact that the landed value of the subject goods is much below the NIP clearly establishes the existence of price underselling. Further, while the cost of production kept increasing over the injury period, the increase in selling price did not commensurate with the increase in the cost of production. The imports were thus suppressing the prices of the domestic industry and preventing the price increases that would have otherwise occurred in the absence of dumped imports. With regard to consequent impact of the dumped imports on the domestic industry, it is observed that while the demand for the product increased very significantly, the profitability of the domestic industry declined due to the low value dumped imports from the subject country.
74. The Authority notes that the domestic industry has suffered injury as a result of which the profitability of the domestic industry has declined. Return on capital employed and cash profits followed the same trend as that of profits. Both return on capital employed and cash profits marked negative growths in POI. Most importantly, the workers engaged in the production of the subject goods have not been able to earn the minimum wages. Thus, growth in respect of most of the parameters such as profits, cash profits & return on capital employed, wages, etc. show an adverse impact on the domestic industry. Thus, Authority concludes that the domestic industry has suffered material injury.

J. CAUSAL LINK AND OTHER FACTORS

75. Having examined the existence of material injury, volume and price effects of the dumped imports on the prices of the domestic industry, in terms of its price underselling and price suppression, and depression effects, other indicative parameters listed under the Indian Rules and Agreement on Anti-Dumping have been examined to see whether any other factor, other than the dumped imports could have contributed to injury to the domestic industry. Accordingly, the following parameters have been examined:-

(a) Volume and prices of imports from third country

76. During POI, imports of the subject goods from countries other than China have been insignificant in volume. Therefore, the imports from other sources cannot be considered to have caused injury to the domestic industry.

(b) Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers

77. It is noted that there is a single market for the subject goods where dumped imports from the subject country compete directly with the subject goods supplied by the domestic industry. It is also noted that the imported subject goods and domestically produced goods are like articles and are used for similar applications/end uses. There is no evidence of trade restrictive practices of and competition between the foreign producers and domestic producers causing injury to the domestic industry.

(c) Contraction of demand or Changes in the pattern of consumption

78. The Authority notes that demand for the product showed significant increase during the entire injury investigation period even though the demand in the POI declined marginally as compared to the immediately preceding years. The Authority thus concludes that injury to the domestic industry was not due to contraction in demand.

(d) Development in Technology

79. None of the interested parties has furnished any evidence to demonstrate significant changes in technology that could have caused injury to the domestic industry.

(e) Export performance of Domestic Industry

80. Domestic industry is not involved in the export sales during the entire injury investigation period. Therefore, Authority concludes that injury to the domestic industry was not due to export performance of the domestic industry.

(f) Productivity of the Domestic Industry

81. The Authority notes that the production of the domestic industry over the injury investigation period has increased except marginal decline during the year 2012-13 as compared to 2011-12. Considering the fact that the workers per basin have remained constant, there is reason to believe that the productivity has in fact increased.
82. From the foregoing, the Authority concludes that there is no evidence of injury being caused due to factors other than dumping.

K. FACTORS ESTABLISHING CAUSAL LINK

83. Analysis of the performance of the domestic industry over the injury period shows that the performance of the domestic industry has materially deteriorated over the injury period on account of low value dumped imports from the subject country. The causal link between dumped imports and the injury to the domestic industry is established on the following grounds:
- Imports from subject country are undercutting the prices of the domestic industry. Resultantly, the profitability has declined while the other financial parameters have been adversely affected significantly during the POI;
 - There is significant price underselling indicating that the Domestic Industry has not been able to get due returns on their investments and labour.
 - The existence of dumped prices is preventing the domestic industry from increasing its prices commensurate with the increase in costs causing price suppression which has resulted in decline in the profitability of the domestic industry during the POI as compared to the base year.
 - Deterioration in profits, return on capital employed and cash profits and inability to earn even the minimum wages are directly a result of dumped imports;
 - The growth of the domestic industry became negative in terms of price related economic as well as volume parameters.
84. The above grounds clearly establish existence of causal link between the dumped imports and injury to the domestic industry. Thus, the Authority concludes that the domestic industry suffered material injury due to low value dumped imports of the subject goods originating in or exported from the subject country.

L. MAGNITUDE OF INJURY AND INJURY MARGIN

85. The Authority has determined non-injurious price for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules, as amended. The non-injurious price so determined has been compared with the landed prices of imports from the subject country. Injury margin for all producers and exporters from China PR has been determined by the Authority on the basis of best available facts, which is as below:

| Particulars | Non Injurious Price - US\$/KG | Landed price – US\$/ KG | Injury Margin - US\$/ KG | Injury Margin % | Injury Margin Range - % |
|---|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------|
| All producers and Exporters from China PR | *** | 53.90 | *** | *** | 0-10 |

86. Post disclosure Statements/Submissions**Submissions by Domestic Industry**

87. The domestic industry had offered their detailed comments/submissions/rebuttals in their earlier communications filed with the Authority at various stages of the investigation. There are no new submissions and same are not being repeated herein for the sake of brevity and to avoid repetitions. In brief, following are the key comments:
- The submissions filed by CCCT should not be accepted, as CCCT has not disclosed by way of any communication that they are a business association and their majority of the members are producers, exporters or importers of product under consideration. Therefore, they cannot be considered as an interested party in terms of Rule 2(c) of the Rules. Further, they had filed their submission much beyond the last date and without giving sufficient cause for the delay. Also, the written submissions filed by CCCT are not signed by any authorized signatory to be treated as legally acceptable document in the present proceedings. For this additional reason, we request the Authority not to take the submissions advanced by CCCT on record.
 - All India Silk Weaver's Federation has not filed the comment on the domestic industry's application within the timeline prescribed by the Authority. In view thereof, the Authority is requested not to accept the submissions filed by All India Silk Weaver's Federation.
 - Sino Imports & Exports Pvt Ltd has filed their written submissions after the prescribed timeline. In view thereof, the Authority is requested not to accept the belated written submissions.

Submissions made by producers/exporters/importers/other interested parties

88. China Chamber of Commerce for Import and Export of Textile, Weavers' Associations who are the users of the imported material and M/s. Sino Import & Exports Pvt. Ltd, the importer have made submissions on disclosure statement. There is no additional point. The brief of the submissions is as below:

- a. The Designated Authority has relied upon DGCI&S transaction-wise import data for analysis in the present investigation. Respondent submits that the product scope covers only "Mulberry Raw Silk (not thrown) of 3A grade and below". Therefore, all transactions where grades above 3A are also mentioned should be excluded from PUC as these transactions do not constitute PUC. Further, all transactions where "Not Thrown" is not mentioned in the item description should also be excluded from PUC. Only transactions where grade 3A or below are mentioned should be made part of PUC.
- b. Respondent submits that imports of 3A grade from China PR are not affecting the domestic industry. Imports are primarily supplementing the demand in Indian market which could not be met by the domestic industry, which is already operating at optimal capacity utilization. The power loom industry has to import bivoltine category from China PR mainly due to the non-availability of bivoltine category of raw silk with the Indian domestic producers. Respondent requests the Designated Authority to separate different grades for apple-to-apple comparison for not only grades 2A and 3A, but also for sub-grades – bivoltine and multivoltine under grades 2A and 3A, respectively and thereafter make dumping and injury determination accordingly during the investigation process.
- c. The Respondent as well as other interested parties have maintained throughout the investigation that the domestic industry cannot supply 3A grade in adequate quantities, therefore 3A grade should be excluded from the product scope.
- d. As the domestic industry is highly fragmented and scattered, comprising of thousands of tiny units which are family run, it is not understood as to how the industry's data was validated during the verification visit and what kind of records were examined and verified.
- e. As per Rule 11(2), the Designated Authority is mandated to determine injury, threat of injury, material retardation to establishment of domestic industry and a causal link between dumped imports and injury for the domestic producers of such articles. Without identifying and collecting injury information from the domestic producers concerned, such an exercise would not be possible. The Designated Authority is mandated to identify the domestic producers and determine injury to such producers based on their injury information at enterprise level only.
- f. The domestic industry's contention that Respondent should not be treated as an interested party is incorrect. Respondent is an interested party in terms of Article 6.11 of the WTO Anti-dumping Agreement read with Rule 2(c) of the AD Rules, and even the Designated Authority has rightly considered Respondent as an interested party in this case.
- g. The imposition of Anti-dumping duty on the imports of raw silk yarn from China will badly affect the silk weaving industry all over the country. More than 20 million weavers working in looms will lose their jobs because of closure of units.
- h. In paragraph 35(iv) of Disclosure Statement, the Designated Authority observes that the domestic industry has made significant investments in new automated machines. However, Respondent submits that it is not clear which domestic producers have made such investments, as no names have been disclosed in the disclosure statement. Further, it is not clear whether such investments were made prior to the POI or after the POI. If such investments have been made post POI, such investments are irrelevant for the purpose of this investigation.
- i. In paragraph 50 of the disclosure statement, the Designated Authority observes that demand for the subject goods has increased in the POI as compared to the base year 2010-11. Respondent respectfully disagrees with the above observation and submits that demand for the subject goods has in fact declined on year-on-year basis. Total demand was 12,084,302 kgs in 2010-11, which rose to 14,389,410 kgs in 2011-12. Total demand further increased to 14,752,457 kgs during 2012-13 but sharply declined to 14,160,475 kgs during the POI (Annualised). Therefore, demand for the subject goods has actually declined during the POI (Annualised) in comparison to previous two years. The Designated Authority is requested to modify its observation in paragraph 50 in light of the above contention.
- j. In Annexure IV of the disclosure statement, the Designated Authority observes that producers of mulberry raw silk in India are in no position to maintain or keep formal accounts and follow the accounting procedures as followed in the organized sector nor do they have the resources to maintain such records. The Designated Authority further observes that vide its Final Findings No. 14/28/2002-DGAD dated 3 July 2003, the Designated Authority had recommended imposition of anti-dumping

duty in similar circumstances. Respondent submits that at the time when the aforesaid final findings were issued, there were no codified rules for determination of non-injurious price. However, now mandatory codified rules on determination of non-injurious price are given in Annexure III of the AD Rules. Principles under Annexure III of the AD Rules have to be followed in all cases without any exception. Therefore, reliance on the aforesaid final findings is incorrect in this case. In light of the above contentions, the Designated Authority is urged to modify its observations in Annexure IV of the disclosure statement.

Examination by the Authority

89. The various issues raised by the exporter and contested by DI have been addressed in above paragraphs but are being again addressed herein for the sake of clarity:

- i. CCCT has submitted that it is in fact the largest textile and apparel trade association both in China PR and the world. They have several functional departments and branches that deal, inter alia, with textiles, silk, garments, etc. In the light of the above submissions, CCCT is qualified to be an interested party under Rule 2(c) of the AD Rules. Further, it has submitted that it is registered as an interested party with the Designated Authority with minor delay. The Designated Authority has recognized them as interested party and decided to accept and examine the submissions made by all the interested parties.
- ii. With regard to the request of the interest parties to exclude all import transactions which mentions the word "Grades above 3A" and/or does not mention the word "Not Thrown", the Authority notes that the price of the Mulberry Raw Silk of grade above 3A and/or of thrown variety is higher than the prices of Mulberry Raw Silk (Not Thrown) of grade 3A and below, because of the additional cost involved. However, from the DGCIS import data it has been noted that in number of transactions the import prices of Mulberry Raw Silk of grade above 3A and/or of thrown variety from China PR is significantly lower than the import prices of Mulberry Raw Silk (Not Thrown) of grade 3A and below. Therefore, the Authority has excluded only those transactions from the product scope where the description specifically mentions grade above 3A and/or thrown and the import price of these transactions are higher than the import prices of Mulberry Raw Silk (Not Thrown) of grade 3A and below.
- iii. With regard to the issue raised by the interested parties that if the duties are levied, then all the 6 to 8 lakh power loom weavers will have to face starvation and death, the Authority holds that the imposition of anti-dumping does not, in any case, affect the availability of the product to the consumers. The objective of the anti-dumping duties is to create a level playing field for the domestic industry to compete more effectively in the market by eliminating injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping in the general interest of the country. Further, the application of the lesser duty rule ensures that the Domestic Industry gets the protection that is sufficient to remove the injury.
- iv. The interested parties have raised an issue that power loom industry has to import bivoltine category from China PR mainly due to the non-availability of bivoltine category of raw silk with the Indian domestic producers. The Authority notes that it was noticed during the verification that the domestic producers are indeed manufacturing silk of various grades including 2A, 3A both bivoltine and multivoltine varieties. Further, though not relevant to this investigation, it is also noted that significant investments have also been made in the new automated machines which will augment supply of Mulberry Raw silk of various grades including 2A, 3A in sufficient quantities.
- v. As regards the issue raised by the interested parties of the application of Annexure III to determine the NIP and the basis on which certain costs were adopted, the Authority notes that the provisions of Annexure III cannot be read in a manner so as to negate the powers of the Authority to use the best available information. It is well recognized that the nature of the domestic industry in this investigation is very peculiar and distinct from the typical organized Domestic Industry. The domestic industry is highly fragmented and scattered, comprising of hundreds of tiny units. These units are cottage based industry and are run predominantly by individual families. While recognizing that there is no specific requirement in law to compute the NIP only on the basis of enterprise-specific information, the Authority has nevertheless validated the accuracy of the information provided by the domestic industry in their application during the verification visit of the constituent units. It is this validated information that has formed the basis for the calculation of the NIP.
- vi. With regard to the request of the interested parties to calculate the grade wise dumping and injury margin, it is noted that the exporters from the subject country have not filed the questionnaire response and have not given material information necessarily required for the calculation of the dumping margin. In the absence of the relevant information, it is not possible to determine grade wise dumping and injury margin.

- vii. With regard to the submission of the opposite interested parties that the applicant should make available information of the individual producers, the Authority notes that in the present case domestic industry is highly fragmented and scattered, comprising of thousands of tiny units. These units are cottage based industry and are run predominantly by individual families. Accordingly, these units are in no position to maintain or keep the books of accounts as is followed by the units in the organized sector nor do they have the resources to maintain such records. During the verification visit of the constituents of domestic industry, the Authority verified the records maintained by the cocoon exchange as well as the reelers and validated the data submitted by the domestic industry.
- viii. As regards to the issue raised by the interested parties that Designated Authority is mandated to determine the injury considering the injury information at the enterprise level, the Authority holds that there is nothing in the scheme of the Act and the Rules which mandates that the information regarding injury, etc. has to be at the enterprise level. The rules specifically provide for examination of the "state of the industry". In this context, the Authority also refers to its Final Findings F. No. 15/24/2010-DGAD dated 05th December, 2011 in case of "Silk Fabrics 20-100 gms per meter originating in or exported from China PR" wherein a clear view had been taken that "there is no specific law which prescribes the acceptance of aggregated information for the industry as such. Thus, there is no bar in accepting information provided by the Central Silk Board for the purpose of any aspect of this investigation. Therefore, the Authority finds no reason to discard the data or information provided by the CSB".
- ix. With regard to the issue raised by the interested parties that imposition of anti-dumping duties will badly affect the silk weaving industry all over the country, the Authority states that imposition of anti-dumping will not affect the availability of the product to the consumers. The objective of the anti-dumping duties is to create a level playing field for the domestic industry to compete more effectively in the market by eliminating injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping in the general interest of the country. Further, the application of the lesser duty rule ensures that the Domestic Industry gets the protection that is sufficient to remove the injury.
- x. Interested parties have raised the issue regarding the period in which such investment has been made. Further, the interested parties have raised the issue regarding the disclosure of the names of the domestic producers who have made significant investment. The Authority notes that several reelers have made investments in the automated machines. These investments have been made in both POI as well as Post POI. The Authority has only visited some of these units considering the nature of the industry which is highly fragmented and scattered.
- xi. As regards the request of the interested parties to modify the observation made in paragraph 50 of the disclosure statement considering the fact that the demand for the subject goods has actually declined during the POI (Annualized) in comparison to two previous years, the Authority notes that the examination done in Para 50 regarding the demand of the subject goods in India is in line with the facts of the case. It is noted that the demand in the country has increased in the POI as compared to the base year. While there is a decline in the annualized values of demand in the POI as compared to the preceding years, the decline is marginal and the general level of demand remained more or less in the same band.
- xii. The request of the interested parties to modify Annexure IV of the disclosure statement was noted by the Authority. It is clarified that it is a fact that the rules for determination of non-injurious price have been codified vide Annexure III on 1st March 2011 and the Authority is required to determine the fair selling price or non-injurious price of the like domestic product taking into account the principles specified in this Annexure. These rules are based on set principles of costing which prevailed even before the notification. Therefore, making a reference of the previous findings on such principles does not mean that the rules specified in Annexure III have not been followed by the Authority while determining the non-injurious price in the present case. The contention of the interested parties that the guidelines of Annexure III have to be necessary followed, the Authority observes that the guidelines contained in the said Annexure have to be read harmoniously along with the other provisions of the Act and the Rules. The fact that information is not available at the enterprise level to enable the Authority to apply all the guidelines and principles contained in Annexure III, does not dilute the power of the Authority to use the best information available in the facts and circumstances of any case.
- xiii. As detailed in Annexure IV of the disclosure statement, non-injurious price of the product has been determined in accordance with the principles laid down in Annexure III. Material cost which accounts for above 80% of the total cost of production has been taken at the best utilization norms. The propriety of all expenses charged to the cost of production has been reviewed and ensured that only reasonable amount is charged to the cost of production. No expenses specified in Para 4(vii) of the Annexure III

have been included in the cost of production. A reasonable return on average capital employed for the product has been allowed in accordance with the principles laid down in the said Annexure.

CONCLUSION

90. The Authority has, after considering the foregoing, come to the conclusion that:

- a. The subject goods have been exported to India from the subject country below its normal value;
- b. The domestic industry has suffered material injury;
- c. The material injury has been caused by the dumped imports of the subject goods from subject country.

INDIAN INDUSTRY'S INTEREST AND OTHER ISSUES

91. The Authority recognizes that imposition of antidumping duties might affect the price level of product in India. However, fair competition in Indian market will not be reduced by the anti-dumping measures. On the contrary, imposition of anti-dumping measures would remove the unfair advantage gained by dumping practices, would arrest the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods. Consumers could still maintain two or more sources of supply.
92. The Authority notes that the purpose of antidumping duties, in general, is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures would not restrict imports from the subject country in any way, and therefore, would not affect the availability of the products to the consumers.

RECOMMENDATIONS

93. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the exporters, importers and other interested parties to provide positive information on the aspects of dumping, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and the causal link thereof in terms of the AD Rules and having established positive dumping margins as well as material injury to the domestic industry caused by such dumped imports, the Authority is of the view that imposition of antidumping duty is required to offset dumping and injury. Therefore, the Authority considers it necessary to recommend imposition of definitive anti-dumping duty on imports of subject goods from the subject country in the form and manner described hereunder.
94. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of definitive anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, the antidumping duty equal to the amount indicated in Col No.9 of the table below is recommended to be imposed on all imports of the subject goods originating in or exported from the subject country.

| Duty Table | | | | | | | | | |
|------------|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|-----------------|---------------------|
| Sl. No. | *Tariff Items | Description of Goods | Specification | Country of Origin | Country of Export | Producer | Exporter | Amount (in USD) | Unit of Measurement |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1. | 50020010 | Mulberry Raw Silk (not thrown) of 3A grade and below | Any specification | China PR | China PR | Any | Any | 1.85 | KG |
| 2 | 50020010 | Mulberry Raw Silk (not thrown) of 3A grade and below | Any specification | China PR | Any | Any | Any | 1.85 | KG |
| 3 | 50020010 | Mulberry Raw Silk (not thrown) of 3A grade and below | Any specification | Any | China PR | Any | Any | 1.85 | KG |

95. Landed value of imports for the purpose of this Notification shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the said Act.
96. An appeal against the order of the Central Government arising out of this final finding shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

A. K. BHALLA, Designated Authority